# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६ ] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का १२वां दिवस [ संख्या १०



मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

———

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, उद्योग, योजना, सार्वजनिक निर्माण, समाजकल्याण, नागरिक रसद, देवस्थान व विकास-विभाग.]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, रावराजा श्री सरदारसिंह।

### हाई स्कूल, हायर सेकन्डरी एवं इन्टरमीजियेट परीक्षाओं के परिणाम

३४३. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में प्रति वर्ष हाई स्कूल, हायर सेकन्डरी एवं इन्टरमीजियेट परीक्षाओं के परिणाम संतोषजनक नहीं रहते हैं ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त परिणामों के सम्बन्ध में कोई पृथक जांच कमेटी बनाई है ?

(ग) अगर हां, तो क्या सरकार के समक्ष सम्बन्धित कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है ?

उपमंत्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ): (क) जितने अच्छे परिणाम चाहते हैं, उतने नहीं आ रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं, पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : One representative from the Ministry of Education.

# Page No.2



( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

Two representatives from Delhi Administration with experience of Higher Secondary Education.

Two representatives will be co-opted by the Committee.

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : कमेटी क्या कार्य करेगी, किस किस आधार पर कार्य करेगी ? सदस्य की क्या क्वालीफिकेशन्स होंगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उनकी क्वालीफिकेशन जो हायर सेकिन्डरी की पद्धति है उसको देखते हुए एजुकेशनलिस्ट होने चाहिये ।

**श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : यह कमेटी कब बनी और इस कमेटी के बनाने के क्या आधार हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने आपको जैसा बताया कि फेल्योर्स की संख्या बढ़ रही थी । इसलिए इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी का गठन हुआ । यह ४ सितम्बर, १६५६ को हुआ था ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या इसके लिये कोई शिकायत सुनी या विभागीय जांच कराई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह तो जाहिर था कि जो रिज़ल्ट्स थे वे असंतोष-प्रद थे ।

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसने इन्टेरिम रिपोर्ट दी है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : उसने क्या सिफारिश की है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसने कहा कि हायर सेकन्डरी को दो भागों में बांट दिया जावे । एक तो १० वीं कक्षा के बाद में परीक्षा होनी चाहिये और दूसरी ११ वीं एक सोशियल स्टडी, जनरल साइन्स, एलिमेंट्री मेथेमेटिक्स का १० वीं में एग्ज़ामिनेशन होना चाहिये और तीन, दूसरे विषयों का सिविक्स आदि का १० वीं के बाद होना चाहिये ।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या १० वी के एग्ज़ामिनेशन में और हायर सेकन्डरी के एग्ज़ामिनेशन में कोई डिफरेन्स रहेगा या नहीं रहेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## जिला जालोर के पसायतेदार

३४५. **श्री लक्ष्मीचन्द ( सांचोर )** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि जिला जालोर के जसवन्तपुरा, आहोर व जालोर तहसील में पसायतेदारान को मुख्य जागीर के साथ खालसा किया गया है और सांचोर तहसील में पसायतेदारान को अलग मान कर रिज़्यूम किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि जागीरों को खालसा करने के लिये इन्कम ग्रुप बनाये

# Page No.3



( श्री लक्ष्मीचन्द )

गये हैं तथा उनमें पसायतेदार की आमदनी शामिल की जाकर रिज्यूम किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) भूमि सुधार एवं जागीर पुन: ग्रहण अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत जो जागीरदारों से आमदनी का १।१६ हिस्सा सरकार द्वारा वसूल किया गया है क्या उसमें पसायतेदारान की आमदनी जागीरदारों की आमदनी में शामिल है या पसायतेदारान से १।१६ हिस्सा अलग वसूल किया जाता है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, जागीर खालसा करते समय जिन पसायतेदारों के बारे में यह साबित हुआ कि वे अलहदा तौर पर सब-ग्रांटीज़ हैं तो उनकी जागीरें उनके आय ग्रुप के अनुसार खालसा की गई हैं तथा जिन पसायतेदारों के लिये राजस्थान अभिलेख से यह साबित नहीं हुआ कि वे अलहदा सब-ग्रांटीज़ हैं तो वैसे पसायतेदार मुख्य जागीर के साथ खालसा की गई ।

(ख) जी हां । जिन पसायतेदारों के लिये साबित नहीं हुआ कि वे अलहदा जागीर के सब-ग्रांटी हैं तो मुख्य जागीर की शामिल आय पर इन्कम ग्रुप माना गया ।

(ग) जी हां । पैरा (ख) के अनुसार जो पसायतेदार मुख्य जागीर के साथ खालसा किये गये उनकी आय एसेसमेंट के लिये मुख्य जागीरदार की आय मान कर १।१६ हिस्सा मुख्य जागीरदार से वसूल किया गया। अत: पसायतेदार से अब अलहदा वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : जब आप उसको जागीरदार से सेपरेट मानते हैं तो फिर यह रकम जागीरदार से क्यों वसूल की जाती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं इसका जबाब अर्ज कर चुका हूं । जिनके रेकॉर्ड में नाम अलग हैं उनके साथ यह नहीं हुआ है ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : क्या यह सही है कि सांचोर में अलग पसायतेदार हैं लेकिन उनकी इन्कम जागीरदार से वसूल की जाती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं इसका जबाब दे चुका हूं ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : जो सेपरेट हैं और उनको सेपरेट कम्पेन्सेशन मिलता है तो फिर क्या मतलब है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आपको जबाब दिया कि जो सब-ग्रान्टो नहीं है उसके तहत में जागीर कमिश्नर के पास आप जा सकते है । यह जुडिशियल मामला है, यह एग्ज़िक्युशन का मामला नहीं है । और हमको भी किसी प्रकार की इसमें आपत्ति होती है तो हम जागीर कमिश्नर के पास जाते हैं और माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि वे इसकी कार्यवाही वहां पर करावें । जहां तक उसूलों और कानून का प्रश्न था मैंने अर्ज कर दिया ।

# Page No.4



**श्री लक्ष्मीचन्द** : क्या यह सही है कि पसायतेदारों को मुख्य जागीर के शामिल नहीं किया गया है और फिर भी १।१६ हिस्सा जागीरदारों से काटा जाता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : कलेक्शन का १।१६ का हिस्सा है उससे अलग क्यों नहीं माना ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया कि अगर रेवेन्यू रेकॉर्ड में अलग शुमार किया है तो उसके लिये पसायतेदार अलग हैं तो ठीक है और अगर मुख्य जागीरदार के साथ है तो मुख्य जागीर के साथ वह वसूल होगा। अब रहा कम्पेन्सेशन का सवाल कि किस तरह से हो, इसके लिये जिस तरह से जागीर कमिश्नर करते हैं....

**श्री लक्ष्मीचन्द** : जब आपने उनको अलग रेकॉर्ड में कर दिया तो मुख्य जागीरदार के साथ फिर उसको क्यों लिया जाता है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह तो वैधानिक स्थिति है। इसके बारे में आप जागीर कमिश्नर के पास जावें। वह जुडिशियल ऑथोरेटी है।

**श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि रेकॉर्ड में एन्ट्रीज़ गलत हुई हैं या सही, कोई कदम उठाया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाये हैं और अगर सरकार के नोटिस में कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर कदम उठाएगी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री मोगजी भाई।

## बांसवाड़े के लघु उद्योग

३४५. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उद्योग विभाग, बांसवाड़ा ने सन् ५८, ५६ व ६० में छोटा उद्योग खोलने के लिये कितनी कितनी रकम सहायता व कर्ज के रूप में किन किन कम्पनियों व सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को दी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त वर्षों में छोटे उद्योग खोलने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए व उनको प्राथमिकता किस तरह दी गई ?

**उद्योग मन्त्री** ( श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जाए।

**श्री मोगजी भाई** : कब तक दिया जावेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय की अगली टर्न पर।

( विराम )

श्री मुरलीधर व्यास।

## तहसील भीलवाड़ा की भूमि का आवंटन

३४६. **श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर-

# Page No.5



( श्री मुरलीधर व्यास )

सिटी ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील भीलवाड़ा में नहरी और गैर नहरी जमीन १५ अगस्त, १९५७ से १५ अगस्त, १९५९ तक कितने बीघा अलॉट की गई ? यह अलॉटमेंट स्थाई है या अस्थाई ?

(ख) उक्त अलॉटमेंट भूमिहीन जमींदार, गैर किसान ( व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्त्ता ) किन किन को हुआ है ?

(ग) क्या अलॉटमेंट किसी कमेटी की राय से सर्व सम्मति, बहुमत की राय या अल्प मत की राय से होता है ? यदि ऐसा है, तो ऐसी कितनी बीघा भूमि है जो उक्त विभिन्न रीतियों से हुई ? क्या कोई अलॉटमेंट बिना समिति की राय से भी हुआ है ?

(घ) क्या जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है, उनके पास पहले भूमि थी ?

**राजस्व मन्त्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : (क) नहरी १९६६।)३ बीघा अस्थाई, गैर नहरी स्थाई ३९५८)४ बीघा अस्थाई १००३।।) बीघा।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) समस्त अलॉटमेंट कमेटी के बहुमत से किया गया है।

(घ) जी नहीं, कुछ के पास १५) बीघा ( बारानी ) से कम थी जिसकी पूर्ति की गई थी।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिए )

**श्री मुरलीधर व्यास** : अलॉटमेंट किया गया, सूची सदन की मेज पर रखी गई। उसमें भूमिहीन के अन्तर्गत व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्त्ता और काश्तकारों को भी भूमि अलॉट की गई थी। यह कहा जाता है कि भूमिहीन को ही अलॉटमेंट के लिए प्राथमिकता दी जाती है तो क्या सब को ही अलॉटमेंट किया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भूमिहीनों को ही अलॉट की जाती है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : फिर व्यापारी, राजनैतिक कार्यकर्त्ता, सरकारी कर्मचारी, और जमीदार हैं उनको क्यों किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं तो वह भी भूमिहीन हो सकता है, जिसके पास फ्रेगमेन्ट्स हैं वह भी भूमिहीन हो सकता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो धन्धा करते हैं, व्यापार करते हैं, कभी भी भूमि जिसने जोती नहीं है उसको अलॉटमेंट कर दिया जायेगा तो फिर भूमिहीन को कैसे होगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : किसके लिए फरमा रहे हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने कहा कि राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सब को भूमि दी जाती है।

# Page No.6



**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने जो अर्ज किया उसका ध्यान रखियेगा। आपने कहा राजनैतिक कार्यकर्त्ता, तो राजनैतिक कार्यकर्त्ता भूमिहीन में आ सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जैसे अन्य गैर काश्तकार हैं, इसके साथ साथ व्यापारी हैं—व्यापार करते हैं, शहरों में रहते हैं, भूमिहीन की दर्खास्त को ही प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास जमीन नहीं है, तो फिर उनको क्यों दी गई और भूमिहीनों को क्यों नहीं दी गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ऐसा नहीं है। भूमिहीन को ही भूमि अलॉट की गई है। इसके विपरीत कोई केस है और उसके लिए पूछें तो मैं बता सकता हूं। यदि आप जनरल पूछते हैं तो ऐसा नहीं किया गया, मैं यही कह सकता हूं। यदि कोई ऐसा केस है तो उसके लिए आप नोटिस दीजिये, स्पेसिफिक केस को रेफर कीजिये। राजनैतिक कार्यकर्त्ता भूमिहीन हैं उनको मिली है। कोई आदमी व्यापार करता होगा उसको भूमि मिल गई होगी। कोई केस हो तो आप बतायें, मेरे ध्यान में नहीं है। यह भी हो सकता है कि व्यापार को छोड़ कर, भूमि नहीं होने से भूमि मिलने पर उसको छोड़ कर भूमि पर आबाद हो गये हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप जैसा फरमा रहे हैं, अलॉटमेंट भूमिहीनों को हो चुका है तो आपने जानकारी पहले ही कर ली होगी कि भूमिहीनों को ही भूमि दी गई होगी, अन्य को नहीं, या तो आप ऐसा फरमाइये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पिछले तीन सालों में १,३०,००० भूमिहीनों को भूमि अलॉट की गई है। यह पोसिबिलिटी नहीं है कि मैं उनको हरएक को एग्ज़ामिन करूं। माननीय सदस्य पोइन्टेडली पूछें तो उसका जवाब देने में मुझे सहूलियत हो सकती है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं पोइन्टेडली पूछूं उसके पहले ही आप जांच करके जवाब दें। आप यह कहें कि प्राथमिकता उनको ही दी है और जांच करके कहते हैं और जांच करके दी है तो फिर मैं उनके नाम बताऊं।

**श्री अध्यक्ष** : जांच करके ही तो उत्तर दिया है, बगैर जांच करके थोड़े दिया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यदि जांच करके दिया जाता है तो यह कहा जाय कि प्राथमिकता भूमिहीनों को ही दी गई है ?

**श्री अध्यक्ष** : बगैर जांच के थोड़े ही दी गई। यदि अलॉटमेंट रूल्स का किसी तरह से उल्लंघन हुआ है और ऐसे लोग हों जिनको मिलना चाहिये उनको न मिले और दूसरों को मिल गई हो, ऐसा केस हो तो आप जानकारी दें।

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : यह तो जरूर मालूम करना चाहिये कि अलॉटमेंट किया गया था तो यह जरूर मालूम किया होगा कि इसके पास सिवाय भूमि तो नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भूमिहीन की डेफिनेशन वैल डिफाइन्ड थी। टिनेन्सी एक्ट में यह साफ दिया हुआ है : "whose main and sole means of

( श्री दामोदरलाल व्यास )

livelihood is agriculture . " उस डेफि-निशन को ध्यान में रख कर अलॉटमेंट कमेटी को जमीन अलॉट करनी पड़ती है। यदि किसी ने उसकी खिलाफवर्जी की है तो पोइन्टेडली बतायें कि अमुक व्यक्ति को दी है। आपने तो जनरल बात पूछी कि भीलवाड़ा तहसील में भूमिहीनों को भूमि अलॉट की गई; उसका जवाब दिया कि भूमिहीनों को अलॉट की गई।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैंने तो पोइन्टेडली ही पूछा था ....

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री दयाकृष्ण विजय।

## माध्यमिक शालाओं की अवकाश तालिका

३४७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या निरीक्षक, शिक्षा विभाग, कोटा द्वारा जिले की माध्यमिक शालाओं को छुट्टियों की कोई तालिका भेजी गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा भी माध्यमिक शालाओं के पास छुट्टियों की तालिका भेजी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(ग) क्या यह सही है कि इन दोनों तालिकाओं में काफी अन्तर है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त शालायें किस आदेश का पालन कर रही हैं ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) जी हां, शिक्षा निरीक्षक, कोटा द्वारा जिले की माध्यमिक व अन्य शालाओं को छुट्टियों की तालिका जो सरकार की आज्ञा संख्या एफ. १० (३) जी ए. ५६ दिनांक २१-११-५६ द्वारा स्वीकृत की गई, भेजी गई है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) शिक्षण संस्थाओं में होने वाली छुट्टियों की तालिका शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित स्कूल कलेन्डर में प्रकाशित की जाती है जिसमें जुलाई से जून तक की छुट्टियों का ब्यौरा रहता है। जुलाई, १९५९ से जून, ६० तक का स्कूल कलेन्डर तो पहले ही समस्त पाठशालाओं को भेजा जा चुका था और १९६०-६१ का कलेन्डर समस्त राजकीय शिक्षण शालाओं में वितरण के लिए सम्बन्धित उप शिक्षा अध्यक्षों को भेजे गये तथा प्राइवेट और सहायता प्राप्त संस्थाओं को शिक्षा विभाग के प्रधान कार्यालय से भेजे गये जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) इनमें काफी अन्तर तो नहीं है लेकिन निम्न दिवसों को पाठशालायें बन्द नहीं रहतीं बल्कि इन दिवसों पर शिक्षण कार्य न चलाया जाकर समस्त छात्रों को एकत्रित करके इन विशेष अवसरों का महत्व समझाया जाता है ताकि छात्रों को मालूम हो सके कि किस विशेष दिवस का क्या महत्व है। वे निम्नलिखित दिवस हैं : १ जन्माष्टमी, २. स्वतन्त्रता दिवस, ३. महात्मा

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

गांधी जन्म दिवस, ४. गुरु नानक जयन्ती, ५. बसन्त पंचमी, ६. बुद्ध पूर्णिमा, ७. महावीर जयन्ती, ८. रामनवमी, ९. बारावफात।

(घ) समस्त शालाओं में स्कूल कलेन्डर में दिये हुए आदेशों का पालन किया जा जा रहा है।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिए )

**श्री दयाकृष्ण विजय :** मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि एक तो आदेश है शिक्षा विभाग का २१-११-५९ का और दूसरा आदेश है एडीशनल डाइरेक्टर का १५-१२-५९ का। पहले वाला आदेश मान्य है या बाद में आया आदेश मान्य है, कौनसा आदेश मान्य है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** शिक्षा अध्यक्ष ने कहा है, वह मान्य होना चाहिये।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** तो क्या यह समझा जाय कि जो एडीशनल डाइरेक्टर ने सूची भेजी है वह गलत भेजी है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** भूल थी तो दुरुस्त कर दिया गया।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** भूल तो बाद में दुरुस्त होती है। शिक्षा विभाग ने आदेश भेजा वह नवम्बर का है और एडीशनल डाइरेक्टर ने भेजा है वह दिसम्बर का है। सूची भेजी है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इसके बारे में जिले के इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने गलती कर दी थी। उसमें यह था कि राज्य सरकार का आदेश है उसके अनुसार अपने आदेश जारी कर दिये। स्कूल की छुट्टियों के आदेश शिक्षा विभाग से जारी किया गया और उसके अनुसार ही कार्यक्रम चलना चाहिये।

**श्री दयाकृष्ण विजय :** अध्यापकों के अतिरिक्त जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको भी छुट्टियों के अवसर पर आना पड़ता है, इस तरह से वे सारी छुट्टियों से महरूम रह जाते हैं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** जो जलसा मनाया जाता है उनमें शामिल होते हैं और वे खुद सीखते हैं, यह उनके लाभ की चीज़ है।

**प्रश्न संख्या ३४८**

**श्री अध्यक्ष :** श्री वीराराम।

( अनुपस्थित )

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

**तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप**

**२४९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से समस्त पंचायतों एवं जिला परिषदों से उनकी अपनी योज-

# Page No.9



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

नाएं आमन्त्रित की हैं ? यदि हां, तो फिर नगरपालिका क्षेत्रों की दृष्टि से क्या सभी नगरपालिकाओं से भी इसी प्रकार सुझाव या योजनाएं आमन्त्रित की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) इन सभी योजनाओं अथवा सुझावों पर विचार कब तक हो जावेगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अन्तिम रूप से कब तक तैयार हो जावेगा ?

(ग) क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा राज्य सरकार द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा चुकी है ? यदि हां, तो फिर इन सुझावों व योजनाओं का क्या अर्थ होगा ?

**राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):**

(क) राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिये समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को उन योजनाओं के लिये जो कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण होने पर पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर दी गई हैं अपनी योजनायें बनाने के लिये आमन्त्रित किया है। नगरपालिकायें केवल उन्हीं योजनाओं के लिये आमन्त्रित की गई हैं जो कि उनके क्षेत्र में आती हैं और जिन्हें वे कार्यान्वित करती हैं।

(ख) इन योजनाओं पर विचार अक्टूबर, ६० तक हो जावेगा तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अन्तिम रूपसे नम्बर,१६६० तक तैयार होने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा का ढांचा योजना विभाग के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु राज्य योजना मंडल की एक उप समिति तथा विभिन्न मदों (Sectors) सम्बन्धी क्रियमाण ग्रुप (working groups) भी बनाये थे। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना उक्त तीनों आधारों तथा पंचायत समितियों के सुझावों एवं प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। योजना का अन्तिम रूप प्लानिंग कमीशन से बहस होने के बाद ही तैयार किया जा सकेगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्ध में जो प्लान एक्सपेन्डीचर होने वाला है उसके लिये डिटेल्ड सर्वे करके प्लान्स स्कीम्स नगरपालिका से मांगी हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अभी तो इनके 'इन्कोर्पोरेट' की स्टेज नहीं आई, लेकिन जहां तक नगरपालिका क्षेत्र से सम्बन्धित सुझावों का प्रश्न है वे नगरपालिका से मांगे गये हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी):** क्या जिला परिषद् और पंचायत समितियों को तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भेजा गया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जो कुछ भी एलोकेशन था उनको सब भेजा गया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर ने जाकर उनके उद्देश्य आदि समझाये हैं।

Page No.10



**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या यही प्रोसीजर नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी अपनाया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नगरपालिका क्षेत्र से सम्बन्धित, नगरपालिका से मांगा गया है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**सरोली–दूनी सड़क पर पुलों का निर्माण**

**३५०. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरोली, तहसील देवली से दूनी तक पुख्ता सड़क तैयार हो चुकी है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के बीच में नाले पड़ते हैं ? अगर हां, तो कितने और क्या उन पर पुल बनवाने की मन्जूरी हो चुकी है ? अगर हां, तो कब कितने बन चुके और कितने बाकी हैं ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : १. जी हां, जून १९६० में।

२. सही है; पांच। पुल बनवाने के लिये कोई धन–राशि स्वीकृत नहीं हुई है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जब नालों के लिये रकम मन्जूर नहीं हुई तो सड़क बनाने से क्या फायदा ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : अब तक स्वीकृति नहीं हुई है, आगे हो सकती है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : अगली बरसात से पहले हो जायगी या नहीं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जी हां।

**प्रश्न संख्या ३५१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

**उच्च माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम समिति**

**३५२. डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में जांच करने के लिये विशेषज्ञों की कोई समिति बनाई थी ? यदि हां, तो कब ? समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो कब ? रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ग) समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या नये सत्र से उच्च माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है ?

**उप मंत्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

बिश्नोई ) : (क) जी हां, सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति आज्ञा क्रमांक एफ २०।४ एज्यु. बी. ५९, दिनांक ४-९-५९ के द्वारा बनाई, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां, समिति ने अपनी इन्टेरिम रिपोर्ट दिनांक १८।५।६० को दे दी है । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी हां, सरकार ने जो सिफारिशें मान ली हैं और जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यथा संभव १९६०-६१ के वर्ष काल से ही लागू करने के लिये निवेदन कर दिया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

**श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : कमेटी ने सिफारिशें क्या की हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उन्होंने यह सिफारिश की है कि हायर सेकन्डरी एग्ज़ामिनेशन को दो भागों में बांट दिया गया है पहला एग्ज़ामिनेशन कुछ सब्जेक्ट्स के लिये है, उसके बाद ११ वीं के लिये ।

**डॉ० चन्द्रकला** : इस कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार इन कक्षाओं के लिये जो पाठ्य क्रम है वह बहुत बड़ा है ; जब यह सिफारिश मान ली गई है तो उसके अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : एक दिन में तो पाठ्यक्रम बदला नहीं जा सकता । बुक्स वगैरह का रिवीजन करना होगा । हमने लिखा दिया है, वे जल्दी से जल्दी इस रिकमन्डेशन को लागू करेंगे ।

**डॉ० चन्द्रकला** : पाठ्यक्रम जो भारी है उसको हल्का करने का सवाल है और इसी तरह की कमेटी की सिफारिश है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इसमें भी तो आखिर समय लगेगा, बोर्ड ऑफ सेकिन्डरी एज्युकेशन इस पर विचार करेगा; सिफारिशों के मुताबिक उसको चेन्ज करना होगा । आखिर थोड़ा समय तो लग सकता है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या सरकार यह महसूस करती है कि अगर इसी प्रकार का पाठ्यक्रम इस साल भी जारी रहा तो जो परिणाम गत साल आया कि बहुत छात्र अनुत्तीर्ण रहे, क्या इस साल भी उसी तरह का रिज़ल्ट नहीं रहेगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप ही कोई सुझाव दें । हम क्या कर सकते हैं, हम कैरीकुलम तो बनाते नहीं हैं ।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या सुझाव लेने का यही प्रसंग और अवसर समझते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

### धौलपुर-राजाखेड़ा सड़क

३५३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री मुरलीधर व्यास )

(क) धौलपुर से राजाखेड़ा जाने वाली सड़क कब बनाई गई थी ?

(ख) यह सड़क जिन जिन किसानों के खेतों में होकर गई है क्या उन्हें मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) वर्ष १९५३–५४ में।

(ख) जी नहीं। अभी कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : ५४ से अब तक कार्यवाही पूरी नहीं होने का कारण क्या है ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : जल्दी से जल्दी कार्यवाही पूरी करने की कोशिश की जायेगी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : १९५४ से अब नहीं की गई, तक इसके क्या कारण हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : अफसरों की कमी के कारण काम में देरी हुई है। अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि लैंड एक्वीज़िशन के मामलों को देखते हुए अफसरों की तादाद बढ़ाई जाय ताकि उनके फैसले होकर मुआवजा मिल जाय।

**श्री मुरलीधर व्यास** : अफसरों की तादाद नहीं बढ़ी तो क्या अब तक जिनकी भूमि ली गई है उनको मुआवजा नहीं मिलेगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : इस मामले के बारे में मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया जायेगा।

**श्री किशनाराम** ( रतनगढ़ ) : कौन कौन से ऑफिस में ऑफिसरों की कमी है, बता दीजिये ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## शुभधरा तथा कुशलपुरा बस्तियां, शाहबाद ब्लॉक

३५४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:–

(१) शाहबाद ब्लॉक में शुभधरा तथा कुशलपुरा बस्तियां किस सन् में बसाई गई थीं ?

(२) अब तक इन बस्तियों पर कुल कितना रुपया सरकार का किन किन प्रसंगों में खर्च हो चुका है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) प्रत्येक बस्ती में कितने परिवार बसाये गये तथा प्रत्येक परिवार को कितनी जमीन, कितनी राशि बैलों तथा कुंओं के लिये दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि जो तालाब इन बस्तियों के लिये सरकार ने बनाया था उससे गर्मियों व सर्दियों में पानी खेतों तक नहीं पहुँचता ?

(५) इस तालाब को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितनी भूमि इससे सिंचित होने

# Page No.13



( श्री दयाकृष्ण विजय )

का अनुमान था तथा इससे अधिकतम भूमि किस वर्ष में सिंचित हुई ?

(६) क्या यह सही है कि अधिकांश व्यक्ति जो इन बस्तियों में बसाये गये थे वे बस्तियां छोड़ कर चले गये हैं ?

(७) क्या इन बस्तियों के लिये एक पाठशाला भवन भी बनाया गया था ? उसमें कितना खर्चा हुआ तथा इस समय कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

(८) क्या सरकार पृथक समाज कल्याण विभाग को समाप्त कर उसकी राशि अनुसूचित जातियों में ही खर्च करने के लिये पंचायत समितियों को देने का विचार रखती है ?

**उद्योग मन्त्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सन् १६५५-५६ में।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) शुभधरा में १०० और कुशलपुरा में ८२ परिवार बसाये गये। प्रत्येक परिवार को १५ बीघा जमीन दी गई। ३ पीने के पानी के कुओं के हेतु ४,०००) रुपये की सहायता दी गई।

(४) जी हां।

(५) इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है; ५०० बीघा भूमि सिंचित होने का अनुमान था और करीब ५० बीघा भूमि में पानी लिया जाना पाया जाता है।

(६) जी नहीं। १५० परिवार मौजूद हैं।

(७) जी नहीं। एक स्कूल पंचायत घर में चल रही है और ५० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(८) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

**श्री दयाकृष्ण विजय** : इस तालाब से ५०० बीघा में पानी देना चाहिये था ५० बीघा में ही पानी दिया गया; इसका क्या कारण है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जितनी उस आबादी के लिये सिंचाई होनी चाहिये वह नहीं हो पाई है। वहां जो तालाब बनाया गया है उसमें पानी ज्यादा नहीं रह सकता।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : इसका अनुमान किसने लगाया कि ५०० बीघा को सिंचाई इससे होगी ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अनुमान तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ही लगाया, लेकिन जितना अन्दाज था वह पूरा नहीं हो सका; रोकी जगह होने की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर आईं।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आपने भाग (६) के उत्तर में बताया कि १५० परिवार बसे हुए हैं और पहले यह बताया गया था कि १८२ परिवार बसाये गये थे; ३२ कहां चले गये ?

# Page No.14



**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : कुछ परिवार चले गये। हो सकता है वह जमीन उनको सूट नहीं हुई हो।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : आखिर इन लोगों के छोड़ जाने का क्या कारण है?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : कई कारण हो सकते हैं। किसी को वहां की जमीन काश्त करने योग्य मालूम नहीं हुई हो, और भी कई दिक्कतें आई हों, इस वास्ते चले गये हों।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या यह सही है कि ५५ से लेकर ६० तक भूमि की व्यवस्था नहीं होने के कारण पहाड़ी जमीन छोड़ कर चले गये हैं?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऐसा नहीं है; १५० परिवार तो बस ही रहे हैं और उसी जमीन को अच्छी करके खेती कर रहे हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : तालाब में पानी न रुकने का क्या कारण है?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## तहसील सांगानेर (जयपुर) द्वारा दिया गया तकाबी ऋण

**३५५. श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में सन् १९५७–५८ से आज तक कितना कर्जा तकावी के रूप में किस किस ग्राम में और किस किस व्यक्ति को किस किस पंचायत क्षेत्र में किस कार्य हेतु दिया गया है? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जो रुपया तकावी कर्जे में दिया गया है उनका उपयोग ठीक हुआ या नहीं और रुपया कर्जे का वसूल होने लगा गया या नहीं? अगर नहीं होने लगा, तो उसका क्या कारण है?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा कि "तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में सन् १९५७–५८ से आज तक कितना कर्जा तकावी के रूप में किस किस ग्राम में और किस किस व्यक्ति को किस किस पंचायत क्षेत्र में किस कार्य हेतु दिया गया है?" इस प्रकार के १,५०० आदमी होते हैं और जो सूचना चाही गई है उसके अनुसार १२ कॉलम सम्भव होते हैं। इस प्रकार की सूचना से मैं नहीं पाया कि माननीय सदस्य का क्या पर्पज़ हल होने वाला है। इतना लंबा उत्तर होने के कारण इसका उत्तर अभी तक तैयार नहीं हो सका।

**श्री अध्यक्ष** : बॉड फीगर्स ही बता दीजिये।

**श्री श्रीमानसहिं** (बयाना) : But this cannot be made the basis of not answering the question in this House. His saying that the answer is lengthy, this is not sufficient. This can be taken and replied as an unstarred question.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That is, what I am saying.

श्री श्रीमानसिंह : But not answering the question like this in the House, that will be a bad practice and a bad precedent also.

श्री अध्यक्ष : I is a request for postponement actually.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is for changing it into unstared; becarrse it is really difficult to prepare such a lengthy reply and that will serve no useful purpose.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : How do you say, this will not serve any useful purpose ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is my opinion.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Before the reply is given in the House the Minister has already given his opinion.

## प्राइमरी रिफ्यूजीज़ स्कूल्स, जयपुर के शिक्षकों का वेतन

३५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) जयपुर शहर प्राइमरी रिफ्यूजीज़ स्कूल्स के शिक्षकों को पहले क्या वेतन मिलता था ?

(ख) क्या यह सत्य कि फरवरी, १९६० से उनके वेतन में कोई कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी तथा किस ऑर्डर से ? कृपया ऑर्डर की नकल सदन की मेज पर रखें ।

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जयपुर शहर के रिफ्यूजीज़ प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों को १-७-५२ से पहले ६०-३-९० की वेतन शृंखला में और कुछ को पचास रुपये फिक्स मिलते थे ।

(ख) जी हां । उनके वेतन में कटौती की गई । आज्ञाओं की प्रतिलिपिएं जिनसे उनका फिक्सेशन युनिफाइड पे स्केल में किया गया सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या शिक्षकों ने आपके पास इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वे सर्टीफाइड कॉपियां पेश नहीं कर सकते, इसलिए उनके ग्रेड वे ही रहने दिये जावें ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रूल्स की कॉपी आपको दे दी गई है । यह इन्टीग्रेशन ऑफ फिक्सेशन इनके अनुसार होता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : पर सवाल यह है कि बाहर से आये शरणार्थी थे । उनके पास सर्टीफिकेट्स रहे नहीं और यही समझ कर उनको ९० की ग्रेड में फिक्स किया था; तो क्या उनकी इस मजबूरी का भी ध्यान रखा गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सब विचार करके ही कम किया गया है ।

# Page No.16



**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : जयपुर के लिए या बाहर के लिए भी यही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सबके लिए यही है।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : स्कूल टीचर के बराबर ही क्वालिफाइड हैं वे, पर रिफ्यूजी की स्कूल में पढ़ाते थे इसलिए उनका पे स्केल भी वह नहीं रहा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह नहीं है; पहले रिलीफ रीहैबिलिटेशन ने उनको नियुक्ति दी। बाद में उनको इधर ट्रान्सफर कर दिया शिक्षा विभाग में। जब यहां ट्रान्सफर किया तो उनको कौनसा पे स्केल दिया जावे, यह सवाल आया। तो यह तय पाया गया कि इसी विभान की पे स्केल में उनको फिक्स किया जावे। उनके अनुसार पे फिक्स करने पर कई केसेज़ में उनकी तनख्वाहें कम हुई।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : जो आपने कहा वही समझ कर पूछा है। उनका दुर्भाग्य सिर्फ इतना था कि उनको रिफ्यूजी के लिए खुले स्कूलों में पढ़ाना स्वीकार किया था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : पर जब शिक्षा विभाग में वे आये तो हम तो नियमानुसार ही उनका फिक्सेशन कर सकते थे। यह कैसे करते कि उन्हीं की क्वालिफिकेशन के एक मास्टर को इस स्केल में देते और इनको उनसे अधिक देते ?

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : और जो अभी उस ग्रेड में आने से रह गये हैं उनका कुछ करने को तैयार हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी, जो नियम बने हैं उनके अनुसार ही उनको देखा जावेगा और उन्हीं के हिसाब से उनको रिलीफ दिया जावेगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या यह सही है कि सरकार ने इस सिद्धान्त को माना है कि जिसका वेतन ज्यादा है वही इन्टीग्रेटेड वेतन माना जावेगा और नये या किसी ग्रेड में भी उसको लिये जाने पर भी उसके वर्तमान वेतन में कमी नहीं की जावेगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने सूची दी है। अगर जरूरत पड़ी तो एडवान्स इन्क्रीमेन्ट देकर उनको लाभ पहुँचाया जा सकता है।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली) : एक सवाल उठता है जो वेतन उनको रिलीफ और रीहैबिलिटेशन विभाग से मिलता था उनको ग्रेड फिक्सेशन में कम कैसे कर सकते हैं ? It is not a kind affair, it is a very brutal affair.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : वे टेम्पोरेरी डिपार्टमेन्ट में थे।

**श्री जनार्दनराय नागर** : Temporary are no temporary. सवाल यह है कि आप एक टीचर की मिलती तनख्वाह में कम करते है, I think this is a very serious question and it requires a serious attention of the House and even of the Minister concerned.

Page No.17



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उनको सभी सुविधाएं दी गई हैं। उनकी एज ज्यादा थी तो वह कमी भी रिलेक्स करके दूर की गई। एरियर्स थे वे वेव कर दिये गये। पर क्वालिफिकेशन में अगर वह सातवीं क्लॉस का ही है और वेतन हम ६० की ग्रेड का देने लगें तो यह बैठ नहीं सकता था। यह फिर दूसरों के साथ भेदभाव की बात होती। हमने इन सारी बातों पर विचार किया और यही तय किया कि इनको भी राजस्थान के अन्य स्कूलों के वेतन क्रम में ही फिक्स करना चाहिये। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य सुविधाएं दी गई वे अलग हैं। जितना हम कर सकते थे वह किया है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : वे कितने हैं जिनके वेतन पहले से कम हुए हैं इन फिक्सेशनों में ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें आप।

## श्री सारनेश्वरजी (सिरोही) की जागीर

३५७. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that the Jagir of Saraneshwarji in Sirohi has been resumed by the State Government ?

(2) If so, has the Devasthan Department taken charge of the Jagir? A statement showing the date on which the Jagir was resumed and the date on which the Devasthan Department took charge of it may be placed on the table of the House.

**राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास)**:

1. Yes.

2. The Jagir of Sarneshwarji has been resumed and not the temple which is the personal Diety of the Maharao of Sirohi. As such the question of taking over charge of Jagir by the Devasthan Department does not arise.

The Jagir was resumed on 1. 11. 1959. and the charge of the same was taken over by the Tehsildar, Sirohi on 18. 11. 59.

**श्री पी० के० चौधरी** : And of the temple property ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I have already said that it is a private property of His Highness the Maharaja of Sirohi.

**श्री पी० के० चौधरी** : Is it correct that there is a Trust of the Temple ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I am not in the know of this.

## प्रश्न संख्या ३५८

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती गौरी पूनिया।

( अनुपस्थित )

## मिडल स्कूल भवन, बांसवाड़ा

३५९. **श्री मोगजी भाई** ( बांसवाड़ा ): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

# Page No.18



( श्री मोगजी भाई )

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा शहर के मिडल स्कूल में तीन कक्षाएं एक ही मकान में पढ़ाई जाती हैं ? यदि हां, तो उस मकान में कितने कमरे हैं और कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं ? ३१ जुलाई, १९६० तक भरती हुए विद्यार्थियों व शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से मिडल शाला भवन निर्माण के लिये सरकार के पास सुझाव पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्य-वाही की ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मिडल शाला में विद्यार्थी अधिक हैं तथा शिक्षकों का अभाव है ? यदि हां, तो इस अभाव की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

**उप मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (१) जी हां। बांसवाड़ा शहर की माध्यमिक शाला में ३ कक्षाएं हैं, ६,७ और ८। एक ही भवन में चलाई जाती हैं। इस भवन में छोटे-बड़े १३ कमरे हैं। इस समय ७६१ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं। ३१-७-६० तक जितने विद्यार्थी भरती हुए उनकी सूची संलग्न है।

(२) सन् १९५९-६० में स्कूल भवन निर्माण के लिये पांच हजार स्वीकार किये गये।

(३) और (४) जी हां। विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, परन्तु शिक्षकों का कोई अभाव नहीं है क्योंकि १९ सेक्शन्स हैं और २५ अध्यापक।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिए )

**श्री मोगजी भाई** : तीन-चार का एक साथ जवाब बता दिया, इसका क्या मतलब ? क्या यह सही है कि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से इस साल जगह नहीं मिली ? जिनको जगह नहीं मिली सात-आठ कक्षाओं में ऐसे कितने थे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह प्रश्न पूछते तो उत्तर देता। प्रश्न तो आपने भवन के अभाव का पूछा था, उसका उत्तर दे दिया।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): भवन के बारे में भी 'मकान' शब्द है; 'एक ही मकान में', तो एक ही मकान या कमरा है, क्या है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : एक मकान जिसमें १३ कमरे हैं, यह मैंने निवेदन किया।

**यज्ञनारायण अस्पताल भवन, किशनगढ़**

३६०. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** ( किशनगढ़ ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल की इमारत की मरम्मत आदि के लिये कोई रकम स्वीकृत हुई है ?

(ख) अगर हां, तो यह स्वीकृत कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं किया गया व अब कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ( श्री हरिश्चन्द्र )** : (क) जी हां।

(ख) टेन्डर मांगे जा रहे हैं। टेन्डरों की स्वीकृति होने पर।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : ऑर्डिनेरी मेन्टीनेन्स के लिये ७०८) रु० और एडीशन-ऑल्टरेशन के ५०,०००) रु०।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह पचास हजार का काम कब शुरू होगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने कहा न कि टेन्डर स्वीकार होने के बाद।

## जिला जोधपुर तथा नागोर में चद्दरों का कोटा

३६१. **श्रीमती गोरी पूनिया** [डिगाना-श्री अनूपसिंह ( बालोतरा ) द्वारा पूछा गया]: क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जोधपुर व नागोर के गांवों मे लोहे की चद्दरों का कोटा किसानों की मांग को देखते हुए बहुत ही कम आता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि सिविल सप्लाइज़ विभाग में आवश्यकता से अधिक चद्दरों का कोटा आता है जिसका अक्सर ब्लैक होता है ? क्या सरकार अपनी इस वितरण प्रणाली में कुछ सुधार करने का विचार रखती है ?

**नागरिक रसद मन्त्री ( श्री रिखबचन्द धारीवाल )** : (क) जी हां। चद्दरों का उत्पादन अभी कम है, अतः मांग की अपेक्षा कोटा कम ही आता है।

सिविल सप्लाइज़ विभाग में जरूरत से ज्यादा चद्दरों का कोटा कभी नहीं आया। मौजूदा वितरण प्रणाली में किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**श्री अनूपसिंह** : क्या यह भी मालूम किया कि जब कोटा हिसाब से आता है तो ब्लैक मार्केट कहां से होता है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने निवेदन किया कि सिविल सप्लाइज़ तो एग्रीकल्चर विभाग को अलग कोटा दे देता है। वह अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वितरण के लिये भेज देता है। कुछ कोटा कलेक्टर के सुपुर्द कर दिया जाता है। सिविल सप्लाइज़ के लिये जो जरूरत होती है अलग अलग आदमियों को वितरित कर दिया जाता है। अब आप कोई स्पेसिफिक ब्लैक मार्केट की इन्स्टान्स बतावें तो जांच कराई जा सकती है।

**श्री अनूपसिंह** : आपने जांच करने की कोशिश की ? एक कोटा पर्टिक्युलर डीलर को दे दिया जाता है। आप उसको जांच नहीं सकते और थोड़े दिन बाद कह दिया जाता है कि फ्री बेच सकते हो। उस समय आप फ्री बेचने के बजाय उसे अपने अधिकार में लेकर बेच सकते हैं पर आप उनको फ्री बेचने की इजाजत दे देते हैं और यह फिर ब्लैक मार्केट में आता है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** ऐसा है, इसके लिये तो वह सेन्ट्रल कन्ट्रोल ऑर्डर मौजूद है। इसके तहत में जो रूल्स हैं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है। वह हमारे हाथ की बात नहीं है। जो डीलर यह कहे कि उसका माल दो साल नहीं बिका तो रूल्स के तहत हम उसको फ्री करते हैं। इसलिए इसके लिये कुछ करना सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ की बात है। माल नहीं बिकता तो दो साल के बाद फ्री सेल कर सकता है। इसलिये हमारा तो इस पर कोई नियन्त्रण है नहीं, जो कुछ है ऑर्डर में है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : सवाल इस बात का है कि जब आपके पास सप्लाई के लिए इस प्रकार से टीनें नहीं हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्केट में जितनी टीनें चाहें उतनी खरीद सकते हैं तो क्या इसके लिए कभी सरकार ने जांच करके देखा है कि बाहर ब्लैक मार्केट के लिए टीनें कहां से आती हैं? जब आपके पास नहीं हैं और चीज़ थोड़ी है तो जब चीज थोड़ी होती है और मांग ज्यादा होती है तो जिनको चाहिए उनको बंधी हुई रेट पर मिल जानी चाहिए। यह सब कुछ होते हुए भी वह मार्केट में ब्लैक से मिलती हैं तो इसका भी हिसाब लगाया कि ये क्यों मिलती है?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** जी हां, हिसाब तो बहुत लगाया और उसके करने की भी बहुत कोशिश की गई लेकिन जो परिस्थितियां हैं वे आपको मालूम हैं। बहुत से आदमी इस तरह के हैं कि जो अपनी मांग देते हैं और लेते नहीं हैं। दो महीने का अवसर भी निकल जाता है और फिर वह मार्केट में फ्री सेल के लिए जाता है।

**श्री अध्यक्ष :** कितने दिन बाद स्टॉकिस्ट्स बाहर बेच सकता है?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** आइरन एण्ड स्टील ऑर्डर्स के अन्तर्गत जो रूल्स बना रखे हैं उनके तहत में स्टॉकिस्ट्स के पास जब माल आये तो दो महीने के अन्दर अन्दर बेच दे। अगर नहीं बेचता है तो फिर फ्री सेल कर सकते हैं।

**श्री अनूपसिंह :** मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जिस तरह की हैल्पलैसनैस जाहिर कर रहे हैं, उससे यह देखना चाहिए कि सिविल के लिए जो कोटा है अगर उसको एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए कन्वर्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? जब आप जानते हैं कि मार्केट में चीजें हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ ही कन्वर्ट करनी है तो ऐसा आप क्यों नहीं कर देते?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** कन्वर्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो कोटा सिविल पर्पज़ के लिए आता है वह अलग है और जो कोटा एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए आता है वह अलग आता है। तो आप किसमें कन्वर्शन चाहते हैं, सिविल से एग्रीकल्चर की तरफ या एग्रीकल्चर से सिविल की तरफ?

**श्री अनूपसिंह :** अगर एक तरफ काम नहीं आता है तो दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया जाये।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल :** No. No. We cannot do it. This is fixed and no change can be made.

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह जो माननीय मंत्री महोदय कमजोरी दिखाते हैं, जो लोग खुले मार्केट में ब्लैक से बेचते हैं तो आप उनके माल को सीज़ क्यों नहीं करते ? जब आपको मालूम है कि इस तरह की गड़बड़ी होती है तो इसको आप सीज़ कर लें और पूछें कि आप यह कहां से लाये ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : सीज़ करने का सवाल नहीं है। फ्री सेल जब उनको अलाउ है तो वह होगा ही। जब उनको फ्री सेल का अधिकार है तो सीज़ करने का प्रश्न कहां खड़ा होता है ?

**श्री दयाकृष्ण विजय ( छबड़ा )** : जो फ्री सेल करते हैं दो महीने के बाद, तो क्या आप उनके भावों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि वे कन्ट्रोल के दाम से ही बेचें या वे मनमाने भाव से बेच सकते हैं ?

**श्री रिखबचंद धारीवाल** : वे तो हमेशा कन्ट्रोल के ऊपर ही बेचेंगे, रसीद तो कन्ट्रोल रेट की ही देंगे ; फिर वह ब्लैक से कहां हुआ ? हमारे हाथ में कहां है ?

**श्री जनार्दनराय नागर ( मावली )** : आपने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो एज़ ए गवर्नमेंट फिर आपके हाथ में क्या है ? जब कि खुले आम ब्लैक मार्केट होता है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में क्या है ?

**श्री पी० के० चौधरी ( फुलेरा )** : पंचायत समितियां बनने के बाद वितरण का काम पंचायत समितियों द्वारा या कोऑपरेटिव्ज़ के द्वारा नहीं करा कर एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को क्यों देते हैं ? डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर को क्यों वितरण का काम देते हैं जब कि पंचायत समितियों के पास डिस्ट्रीब्युशन की स्टेचुटरी पॉवर्स हैं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अब ऑर्डर्स दे दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न एग्रीकल्चर के कोटे का नहीं है, यह तो सिविल सप्लाई के कोटे के बारे में है।

**श्री पी० के० चौधरी** : He has said about Agriculture Quota....

**श्री अध्यक्ष** : He has not said so.

**श्री पी० के० चौधरी** : He said.

**श्री अध्यक्ष** : No. This question is concerned with the Civil Supplies quota and he has said that he cannot convert the Civil Supply Quota into Agriculture quota.

**श्री लक्ष्मीचन्द ( सांचोर )** : क्या यह सत्य है कि जो सप्लाइंग ऑथोरिटी है वह समय पर परमिट इश्यू नहीं करते इसलिए माल ब्लैक मार्केट में आता है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऐसी शिकायत तो नहीं आई है, अगर आप स्पेसिफिकेली इसके बारे में कहें तो जानकारी करके बताया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि दो महीने में पर्मिट्स इश्यू हो जायें ताकि फ्री सेल का प्रश्न ही पैदा नहीं हो ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यही कोशिश की जाती है और कलेक्टर के पास सिविल सप्लाईज़ में आये हुए कोटे को वितरित करने का अधिकार है और जो एग्रीकल्चरल कोटा है वह डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के पास रहता है और वही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वह जो डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनको वितरित कर देते हैं और वह उसकी व्यवस्था करते हैं।

**श्री पी० के० चौधरी** : He is committing, Sir.

**श्री अध्यक्ष** : वह भी आज-कल पंचायत समिति करती हैं।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : वह उनको अब ऑर्डर्स दे दिये हैं।

( कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर )

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री अनूपसिंह।

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री अनूपसिंह।

### जसवन्त सराय, जोधपुर

३६२. **श्री अनूपसिंह** ( बालोतरा ) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर स्थित जसवन्त सराय की वार्षिक मरम्मत के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित है और उसे किसके द्वारा खर्च कराया जाता है? मरम्मत के औचित्य को कौन तय करता है?

(२) जसवन्त सराय में ऐसे कितने मकान हैं जिनकी पिछले पांच साल से पोताई तक नहीं हुई?

(३) क्या यह सही है कि मरम्मत की रकम कुछ सरकारी कर्मचारियों के मकान पर ही खर्च कर दी जाती है जिससे दूसरे मकानों के लिये कोई रकम नहीं बचती?

(४) जसवन्त सराय के मकानों में कुल कितने सरकारी कर्मचारी किराया देकर रहते हैं? उनके नाम की सूची देने की कृपा करें। सराय में कुल कितने मकान हैं और उनका कुल किराया कितना आता है?

**देवस्थान मन्त्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : (१) जसवन्त सराय की वार्षिक मरम्मत के लिये १,६००) रु० की धन-राशि निर्धारित है जो जन कार्य विभाग द्वारा खर्च होती है। मरम्मत में औचित्य को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर तय करता है।

(२) ऐसा कोई मकान नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) जसवन्त सराय में कुल मिला कर १४२ मकान किराये के हैं जिनके किराये की कुल माहवारी आमदनी १,३६६.५६ नये पैसे होती है। जसवन्त सराय के कुल किरायेदारान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सरकारी मुलाजिम व दीगर

( श्री दामोदरलाल व्यास )

लोगों की सूचियां अलहदा-अलहदा नहीं बनाई जाती हैं ।

( कृपया परिशिष्ट ७ देखिये )

**श्री अनूपसिंह** : आपने यह फरमाया कि औचित्य को तय करते हैं और काम करवाते हैं पी० डब्ल्यू० डी० वाले, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के काम कराने के बाद में यह कोई देखता है कि काम होता है या नहीं या जो काम होना चाहिये था वह हुआ है या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : दोनों बातें होती हैं । औचित्य तय किया जाता है, काम किया भी जाता है और काम हो जाने के बाद उसे देखा भी जाता है ।

**श्री अनूपसिंह** : क्या आपको मालूम है कि इन मकानों में वाकई कई मकान ऐसे हैं जो पांच साल से ठीक नहीं हैं, इसकी जांच कराने की कोशिश की ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

**प्रश्न संख्या ३६३**

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती गोरी पूनिया ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी)**: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाये ।

**श्री मांगीलाल 'मंगल' द्वारा रॉकेट छोड़ा जाना**

३६४. **श्री भैरोंसिंह** [ श्री माधोपुर—श्री मुरलीधर व्यास ( बीकानेर सीटी ) द्वारा पूछा गया ] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि धौलपुर निवासी श्री मांगीलाल 'मंगल' दिनांक १२ या १३ जून, १९६० को सायंकाल ६ बजे राकेट छोड़ने का प्रदर्शन करने वाले थे ?

(ख) क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए निश्चित स्थान तथा समय पर राजस्थान के कई मन्त्रीगण व शहर की काफी जनता वहां पहुंच गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि निर्धारित समय से पूर्व जिलाधीश महोदय ने दुर्गापुरा पहुँच कर रॉकेट छोड़ने से श्री 'मंगल' को रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि कुछ दिनों पश्चात् यह रॉकेट माननीय मुख्य मन्त्री व अन्य मन्त्रियों की उपस्थिति में छोड़ा गया ? यदि हां, तो उस समय इसकी आज्ञा किस प्रकार दी गई और क्या आज्ञा देने से पहले राकेट छोड़ने से होने वाले परिणाम की पूर्णतया जानकारी कर ली गई थी ? यदि हां, तो यह जानकारी किस प्रकार की गई ?

**उप मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

(घ) श्री 'मंगल' ने रॉकेट छोड़ने की पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी । यह सही है कि कुछ दिनों बाद यह राकेट मुख्य मन्त्रीजी और अन्य मन्त्रियों की उपस्थिति में श्री 'मंगल' ने छोड़ा । इसके बारे में रॉकेट छोड़ने के लिए श्री 'मंगल' ने पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । उसकी समुचित जांच किये जाने पर राकेट छोड़ने की स्वीकृत दे दी गई । स्वीकृति देने के पहले रॉकेट फायर होने से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर विचार कर लिया गया था। इसके बारे में सब सम्बन्धित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई और सलाह ली गई।

**श्री पी. के. चौधरी ( फुलेरा ) :** ये परिणाम क्या क्या आये थे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इसके बारे में प्रश्न पूछा नहीं गया है।

**श्री पी० के० चौधरी :** आपने किन एक्सपर्ट्स की राय ली थी कि इसको छोड़ा जाये या नहीं या इसको छोड़ा जाना डेट्रीमेन्टल होगा या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** कलेक्टर ने कॉलेज के प्रोफेसर्स से राय ली थी।

**श्री श्रीभानसिंह (बयाना ) :** वे कौनसे प्रोफेसर्स थे जिनसे राय ली थी ?

**श्री पी. के. चौधरी :** जिन्होंने राय दी थी कि यह वाकई में रॉकेट या और कोई आतिशबाजी नहीं है; यह किस प्रोफेसर ने राय दी थी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** प्रोफेसर का नाम तो याद नहीं है । अगर आप प्रश्न पूछें तो जानकारी करके बताया जा सकता है। यह तो इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

**श्री पी० के० चौधरी :** जब परिणामों की जांच करवाई थी तो उसमें से कुछ धूल और कंकड़ माननीय मुख्य मन्त्रीजी के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर पड़े थे, ऐसा क्यों हुआ ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** ऐसे एम्बीशियस प्रोग्रामों में गड़बड़ी हो ही जाती है। अमेरिका वाले भी छोड़ते हैं तो बहुत से जमीन पर ही नष्ट हो जाते हैं।

**श्री जनार्दनराय नागर (मावली) :** यह दुर्गापुरा में एक खेत से छोड़ा गया और माननीय मन्त्री महोदय अमेरिका की बात करते हैं । क्या उनको मालूम है कि अमेरिका के अन्दर किस जगह पर ये परीक्षण किये जाते हैं ? यह रॉकेट है, this is a mysterious affair to be examined.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** साइन्स के प्रोफेसर्स थे वे मौके पर उपस्थित थे।

**श्री जनार्दनराय नागर :** वे प्रोफेसर्स दूसरी साइन्स के होंगे । मेरे ख्याल से तो क्या फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स कह सकते हैं कि यह रॉकेट है और इसको छोड़ना चाहिये ? यहां के फ़िज़िक्स के प्रोफेसर्स क्या यह कह सकेंगे कि यह रॉकेट है ?

# Page No.25



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : रॉकेट के लिए तो यहां के साइन्स के प्रोफेसर्स ही कह सकते हैं ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : How they can say ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : जिन प्रोफेसर्स ने राय दी थी तो क्या रॉकेट छोड़ने वाले ने प्रोफेसर्स को बता दिया था कि इसमें क्या क्या मेटीरियल था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : चर्चा हुई थी इसके लिए । श्री 'मंगल' भी बहुत से सीक्रेट्स को देना नहीं चाहते थे और उन्होंने कितना सीक्रेट दिया, कितना नहीं दिया; तो आपस में उनके बातचीत जरूर हुई थी ।

**श्री जनार्दनराय नागर** : रॉकेट छोड़ने के बाद जो परिणाम हुए, क्या इस नतीजे पर सरकार पहुँची है कि इस तरह की इजाजत देना एक प्रकार से इर्रेस्पोन्सिबल इजाजत थी ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**हरिजन कुआं, रूपनगढ़ (अजमेर)**

३६६. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या रूपनगढ़ (जिला अजमेर) में जो पुलिस थाना बन रहा है उसकी बाउन्ड्री में हरिजनों के पानी पीने का कुआं आ गया है ?

(२) अगर हां, तो क्या इस कुएं के एवज में हरिजनों को कोई दूसरा कुआं खुदवाने के लिए पैसा दिया गया है ?

(३) अगर नहीं, तो अब वे हरिजन किस कुएं से पानी पीने के लिए लायेंगे ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)** : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं, इनको पानी के लिए दूसरा कुआं फिलहाल बता दिया गया है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह बिल्कुल गलत बात है । कोई कुआं नहीं बताया गया है और वे बेचारे परेशान हैं ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैं उनकी जांच करा लूंगा । मेरे पास लिखा है कि दूसरा कुआं बतला दिया गया है ।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : उनकी तो यह भी मांग है कि दूसरा कुआं खुदवा कर देना चाहिये ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : यह बात दूसरी है ।

**श्री पुरुषोतमलाल शर्मा** : लेकिन अभी तक तो दूसरा कुआं भी नहीं बतलाया गया है ।

**श्री हरिश्चन्द्र** : मैंने कहा न कि मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : पी. डब्ल्यू. डी. ने यह कुआं लिया है वह किस कार्य के लिए लिया है ?

# Page No.26



**श्री हरिश्चन्द्र** : पुलिस थाने की बाउन्ड्री में आया, इसलिए लेना पड़ा है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या हरिजन वहां पर पानी नहीं भर सकते ?

**श्री हरिश्चन्द्र** : पानी क्यों नहीं भर सकते ? कुआं खुदवाने के लिए तखमीना हो गया है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): पानी भरने में क्या नुकसान है, साहब ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

## ग्राम भाप के नमक भूखण्डों का आवण्टन

३७०. **श्री सूरजमल** (फलोदी-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— फलोदी तहसील के गांव भाप में नमक के कुलकितने प्लॉट अलॉट किये जिनमें से कितने सवर्ण जाति के व्यक्तियों को और कितने अनुसूचित और अन्य पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्तियों को अलॉट किए गए ? नाम सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उद्योग मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : नमक के कुल २६२ प्लॉट्स अलॉट किये गए जिनमें ४ प्लॉट्स तो अनुसूचित जाति व ८ पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्तियों को दिये गए, बाकी सवर्ण जाति व सहकारी समितियों इत्यादि को। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। ४३ और प्लॉट्स अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए रिज़र्व में रखे हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : ये प्लॉट्स जो हैं किस किस अवधि में किस किस वर्ष में अलॉट किये गए ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : कुछ तो इस साल और कुछ गये साल में हुये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो प्लॉट्स बाकी हैं वे कब तक दे दिये जायेंगे ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : कुछ तो फार्मर्स को दे दिये गये हैं और जो रिज़र्व है ज्यों २ दरख्वास्तें आयेंगी अलॉट कर दिये जायेंगे।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : जिस एरिया के निवासियों के लिये रिज़र्व किये हैं ये उन्हें ही दे दिये जायं।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : उन्हीं के लिये तो मैंने कहा है।

**श्री हीराभाई** : जिनके लिये रिज़र्व किये हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपको मालूम नहीं होगा, वहां पर तो सबको मालूम है।

## सहकारी ऋण को ब्याज दर

३७१. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

# Page No.27



( श्री हीराभाई )

(१) क्या सरकार ने साहूकारी कर्ज पर मनमाना ब्याज लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का कानून बनाया है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों तथा सरकार ऐसा कानून कब तक बनाने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि साहूकार लोग अपने मनमाने हिसाब से चार माह के अन्दर लोगों से डेढ़, दुगुने ब्याज सहित रकम वसूल करते हैं जिससे जनता कर्ज में दबती जा रही है ?

**राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :** (१) जी हां । Usurious loans Act, 1918 (Central Parliamint ) राजस्थान आॅर्डिनेंस नं० ४ आॅफ १९५० के अनुसार राजस्थान में भी लागू होता है एवम् राजस्थान रिलीफ एन्ड एग्रीकल्चरल इन्डेटनैस एक्ट, १९५७ (राजस्थान एक्ट नं० २८ आॅफ १९५७) पहले से प्रचलित है जिसमें दामदूपट का नियम, ब्याज की दर कम करना व विशेष केसेज़ मे मूलधन को भी कम लिए जाने के नियम विद्यमान हैं। इनके अलावा भी राजस्थान मनी लैंडर्स बिल, १९६० इसी सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे रुपये की लेन-देन और भी अच्छे ढंग से की जा सकेगी।

(२) इस प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न में आ चुका है।

(३) ऐसा कोई विशेष दृष्टांत सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है।

**श्री हीराभाई :** क्या यह पहले आपने बतलाया, ५८ में पहले भी विज्ञापन हुआ था उनका ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** विज्ञापन हुआ, पहले ही कानून बना हुआ है उसका नाम युजूरियस लोन्स एक्ट, १९१८ है। उनमें मनीलैंडिंग करने वाले अधिक ब्याज वसूल नहीं कर सकें, जिसके लिए उसमें अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।

**श्री हीराभाई :** अगर ब्याज अधिक ले तो उनकी कौन जांच करे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अदालत में जाने पर अदालत कार्यवाही करे।

**श्री हीराभाई :** क्या सब साहूकारों को अधिक ब्याज लेने पर कोर्ट वहां पर जाकर जांच करती है ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य के पास दो कॉपियां एक्ट की भिजवा दें।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** यह एक्ट तो पहले से ही गजट में प्रकाशित हो चुका है। अतः माननीय सदस्य वहां से ही प्रतियां ले सकें तो अच्छा हो।

**श्री हीराभाई :** आपने कानून तो बना दिया लेकिन आज भी दूना, तिगुना और चौगुना तक ब्याज लोगों से साहूकार लोग लेते हैं और आपका कानून पड़ा रहता है टोकरियों में। तो इसके लिए कानूनको लागू किया जाय या नहीं किया जाय कानून जब लागू किया जाय ? तो उसके लिए यह इन्तजाम भी किया जाय कि पुलिस को कुछ अधिकार दे दिये जायं

( श्री हीराभाई )

ताकि जांच करके जो गैर कानूनी ब्याज लेते हैं उस पर कुछ अपराध भी बन सके।

मुख्य मंत्री ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : प्रश्न क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : समस्या का प्रतिपादन हुआ।

(विराम)

श्री मोहब्बतसिंह।

## गवर्नमेंट कॉलेज, सिरोही के विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदानों की व्यवस्था

३७२. श्री मोहब्बतसिंह ( सिरोही ): Will the Education Minister be pleased to state :—

1. Whether the Government is aware of the acute shortage of play ground for College students at Sirohi ?

2. If so, what steps have been taken to meet this demand ?

उप मंत्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : 1. Yes Sir.

2. 20 acres of land is already available but the same is to be levelled and cleared up for the use of play fields. A sum of Rs. 2,225/-has been provided in the current year for this purpose and the work has been started.

## लूनी नदी पर पुल निर्माण

३७३. श्री अनूपसिंह ( बालोतरा ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में बालोतरा शहर से जसोल ग्राम के बीच लूनी नदी पर एक लो पिलर ब्रिज (low pillarbridge) बनाने की योजना हेतु सर्वे, तखमीना इत्यादि किया गया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि योजना को क्रियान्वित करने की स्वीकृति हो गई है ? यदि हां, तो कार्यारम्भ करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

(ग) कार्यारम्भ होने पर कितने समय में और कितने खर्चे से यह पुल बन कर तैयार हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री ( श्री हरिश्चन्द्र ) : (क) जी हां। लो लेवल वेन्टेड कॉज़वे ( low level vented cause way) के लिए, न कि लो पिलर ब्रिज ( low pillar bridge ) के लिए।

(ख) जी नहीं, पुल का "डिज़ाइन" सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, जोधपुर के दफ्तर में तैयार हो रहा है।

(ग) तखमीने का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

## चूरू जिले की अध्यापिकाओं का फिक्सेशन

**३७४. श्री रावतराम** ( चूरू-सु० ) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या चूरू जिले की प्राइमरी व माध्यमिक कन्या शालाओं की अध्यापिकाओं का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा अब उनका फिक्सेशन कब तक हो जावेगा ?

**उप मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : जी हां।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन ।

## फ्लो ( Flow ) एरिया की अस्थाई काश्त भूमि की दर

**३७५. श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार राजस्थान नहर के फ्लो [ Flow ] एरिया में टेम्परेरी कल्टीवेशन के लिए दी गई जमीन पर चालू बन्दोबस्त के समय में निर्धारित दरों से अधिक दरों [ Lease amount ) के तौर पर वसूल करती है ? अगर हां, तो सरकार को किस कानून के अन्तर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं ? कृपया सम्बन्धित कानून की सम्बन्धित धारा रीप्रोड्यूस की जावे ।

(ख) क्या इस प्रकार सरकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा ३५ का उल्लंघन नहीं करती है ?

(ग) क्या सरकार इस प्रकार उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिक टैक्स इम्पोज नहीं कर रही है ?

**राजस्व मन्त्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : (क) जी हां, मालकाना फ्लो एरिया में वसूल किया जाता है जिसकी वसूली दफा ७ कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत जो कॉलोनी कन्डीशन्स बनी हैं उनके तहत वसूल किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

## सिवाना व पचभद्रा ब्लॉक

**३७६. श्री अनूपसिंह** ( बालोतरा ) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) तहसील सिवाना व पंचभद्रा ब्लॉक में सन् १९५७-५८, १९५८-५९, ५९-६० और ६०-६१ में कुल कितनी धन-राशि तकावी के रूप में और सबसिडी की तरह बांटी गई और किस किस मद में ? कृपया मदवार दोनों खण्डों की तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(२) तकावी की कितनी रकम वसूल हो चुकी व कितनी बकाया है ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि बहुत से काश्तकारों से पम्पिंग सेट व पर्शियन व्हील खरीदने के लिए रकम की रसीदें ले ली गईं और रकम नहीं दी गई, न मशीन या पर्शियन व्हील ही दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस हैं ?

( श्री अनूपसिंह )

(४) क्या यह सही है कि ऐसे काश्तकारों से तो कुड़की द्वारा रकम वसूल की जा रही है और सरकारी कर्मचारी व व्यापारी ( Dealers ) जिन्होंने यह अनियमितता की उनके खिलाफ कोई कदम नहीं लिए जा रहे हैं।

(५) क्या इस बारे में कलेक्टर ने जांच करके कोई रिपोर्ट दी है?

उप मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) १३ काश्तकारों के ऐसे मामले हैं जिन्हें पम्पिग सेट व पर्शियन व्हील खरीदने के लिए रकम मंजूर की गई थी। तीन काश्तकारों को पम्पिग सेट लगाने के लिए प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये मंजूर किए गए थे। इसी प्रकार दस काश्तकारों को पर्शियन व्हील के लिए कुल मिला कर पांच हजार रुपये दिए गए थे। इन मंजूर शुदा रकमों का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा यह प्रमाणित करने पर उनकी रसीद लेकर किया था कि उन्होंने अपने हिस्से की रकम उक्त फर्म को पहले से ही दे दी है। जिलाधीश, बाड़मेर ने दोनों मामलों में जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट भेज दी है और उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है।

(४) कुड़की द्वारा रकम की वसूली केवल उन्हीं काश्तकारों से की जा रही है जिन्होंने अपने हिस्से की रकम के भुगतान करने के बारे में प्रमाणित तो कर दिया था परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं किया गया। जिन फर्मों ने पम्पिग सेट व पर्शियन व्हील सप्लाई नहीं किये हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनियमितता करने व उसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

(५) जी हां।

( कृपया परिशिष्ट ६ देखिए )

**श्री अनूपसिंह** : क्या यह आपकी जानकारी में है कि जिनके लिए यह कहा गया था कि रकम ले लेते हैं उनके पास एक्चुअल रकम नहीं पहुँची ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने निवेदन कर दिया कि कायदा ऐसा नहीं है। जिनको पर्शियन व्हील देते हैं वे अपने हिस्से का रुपया जमा करा दें। उसके रसीद देने पर यह रुपया उस फर्म को सीधा दिया जाता है। ऐसा देखा गया कि जिस काम के लिए रकम दी जाती है वह उस काम में नहीं लगती। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि फर्म को सीधा रुपया दिया जाय। जैसा मैंने निवेदन किया दस केसेज़ ऐसे आए हैं जिनमें फर्म्स को रुपया दिया गया लेकिन उन्होंने माल सप्लाई नहीं किया। फर्म के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

**श्री अनूपसिंह** : कृषक के खिलाफ तो कार्यवाही की जा रही है जिसको कि पहले ही माल नहीं मिला, फर्म ने उनको माल नहीं दिया जो कि उन्हें देना चाहिए था, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

Page No.31



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय सदस्य ने इसके लिए मैंने जो पहले उत्तर दिया उसको ध्यान से सुना नहीं। तीन काश्तकारों ने प्रारम्भ में रसीदें पेश कर उस फर्म को अपने हिस्से के रुपये जमा करा दिए लेकिन जिन्होंने रुपये जमा नहीं कराए उनसे वापिस वसूल करने के लिए उनको नोटिस दिए गए हैं।

**श्री अनूपसिंह** : आपने यह फरमाया कि कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों ने ही तो वास्तव में यह सारी बातें कराई हैं, नहीं तो रकम कहां गई? उन किसानों ने उन कर्मचारियों के भरोसे रसीदें दे दीं और उन्हीं के भरोसे रह गए। लेकिन न तो उनको माल मिला और न रुपया ही। फिर भी कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जायेगा, यह बड़ी अजीब बात है!

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जिस स्थिति में हमारे सामने अभी कलेक्टर की रिपोर्ट आई उससे कर्मचारियों की गल्ती मालूम नहीं होती है। गल्ती फर्म्स की है जिन्होंने रुपये ले लिये और टाइम पर पर्शियन व्हील सप्लाई नहीं किये।

**श्री किशनाराम (रतनगढ़)** : कलेक्टर के बारे में 'जी हां' कहा तो क्या रिपोर्ट दी है, बतला दें?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आप कृपया जोर से फर्मावें तो बतला दूं।

**श्री अध्यक्ष** : भाग (५) में जो कलेक्टर की रिपोर्ट आई है वह बतला दें।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : उसमें जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि फर्म्स के खिलाफ रिकवरी का किया है और जिन काश्तकारों ने फर्जी सर्टीफिकेट दे दिये हैं उनके खिलाफ रिकवरी का ऑर्डर दे दिया है। डिटेल्ड रिपोर्ट है। सब वाकया बताया है।

## अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१९६०–६१) के प्रथम खण्ड के विवरण का उपस्थापन

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री, वित्त)** : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का १९६०-६१ के प्रथम खण्ड के विवरण को उपस्थापित करता हूँ।

(१२. ०६. म. प.)

## राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं उस पर विचार–विमर्श

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा से संबंधित विभिन्न मदों के ज्ञापन को जिनको कि दिनांक २ दिसम्बर, १९६० को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित आंकड़ों पर चर्चा करूं, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त होगा कि मैं इसके पहले और जिस भूमिका में हम तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते है उसके बारे में विचार करें।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

पहली पंचवर्षीय योजना जैसा कि सब को विदित है राजस्थान के अन्दर इन्टीग्रेशन और कई कारणों की वजह से सही मायने में योजना के रूप में राजस्थान के अन्दर उस पर अमल हो सका हो, वह एक मुश्किल बात थी और पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान में अधिक नहीं हो पाया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो रूपरेखा बनाई गई उसके अन्दर हम कुछ हद तक प्रगति कर पाये हैं। कुछ हद तक, मैं इस ख्याल से कहता हूं कि जो सारे देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उसको है ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी राजस्थान अन्य कई राज्यों से और अगर हम भारत के औसत तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जांच पड़ताल करें तो उस लिहाज से भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी राजस्थान पिछड़ा हुआ रहेगा। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो कुछ धनराशि १०५ करोड़ को राजस्थान और अजमेर दोनों को सम्मिलित करके राजस्थान में थी, सौभाग्य की बात यह है कि हम उस १०५ करोड़ रुपयों में से करीब करीब १०२ करोड़ रुपयों के आसपास राजस्थान के अन्दर खर्च करने में कामयाब होंगे।

हरएक योजना पर जब हम विचार करें तो यह आवश्यक है कि उसके साथ साथ हम इस पक्ष को देखें कि जब हम योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सारे साधन चाहिये जिनको हम रिसोर्सेज़ कहते हैं, उनके बारे में हमारी क्या स्थिति है। और जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम विचार करना चाहते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो कुछ इस संबन्ध में हमने निर्णय लिये हैं उनमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, उस पर भी निगाह डालना, मैं समझता हूं, उचित होगा।

जब तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई तो शुरू के अन्दर जो प्लानिंग कमीशन के साथ जो निर्णय हमने किये थे उसको हम सामने रख कर न भी चले यदि वे कम थे तो भी हमारी तरफ से रिसोर्सेज़ करने का जब भी एक निर्णय १९५७ के अन्दर जो किया गया उसके अनुसार राजस्थान ने अपनी तरफ से जिनको कि हम रेवेन्यू रिसोर्सेज़ और कैपिटल रिसोर्सेज़ दोनों साइड को मिलाकर ३१ करोड़ के करीब राजस्थान को करना था, उसके मुकाबले में इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम अपने रिसोर्सेज़ को प्लान के लिए ४०.०५ करोड़ राजस्थान के प्लान के रिसोर्सेज़ के लिए कन्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका मतलब यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो कुछ हमने रूपरेखा बनाई, जहां तक राजस्थान का प्रश्न था उसने अपने रिसोर्सेज़ रेज़ करने के अन्दर हर प्रकार से पूरा प्रयत्न किया और जो कुछ हम पर जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को ही नहीं बल्कि कुछ अधिक करने का राजस्थान ने प्रयत्न किया। यहां तक कि, अध्यक्ष महोदय, जो एडीशनल टेक्सेशन ११ करोड़ के रेज़ करने थे उसके अन्दर भी ट्रेन्ड इन्क्रीज़ और सारी बातों को देखते हुए भी करीब १३.०५ करोड़ के करीब २ सेकन्ड फाइव इअर प्लान को फाइनेन्स करने में एडीशनल टेक्सेशन के जरिये, रेवेन्यू रिसोर्सेज़ करने की साइड में पूरा करने में कामयाब होंगे।

अब जब कि हम खर्चे पर निगाह डालते

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हैं तो स्वाभाविक रूप से यह बात उठ सकती है कि एक्सपेन्डीचर, खर्चा और अपने रिसोर्सेज़ के लिहाज से तो हमने बहुत कुछ किया है लेकिन फिज़ीकल टार्गेटस के लिहाज से दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य हमने तय किये थे उसमें किस हद तक कामयाबी हुए, तो उसकी जानकारी भी मैं आपके द्वारा इस सदन को देना चाहता हूँ कुछ खास खास क्षेत्रों के बारे में। उदाहरण के तौर पर, कृषि के क्षेत्र के अन्दर अन्न के उत्पादन के लिए हमने ८. १२ लाख टन एडीशनल प्रोडक्शन की व्यवस्था की थी। उसके मुकाबले में करीब २ लाख टन एक्स्ट्रा मतलब एडीशनल प्रोडक्शन राजस्थान के अन्दर बढ़ेगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक। उसी प्रकार रुई के क्षेत्र में २.६५ के बजाय इसमें कुछ कम होगा, २.३५ लाख बैल्स के करीब होगा। शूगरकेन में ०.६ लाख के बजाय ०.६ लाख टन होगा। इसमें भी ज्यादा होगा और ऑइल सीड्स में ०.४० लाख टन के मुकाबले में २.७६ लाख टन्स होंगे, तो इसमें भी ज्यादा होगा। उसी प्रकार कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हमने यह उद्देश्य निश्चित किये थे कि ३० प्रतिशत गांवों के अन्दर सहकारिता को हम पहुँचाएं। उसके मुकाबले में ४० प्रतिशत गांवों तक हम टार्गेटस को एचीव करेंगे और १५ प्रतिशत रूरल पोपुलेशन को कवर करने के बजाय २० प्रतिशत पोपुलेशन को हम कवर करेंगे। पॉवर के अन्दर हमारा टारगेट था कि हम ६२,१८० किलोवाट पॉवर एडीशनल दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे यहां पर हम इसका उत्पादन करेंगे। इसमें अगर भाखरा से पूर्ण रूप से पॉवर मिलेगी तो हम आशा करते हैं कि यह जो हमारा टार्गेट है वह करीब करीब पूरा हो जायगा, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक इतनी पॉवर एवेलेबल होगी। यहां पर मैं यह भी निवेदन कर दूं तो उचित होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान की स्थिति पॉवर की दृष्टि से यह थी कि हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी कुल मिलाकर ३४,६०० किलोवाट थी जिसमें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में आयें तो उसमें डीटोरियोरेशन और दूसरी तरह से कम हो जायगी। उसको देखते हुए उस कैपेसिटी में हमको और ६,००० किलोवाट के आसपास एवेलेबल होगी जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में थी उससे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादातर जो पॉवर एवेलेबल होगी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के एफर्ट्स की वजह से होगी। पुराने एफर्ट्स के परिणाम स्वरूप ६,००० किलोवाट के आसपास वह पॉवर एवेलेबल होगी।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्री के अन्दर ६ इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने की बात थी, उसके मुकाबिले में ३ पूरे हो जायेंगे, ५ करीब करीब पूरे होंगे और ६ पर और काम शुरू हो चुकेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नई सड़कें बनाने का २७०८ मील का उद्देश्य था। उसके बजाय २,१७० मील बनेंगी, क्योंकि ज्यादा वेजेज़ होने के कारण २,७०८ मील पूरी न बन पायेगी और २,१७० मील ही होंगी। और जो इम्प्रूवमेंट रोड्स में करने की बात थी १,६४२ माइल में उसके बजाय इम्प्रूवमेंट करने में हम एक्सीड करेंगे और १,६७२ मील सड़क में इम्प्रूवमेंट कर लेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में ५,००० प्राइमरी स्कूल्स खोलने की व्यवस्था हमने की थी उसके बजाय

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

७ ०६० खोलेंगे। अगर २,५०० लगाने थे जिसके बजाय ४,६४८ लगेंगे मिडिल स्कूल २८२ खोलने थे जिनके बजाय ६६३ खुलेंगे। हाई स्कूल्स और हायर सेकन्डरी स्कूल्स११४खोलने थे जिनके बजाय २४२ खोले जायेंगे। डिग्री कॉलेजेज ३ खोलने थे उसके बजाय १६ नये डिग्री कॉलेजेज खोले जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन पोलीटेक्निक स्कूल्स खोलने थे उसके बजाय ५ पोलीटेक्निक स्कूल्स खोले जायेंगे।

मेडिकल में ७ टी. बी. क्लिनिक खोलने की व्यवस्था की थी वह पूरी हो जायगी। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स १३४ खोलने थे उसके बजाय हैल्थसेन्टर्स खोले जायेंगे।

इर्रिगेशन में ११ लाख एकड़ का टार्गेट एचीव करना था उसके बजाय ५.४ लाख एकड़ का टार्गेट एचीव कर सकेंगे। इसमें रिडक्शन होगा। इस बारे में हमने जो टार्गेट रखा था उसमें कुछ रुकावटें आने के कारण सेकन्ड फाइव इयर प्लान में हम उसे पूरा नहीं कर पायेंगे।

इन चीजों में, दूसरे क्षेत्रों में जैसे उद्योग के क्षेत्र में विशेष तौर से दूसरी पंचवर्षीय योजना के पिछले वर्षों में कुछ प्रगति हुई है। जैसा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है, दूसरी पंच वर्षीय योजना में टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज में खास तौर पर आघात लगा है। कई जगह टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ बन्द हो गई हैं और कई जगह चल रही हैं असंतोषजनक स्थिति में। कुछ जगह स्क्रेप करना पड़ा है और कुछ जगह गवर्नमेंट ने खुद ने टेक्सटाइल मिल्स को अपने खुद के कंट्रोल में लिया है और चलाई जा रही हैं। जो स्क्रेप डिक्लेअर की गई हैं या जहा पर सिलन्डर्स यूज़ नहीं हो रहे थे वहां भी चार नये युनिट्स लगाने की व्यवस्था की गई है। उनमें से एक युनिट तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जायगा और बाकी तीन युनिट्स १९६२ के शुरू में या अन्त तक शुरू हो जायेंगे।

कोपर स्मेल्टर के बारे में प्रोस्पेक्टिव साइड का काम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने अलवर के खो दरीबा और खेतड़ी से किया है। जो जानकारी की गई है उसके आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्मेल्टर लगाने की योजना बनाई गई है। जिन्क स्पेल्टर के बारे में दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाइसेन्स और फॉरेन एक्सचेन्ज देने की सुविधा देने का निर्णय किया जा चुका है और इसी योजना में शुरू होगा और आशा करते हैं कि १९६२ के शुरू में या अन्त तक प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा।

इसी प्रकार से नायलोन फैक्ट्री, वेगन फैक्ट्री और दूसरी मेटल फैक्ट्रीज़ बालबेअरिंग फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ा है।

माइनिंग साइड में प्रोस्पेक्टिंग का काम शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिप्सम के बारे में विशेष तौर से नागोर के पास काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने की आशा है, इसकी जांच हुई है। इसी प्रकार से लिगनाइट और क्लोराइड जो रेअर मिनरल्स हैं उनकी भी जानकारी की गई है और आगे जानकारी की जाकर इसकी योजना बनाई गई है।

यह मोटे तौर से मैंने आपके सामने

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

निवेदन किया। इन क्षेत्रों में जो खास काम हुआ वह संक्षेप में बताया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य तय किया था कई क्षेत्रों में इस उद्देश्य की पूर्ति से कहीं ज्यादा कामयाबी हासिल की। एक-दो क्षेत्रों में जैसा कि मैंने बताया, खास तौर से सड़कों में, मजदूरी बढ़ जाने से कुछ कम काम हुआ और इर्रिगेशन साइड में जो पोटेन्शियलिटीज़ डेवलप हुई उनका पूरा फायदा तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिलेगा। क्योंकि देर से प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे इसलिए अन्तर आया है। कृषि के क्षेत्र में आगे जाकर उत्पादन में काफी फर्क पड़ेगा। जो साधन कुओं वगैरह के बढ़े उनसे भी कृषि में काफी इम्प्रूवमेन्ट हुआ। कहीं कहीं पर डब्बल क्रोप होने लगी और जो सुधार हुए फरटीलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह में उनसे उत्पादन में वृद्धि नजर आ रही है।

अब इन सारी चीजों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें यह भी देखना होगा, अध्यक्ष महोदय, कि सब का प्रभाव आर्थिक दृष्टि से राजस्थान पर क्या पड़ता है। अब तक जो कुछ साधन हमारे समक्ष उपलब्ध हो सके उन्हें हम टेन्टिटिव समझ कर चलें। मैं उनको इसलिये टेन्टेटिव कहता हूं कि अभी और जांच की जा रही है जो बहुत जरूरी है। लेकिन जो फिगर्स उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार दूसरी योजना में यह मानना पड़ेगा कि पर केपिटा इनकम २६४ राजस्थान में होगी और उसके लिये जब दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उससे पहले २४४ पर-केपिटा इनकम थी। उससे बढ़ कर २६४ हुई। यह एडीशन दूसरी योजना के अन्त तक हुआ। इसके मुकाबले में ऑल इंडिया पर-केपिटा इनकम २८५ योजना के प्रारम्भ में बताई गई थी और योजना के अन्त तक ऑल इंडिया पर-केपिटा इनकम ३०५ होगी। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान की इनकम पर-केपिटा ऑल इंडिया पर-केपिटा इनकम के मुकाबले में १३.५ राजस्थान की इनकम कम होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में।

अब इन चीजों को मैंने आपके सामने इसलिये रखा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह विचार कर सकें कि आर्थिक दृष्टि से और रिसोर्सेज़ की दृष्टि से हमारी क्या स्थिति है और ऑल इंडिया बेसिस पर हम कहां स्टेन्ड कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर ख्याल करते हुए हम सोचें।

अध्यक्ष महोदय, इस बीच में एम्पलॉयमेंट के बारे में जो स्टडी की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ३१-३-५६ से ३१-१२-५८ के बीच में पब्लिक सेक्टर में स्टडी ग्रुप ने जो स्टेडी की उसके आधार पर मुझे सूचित करते हुए हर्ष होता है कि राजस्थान में जो पर्सेन्टेज पहले ढाई वर्षों में आया है वह ४२.५ है और यह ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा है। जो बाद में ढाई वर्षों में एडीशनल बढ़ोत्तरी हुई है उसके फिगर्स हमारे सामने नहीं हैं इसलिये मैं उसकी चर्चा में पड़ूं, यह उचित नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो एम्पलॉयमेंट हुआ है उसकी जानकारी हमारे सामने नहीं है। प्लानिंग कमीशन में लेबर एम्पलॉयमेंट डिविजन है उसकी तरफ से इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है इसके आंकड़े जब उपलब्ध हो जायेंगे और चैक-अप कर लेंगे तब निवेदन करूंगा।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

इन आंकड़ों के बारे में निवेदन करने के बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस भूमिका में हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना बनानी है। जो लिट्रेचर और पेपर्स आपको सक्युलेट किये गये हैं उनके आधार पर जहां तक हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा करें, मैं समझता हूं उचित होगा। हमारे रिसोर्सेज़ की पोज़ीशन क्या है, उस पर विचार करें। रिसोर्सेज़ के लिहाज से जो अब तक सोच विचार हुआ उसके अनुसार अब तक हमारा यह ख्याल है कि राजस्थान में हम कुल ८१.७७ करोड़ के रिसोर्सेज अपने तौर से थर्ड फाइव इयर प्लान के लिये कॉन्ट्रिब्यूट कर सकेंगे। इसके कुछ ब्रोड आइटम्स निवेदन करूं कि इसमें एडीशनल टैक्सेशन के जरिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के ५ वर्षों में २० करोड़ रुपये उपलब्ध कर सकेंगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन का लेवल है उसका जो बेलेन्स होगा वह ११.९३ करोड़ होगा और जो केपिटल अकाउन्ट है वह १४.८६ करोड़ है और पब्लिक लोन्स के जरिये २५ करोड़, स्माल सेविंग्स के जरिये १० करोड़, इस प्रकार ८१.७७ करोड़ का कॉन्ट्रिब्युशन राजस्थान करें। इस बात को सामने रखते हुए हमने एक आधार सोचा है थर्ड फाइव इअर प्लान बनाने के लिए कि हम आगे किस प्रकार का और कितना बड़ा प्लान बनायें। उसके लिए आवश्यक होगा सोचना कि रिसोर्सेज़ के लिहाज से राजस्थान के अन्दर कितना, क्या वह है। जैसा मैंने निवेदन किया, ये टेन्टेटिव फिगर्स हैं, क्योंकि इसके सम्बन्ध में, अभी अभी जब फिगर्स सक्युलेट हुए उसके बाद प्लानिंग कमीशन में चर्चायें हुई, उससे भी आंकड़ों में परिवर्तन आयेगा और फाइनल डिस्कशन इस पर बाकी है, इसके अन्दर और भी रद्दोबदल हो सकते हैं। जैसे लॉ-पेड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में हमारा कमीटेड एक्सपेन्डीचर है उसको लगाया है पांच करोड़ के करीब, यह समझ कर कि सेन्टर असिस्टेन्स कर दे थर्ड फाइव इअर प्लान में। अभी यह निश्चित् नहीं है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेन्स के तौर पर कन्ट्रीब्यूसन हो या नहीं। उसी प्रकार थर्ड फाइव इअर बना लिया जायेगा, उसमें, चम्बल और भाखरा के अन्दर, अगर चम्बल को समझा जायगा कि गांधी सागर और कोटा बैरेज का काम खत्म होने की वजह से इसके अकाउन्ट्स क्लोज़ कर दिये गये हैं, यह मान कर चला जाय तो उसका इन्ट्रेस्ट आ सकता है और अब तक जैसे इन्ट्रेस्ट केपिटेलाइज़ करके लोन में एड किया जाता था उसको अब रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर साइड पर ला सकते हैं। उसकी वजह से भी हमारे रिसोर्सेज़ में कमी हो सकती है, ऐसा अभी मान कर चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा, फर्स्ट इन्डीकेशन्स ऐसे हैं कि उनको हमें एक्सपेन्डीचर साइड पर डेबिट करना पड़ेगा और इस वजह से रिसोर्सेज़ साइड पर असर पड़ सकता है। लेकिन आखिरी चर्चा होने के बाद अन्तिम रूप से क्या फिगर्स बनते हैं, यह देखने की बात है। तो मैं निवेदन करूं कि ८१.७७ करोड़ के जो नये फिगर्स रखे हैं और जो सक्युलेट किये हैं उनको आधार मान कर चलें, उस आधार पर हम सारा का सारा इसको बनायें तो क्या पोज़ीशन बनती है और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा जो

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

इन्डीकेशन्स बीच के दिनों में मिले उनको देख कर यह मान कर चलते हैं कि जहां एक तरफ हमारा एग्ज़िस्टिंग टैक्सेशन लेवल ११. ६८ करोड़ बेलेन्स है फाइनेन्स करने के लिए थर्ड फाइव इअर प्लान में वह फिगर कन्वर्ट हो सकता है माइनस के अन्दर। यदि डेबिट साइड में ले जायं, जो इन्ट्रेस्ट वगैरह शुरू में हैं तो डेबिट साइड से थर्ड फाइव इअर प्लान शुरू होगा। हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वे पूरे न हों, तो जो नये रिसोर्सेज़ हम रेज़ करें उनको काउन्ट करके चलना होगा, जो हमारे थर्ड फाइव इअर प्लान के लिए उपलब्ध हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम विचार करें कि हमारे राजस्थान के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या होगा। जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो नेशनल पर-केपिटा एवरेज है उससे १३.६ पर्सेन्ट, जैसा मैंने आपसे कहा, राजस्थान पीछे रहता है। अब थर्ड फाइव इअर प्लान के एन्ड में क्या स्थिति बने और किस प्रकार से हमारा इन्वेस्टमेंट हो थर्ड फाइव इअर प्लान के लिए, उसके बारे में हमने अपनी तरफ से, नेशनल कौन्सिल ऑफ इप्लाइड रिसर्च, जिसमें लोकनाथन् काम करते हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उसको इस काम को सौंपा था कि राजस्थान के बारे में सारी कन्डीशन्स को देख कर यह बतायें कि राजस्थान के अन्दर इन्वेस्टमेंट का पेटर्न क्या हो और कितना इन्वेस्टमेंट थर्ड फाइव इअर प्लान में होना चाहिए; जिससे जो ऑल इन्डिया एवरेज और राजस्थान के एवरेज में गेप है उसमें कमी करते हुए उसको रीच कर सकें। उन्होंने जो अपनी तरफ से फिगर्स को देखा और एड मिला कर देखा तो थर्ड फाइव इअर प्लान में १०,२०० करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनता है। उसमें टोटल करेन्ट और आउट लेज़ लेकर करीब ११,२५० करोड़ के बन जाता है। १०,२०० करोड़ के प्लान को लें और राजस्थान की पोपुलेसन जो ४.५ पर्सेन्ट ऑफ टोटल पोपुलेशन भारत की है उस आधार पर राजस्थान के अन्दर टोटल इन्वेस्टमेंट ४५६ करोड़ का होना चाहिए, सिम्पल एन्ड प्रपोर्शनेट बेसिस पर, जिसको हम कहें, ऑल इंडिया और राजस्थान की पोपुलेशन का बेसिस है। उतना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करते हैं, तो उसका मतलब है कि जो गेप है उसके अन्दर परिवर्त्तन नहीं होता है, more और less करीब करीब उसी स्थिति पर पहुँच जाते हैं। हम उस गेप को कम करने के प्रयत्न करें, जो प्रेक्टीकल हैं, उसके साथ साथ उतना करना आवश्यक प्रतीत होता है।

मैंने जैसा कहा, एक्सपर्ट्स को यह ओपीनियन है कि थर्ड फाइव इअर प्लान के अन्दर राजस्थान में कम से कम ४०४ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर इतना होगा तो उसके बाद राजस्थान ३३१ पर-केपिटा एवरेज पर पहुंचेगा। इस एवरेज पर राजस्थान थर्ड फाइव इयर प्लान के बाद पहुँच सकता है। उस मौके पर, जब थर्ड फाइव इयर प्लान बनाया गया उसको देखते हुए ऑल इंडिया एवरेज ३६५ तक पहुंच जायेगा। इसका मतलब यह है कि ४०४ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके भी ऑल इंडिया एवरेज तक नहीं पहुँच सकते हैं, ३३१ तक पहुँच सकते हैं, जब कि ऑल इंडिया एवरेज

[redacted]

# Page No.38



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

३६५ होगा। इस प्रकार जो १३.६ का गेप है यह गेप रिड्यूस होकर ६.७ पर्सेन्ट तक आ सकता है यनी ४ पर्सेन्ट के करीब हम गेप में कमी कर सकते हैं इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद। जो इन्वेस्टमेंट ४०४ करोड़ का मैं कहता हूं उसका मतलब यह है कि जो स्टेट इन्वेस्टमेंट है, वह इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और वह इसमें आ गया है। वह सिर्फ स्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसमें हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ जाता है, जो इकॉनोमी इम्पेक्ट है, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। उसके बाद ४०४ करोड़ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किये हैं, उनके अनुसार २१२ करोड़ के करीब अलग अलग मदों के अन्दर हैं और ४५ करोड़ हमने रखे हैं राजस्थान केनाल के लिए। वह सब मिला कर २५७ करोड़ के आसपास होता है। उसको हम २५७ करोड़ मान लें। उसमें यह ख्याल किया जाता है कि २५७ के अन्दर, स्टेट सेक्टर, राजस्थान केनाल दोनों शामिल हैं। हम राजस्थान केनाल को सेन्ट्रल सेक्टर भी मान लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जनरल यह होगा जो इन्वेस्टमेंट होगा और करेन्ट आउट लेज़, दूसरी चीजें हैं, जिन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो यह मान कर चलें कि २५७, कितना कहा मैंने; २५७ करोड़ के अन्दर से २१४ करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेन्शियल आता है, जो है। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ख्याल है कि १५० करोड़ के करीब हम मान कर चल सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स के अन्दर, जिसमें एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्रीज और और सेक्टर्स हैं। उसका १५० करोड़ का इन्वेस्ट में जोड़ दें तब जाकर १३.६ के करीब बीच का गेप रहता है जिसे पब्लिक सेक्टर के जरिये पूरा होना चाहिये। तब जाकर ४०४ करोड़ के इन्वेस्टमेंट की पिक्चर बनती है सारी उसके जरिये।

जैसा मैंने निवेदन किया ६.७ का मार्जिन रह जाता है, थर्ड फाइव इयर प्लान के एन्ड में और जो ऑल इंडिया एवरेज होगा और जो राजस्थान का एवरेज बनेगा उन फिगर्स को वर्क आउट करने के बाद हमें देखना होगा कि जो राजस्थान के लिए स्टेट प्लान बना है उसके लिए हम किन चीजों के बारे में विचार करें।

पहली बात मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो एक सिंगल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सवाल है वह राजस्थान केनाल पर आता है, ४५ करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें अपने यहां से करना है। अभी प्लानिंग कमीशन से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है वह है पाउन डेम पर। जैसा पंजाब की तरफ से सूचना भेजी गई है कि यह ख्याल किया जाता है कि ३२ करोड़ पाउन डेम के अन्दर, जो वाटर सप्लाई करेगा उस पर खर्च किया जायगा। यह भी मैं निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि पाउन डेम के बारे में यहां पिछले सदन में काफी चर्चा हुई कि राजस्थान केनाल का ठीक तरह से लाभ पहुँच सकता है, उसके लिए इसकी आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि इर्रिगेशन मिनिस्टरी ने पाउन डेम के बारे में निर्णय कर लिया है कि पाउन डेम जल्दी बनाया जाय, जिससे सिंचाई को ज्यादा लाभ पहुँच सके। लेकिन मैं अब

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आशा करके चलता हूं कि पाउन डेम पर वर्ल्ड बैंक भी लोन देगा इसलिये वह कम्पलीट हो जाएगा और हमारे स्टेट सेक्टर में आने का प्रश्न नहीं उठता। हम इसी बात पर प्रगतिशील रहें कि राजस्थान केनाल पर खर्च करने का प्रश्न है। राजस्थान केनाल पर जो खर्चा किया जाता है उसका रिटर्न तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं के बराबर होगा। पहले पेरीनियल इर्रिगेशन की संभावना है वह ५ या ६ लाख एकड़ के होगी जब कि योजना ५० से ६० लाख एकड़ की है और वह भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तीसरे या चौथे साल में उसका पेरीनियल इर्रिगेशन उपलब्ध हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही राजस्थान केनाल का काम शुरू करें तो बहतर होगा। वह हम कर नहीं सकते क्योंकि जितना बड़ा काम होता है उसमें समय लगता है और लगेगा।

अब प्रश्न यह है कि आया हम अपने रिसोर्सेज़ में सोशियल सेक्टर को भी लें ? तो शिक्षा में हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर ऑल इन्डिया में ८० पर्सेन्ट है तो यहां पर ७० पर्सेन्ट रखना चाहते हैं और इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काफी खामियें हैं। अगर ऐसी हालत में राजस्थान केनाल पर कम खर्च करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसका भार स्टेट सेक्टर में रहता है। स्टेट सीलिंग के तौर पर इसको रखना जरूरी है। स्टेट की सीलिंग फिक्स है और राजस्थान चेनल की वजह से इन्वेस्टमेंट हो तो हमारी सीलिंग फिक्स करने के लिये इसको भी हमारा पार्ट समझना चाहिये क्योंकि इससे सारे भारतवर्ष को लाभ होता है और सारे राजस्थान केनाल का पार्ट राजस्थान प्ले करता है। इसलिये इस प्रोजेक्ट को हमें स्टेट पर्पज़ के लिये मान कर प्योरली स्टेट सेक्टर पर लेते हैं तो बड़ा असर पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि स्टेट सेक्टर में रखने का निर्णय अंतिम है। लेकिन राजस्थान केनाल के लिये वे प्रोविज़न चाहते हैं, हमारी दूसरी आवश्यकता को देखते हुए हमारी ओरीजिनल सीलिंग को देखते हुए ओवर एन्ड अबव होगा।

जैसा मैंने आपको अर्ज किया राजस्थान में प्लान बनाया है। जैसा आपको विदित ही है भारतवर्ष की १०, २०० करोड़ की योजना है उसमें जो स्टेट के लिये एलोकेशन है उसका टोटल ३, ६०० करोड़ रुपया होता है। हम १०, २०० करोड़ के फिगर्स हैं उससे किसी प्रकार भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़े। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के लिये ८५० करोड़ रुपया, इर्रिगेशन और पॉवर के लिये १,४४५ करोड़ रुपया, ट्रान्सपोर्ट के लिए २२५ करोड़, इन्डस्ट्रीज और माइन्स के लिये १८० करोड़,सोशियल सर्विसेज़ के लिये ६५० करोड़; इस प्रकार कुल ३,६०० करोड़ का टोटल प्लान बनाया है। अब इस ३,६०० करोड़ के अन्दर हम डिस्कशन अभी करेंगे जो आपको एलोकेशन दिया है वह ३,६०० करोड़ का पार्ट है। इसलिये हम यह समझ कर डिस्कशन करें कि हमारा स्टेट प्लान क्या है। जब हम इसको ध्यान में रखेंगे तो

# Page No.40



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हम आसानी से इस पर विचार कर सकेंगे। सेन्टर सेक्टर में इन्डस्ट्रीज़ और माइन्स में १८० करोड़। रेलवे और दूसरी साइड में काफी बड़ी मात्रा में रकम रखी है। जैसा मैंने कहा कि पूरे प्लान में ४ हजार करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर का है। जब हम ३,६०० करोड़ का इसमें से निकाल लेते हैं तो बाकी का प्राइवेट के लिये रह जाता है और जो पब्लिक सेक्टर में होगा उसके फिगर्स निकाल सकते हैं। यह सारे प्लान की पोज़िशन है।

अब हमें यह देखना है कि हमारा प्लान किस टार्गेट पर बनेगा ? हमारा क्या आधार बनेगा जिससे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको प्राप्त हो सके ? यदि ३,६०० करोड़ पर पर-कैपिटा के हिसाब से हो तो ४.५ पर्सेन्ट पोपुलेशन के हिसाब से १६६ करोड़ होता है, वह तो उचीत नहीं होगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारा देश कई सेक्टरों में पिछड़ा हुआ है। आप शिक्षा को ले लें। शिक्षा में बहुत बेकवर्ड है, रूरल वाटर सप्लाई को ले लीजिये इसमें भी बहुत बेकवर्ड है। अर्बन वाटर सप्लाई में भी बेकवर्ड है। इसलिये इसके लिए भी हमको कुछ करना होगा। इसलिये प्रोपोर्शनेटली वर्क आउट नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ज्यादा हो। एक तरफ राजस्थान केनाल का भी प्लान बनाया गया है। राजस्थान में चम्बल, भाखरा और दूसरे स्पिल ओवर हैं वे १६६ करोड़ में कवर नहीं हो सकते। यह बिल्कुल इम्पोसिबल फिगर हैं, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऑल इन्डिया एक्सपेन्डीचर के लिए प्लान बनाया गया है उसके रिसोर्सेज़ के लिए ५५० करोड़ रुपयों का फिक्स्ड सेन्टर में एडीशनल टेक्सेशन का रखा है। ५५० करोड़ एडीशनल टेक्सेशन के लिए कन्ट्रीब्यूट करें; इसको भी ध्यान में रख कर इसके बारे में चर्चा की जावे। इसको पूरा करने के लिए जैसा मैंने कहा ५०४ करोड़ के अलॉटमेंट का प्रश्न है। हमें कितना करना है ? यह सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम विचार करें।

कुछ चीजों के बारे में हमने सोचा कि एडीशनल फूड प्रोड्यूस का प्रश्न है। हम यह चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में १८ लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन हम करें। क्योंकि इसको आधार बना कर हम एक्सपेन्डीचर पर पहुँच सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल इण्डिया सेक्टर में भी जो प्रोविजन दिया गया है उसको भी निगाह में रखें। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए १८ लाख टन फूड प्रोडक्शन में वृद्धि हो। मैं इसके सारे विस्तार में जाना नहीं चाहता कि सेन्टर आदि में क्या होता है।

दूसरी बात है इन्डस्ट्रियलाइजेशन की, मिनरल्स के डवेलपमेंट की। यह स्पष्ट है कि मिनरल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले बिजली की आवश्यकता होती है कि बिजली का उत्पादन बढ़े, इसमें हम पहले से ही, शुरू से ही पिछड़े हुए रहे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने ६२ हजार किलोवाट की एडीशन योजना की है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम चाहते हैं कि ३ लाख ४०

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हज़ार किलोवाट एडीशनल ऐड किये जावें। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिये ४५ करोड़ की आवश्यकता होती है। पॉवर के लिए ४५ करोड़ की आवश्यकता है वह तो है ही लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आशा की जाती है कि वह भी इसमें कितना पॉवर दे सकते हैं। यह पॉवर इसके लिए आवश्यक होगा। पॉवर के बिना बड़ी बड़ी हेवी इन्डस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। बड़ी–बड़ी हेवी इन्डस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी हों तो पॉवर स्ट्रेन्थन होनी चाहिये ताकि उन लोगों की जरूरत को हम पूरा कर सकें। यदि यह सम्भव होता तो, मैं समझता हूं, हम इससे भी ज्यादा करना चाहते। जैसे अलग अलग हैड्स में रखा है सब को यह फीलिंग होगी कि और ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिये था। लेकिन उसकी सम्भावनायें कम मालूम होती हैं। सदन में चर्चा होने के बाद यह प्लानिंग कमीशन में जावेगा। सदन की राय होने से गवर्नमेंट को भी बल मिलेगा और साथ ही जानकारी भी होगी। मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी तरह से विचार हो।

शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, अध्यक्ष महोदय, औसत जहां २३.२४ प्रतिशत के आसपास थी वहां तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५० प्रतिशत। जहां तक ६ से ११ ईयर्स एज ग्रुप का सम्बन्ध है उसकी व्यवस्था करने में कामयाब होंगे। ५० प्रतिशत है। यही नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पोन्सिबिलिटी है उसकी यह पूर्ति करता है; बल्कि हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी यह है कि सब प्रकार की जहां तक प्राइमरी और एलीमेन्टरी एजुकेशन का सवाल है, हम व्यवस्था करें। लेकिन लड़कियां की शिक्षा के बारे में, हमारी जो आज की सोशियल कन्डीशन्स हैं और दूसरी बातें हैं उनको देखते हुये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६० प्रतिशत लड़के और ५० प्रतिशत लड़कियों स्कूलों में पहुँच जावें और औसत हम ७० प्रतिशत एचीव करें। ५० से ७० प्रतिशत तक हमारी तीसरी योजना में हम पहुंच जावें। इस प्रकार ११ से १४ वर्ष एज ग्रुप में ३० प्रतिशत और १४ से १७ तक १५ प्रतिशत पहुँच जावें। यह एक मोटा उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है।

उसी प्रकार से, अध्यक्षजी, लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये सुविधायें प्राप्त हो सकें, उन पर सोच विचार किया है और यह ख्याल किया है कि राजस्थान के अन्दर ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे ६ हजार की आबादी के बीच में, चाहे आयुर्वेदिक हो या मेडिकल, कोई न कोई फैसिलिटी उपलब्ध करें जिससे रूरल एरिया में जहां आज २० हजार की पोपुलेशन में फैसिलिटी नहीं है, वह गांव में ज्यादा फैल सके। इसलिये मेडिकल और आयुर्वेद में प्रोविजन किया है। दो और मेडीकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था है। आज हमारे यहां प्राईमरी हैल्थ डिस्पेन्सरी होते हुए भी डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। थर्ड फाइव ईयर के बाद जो कुछ करना चाहते हैं उसके बाद भी शोर्टेज होनेवाली है, कॉलेज खोलने वाले हैं, तो भी फोर्थ, फाइव ईयर प्लान में शोर्टेज मिलेगी। पूरी तो क्या, थर्ड फाइव इयर प्लान में तो उन कॉलेजों से हमको कुछ भी सुविधा नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिलने वाली है, आगे जाकर कुछ मिलेंगी। आगे जाकर आवश्यकतायें इस क्षेत्र में बढ़ती हैं और बढ़ती जावेंगी, यदि उनकी भूमिका अभी से ही बनालें तो हमको आगे जाकर दिक्कत न हो और डॉक्टर्स उपलब्ध हो सकें।

जहां पीने के पानी का सवाल आता है यह व्यवस्था करने की कोशिश की है कि ४०० से ६०० की आबादी में सेनीटरी वैल्स उपलब्ध हो सकें। उससे ऊपर जितनी आबादी का लक्ष्य था वहां पर अरबन वाटर सप्लाई मिल सके और मलेरिया कम्पलीटली इरेडिकेट किया जाय। उसके टार्गेट्स इसमें हों, उसके लिए व्यवस्था की है। ८० प्रतिशत तक रूरल पोपुलेशन को कवर-अप किया जाय; इस प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी अलग अलग टार्गेट्स रखे हैं।

जहां मैंने निवेदन किया, आंकड़े तो डिटेल्स में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जो माननीय सदस्यों ने देखे होंगे और आवश्यकता हुई जानकारी देने की तो डिबेट के अन्त में मैं अपनी तरफ से बात कहूँगा, उन चीजों को रखूंगा।

मैं समझता हूं कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के अन्दर जहां कई क्षेत्रों में प्रगति की है वहां इस बात की बड़ी उल्लेखनीय घटना हुई है जिससे हमारे प्लान, सारी इकॉनोमी और यह कहना चाहिये कि हमारे समाज पर असर होता है, वह हमारी विकेन्द्रीकरण की योजना है जिसके द्वारा राजस्थान के गांव गांव में हम अपनी तरफ से लोगों में श्रम और दूसरे तरीकों से अपने रिसोर्सेज़ दें और डवेलपमेंट की रफ्तार तेज करें। उसके माने में एक इम्पीटस दिया और उसके साथ, अध्यक्ष महोदय, यह सब को ही विदित है कि राजस्थान के अन्दर यह तीसरी योजना का प्रारूप तैयार किया है उस पर जहां प्लानिंग बोर्ड में अलग अलग ग्रुप में चर्चा होगी, इस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में और क्या जानकारी और सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं; उसके बारे में पंचायत और पंचायत समितियों के स्तर पर उस पर चर्चा की गई है। पंचायत समितियों में जो विकेन्द्रीकरण योजना भेजी गई उन पर पंचायत समितियां चर्चा करें–उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो जानकारी पंचायत समितियां और जिला समितियां द्वारा भेजी है उसका असर तृतीय पंचवर्षीय योजना पर पड़ेगा; यह निश्चित तौर पर मान कर चलना चाहिये।

बीच में मैंने कहा था कि १५० करोड़ के करीब प्राइवेट सेक्टर में हो, उसमें लोकल बॉडीज़ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो पब्लिक सेक्टर के बारे में भारत सरकार सोच-विचार करे। हम भी सदन में और बाहर राजस्थान में पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है? समय समय पर विचार करते रहे हैं। जहां तक चर्चा कर रहे हैं कॉपर के बारे में १० हज़ार टन खेतड़ी में स्मेलटर लगे भारत सरकार की ओर से, यह तय किया है। हिन्दूमल कोट से गंगानगर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन लगे। उदयपुर से हिम्मतनगर रेलवे लाइन पब्लिक सेक्टर में लगे। और भी दूसरे दूसरे काम पब्लिक सेक्टर में होंगे। अभी नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि जिससे कितना

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

डेवलपमेंट होगा, लेकिन इससे काफी डेवलपमेंट होने वाला है। लिग्नाइट पलाना में उपलब्ध है, जिसकी जानकारी करनी है कि कितनी डिपोज़िट्स उपलब्ध हैं। उसको पब्लिक सेक्टर जैसे लागू किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार की इस के बारे में यह राय थी कि कुल मिला कर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स लेने चाहिये पब्लिक सेक्टर में उस लिहाज़ से यह छोटा प्रोजेक्ट है और स्टेट ही इस प्रोजेक्ट के लिए देखभाल करे और इसको चलाये। हमने इस प्लान में जो कुछ प्रोविज़न किया है यह चाहते हुए भी पब्लिक सेक्टर में यह होता तो अच्छा होता। अब भी इसको लागू किया जाय तो हम पसन्द करेंगे। लेकिन नहीं लागू किया तो लिग्नाइट का डेवलपमेंट न हो तो यह उचित नहीं है क्योंकि पॉवर और दूसरी चीजों के डेवलपमेन्ट के अलावा फर्टीलाइज़र फैक्टरी हनुमानगढ़ में लगाने का करीब करीब तय हो चुका है, शंका की बात नहीं है। उसमें लिग्नाइट की आवश्यकता है। इन सब चीजों को देखते हुए लिग्नाइट जरूरी है। पिग आइरन का जहां सवाल आया तो उसके लिए लिग्नाइट आवश्यक है। उसको ओपन कास्ट माइनिंग करने के लिए व्यवस्था की जाय। लिग्नाइट बाहर से इम्पोर्ट होता है उसको स्टेट सेक्टर में लाने की कोशिश की है।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, समय समय पर इन चीजों से जो पॉवर जेनरेट करेंगे डेम्स वगैरह से उसके अलावा एटोमिक पॉवर स्टेशन के जरिये से राजस्थान को पॉवर मिले, उसके बारे में बातचीत करते रहे हैं और मुझे आशा है और जो अब तक जानकारी हुई है, ऑफिशियल नहीं, मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि एटोमिक पॉवर स्टेशन तीसरी योजना में राजस्थान को दिया जावेगा; ऐसा मानना चाहिये। उसके मिलने से भी तीसरी योजना में एडीशनल पॉवर अवेलेबल नहीं होगा, वह तो फोर्थ योजना में होगा। उसके लिए पहले से कुछ करना जरूरी है। उसी तरह पोंग डेम से भी पॉवर मिलेगा। वह भी फोर्थ इयर में मिलेगा, उसके लिए भी प्लान जरूरी हो जाता है।

(१ म० प०)

लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि जो व्यवस्था हमने इसमें की है जैसे प्रताप सागर बांध पूरा करने की आदि तो इसके लिए निश्चित तौर से मैं यह आवश्यक मानता हूं कि राजस्थान में इस वक्त जिसमें हम यह आशा करके चलते हैं कि ये चीजें राजस्थान में जल्दी हों, इसके बारे में दूसरी पार्टीज़ से बातचीत की गई है। इनमें काफी पॉवर कन्ज्यूम होती है इसलिये हमारे यहां राजस्थान में कास्टिक सोडा, पी० वी० सी० केलशियम कार्बोइड की इन्डस्ट्री लागू हो; इस सम्बन्ध में हमारे यहां काफी चर्चायें हो चुकी हैं। इसकी एक्ज़ीक्युशन के बारे में हमारी जो अब तक बातचीत हुई है उसके अनुसार जितना भी पॉवर हमारे यहां से जेनरेट होगा सारा कन्ज्यूम इसी जनरेशन के साथ हो जाने वाला है। आवश्यकता और ज्यादा रहेगी, आगे से आगे गेप न पड़ जाय और फोर्थ प्लान के लिये भी कहां कहां से पॉवर अवेलेबल हो सकती है; इसका भी हमें बन्दोबस्त साथ में ही करना है।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

माइका प्रोजेक्ट को जो लिया जा रहा है जिससे जो कन्टीनुअस प्रोसेस है इसका भी हमें ध्यान रखना है ताकि इस ओर जो हमारा इन्डस्ट्रियलाइजेशन है वह रुक न जाय।

राजस्थान के अन्दर बहुत सारी जमीन है। इस वजह से यहां पर इन्डस्ट्रियलाइ-जेशन नहीं होना चाहिये। क्योंकि हमारे यहां जमीन ज्यादा है इसलिये इरिगेशन और एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है इसलिये औद्योगीकरण पर खर्चा क्यों हो; इस प्रकार की भी एक लोगों में भावना है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें स्पष्ट तौर से यह समझ कर चलना है कि केवल राजस्थान की दृष्टि से ही हमें सोचना नहीं है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में न सिर्फ हमें राज-स्थान की कमी को ही पूरा करना है बल्कि देश में जो खाद्यान्न की कमी है उसको भी पूरा करने के लिये राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना है और काम करना है। यह आप निश्चित मानिये कि राजस्थान केनाल के लिये जेनरेशन को दस साल तक सेक्रीफाइस करने होंगे। जहां हम इस प्रकार से सेक्रिफाइस करने के लिये तैयार होंगे वहां हम आगे की जेनरेशन के लिये राज-स्थान केनाल के जरिये राजस्थान को और देश को लाभ पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी इग्नोर नहीं कर सकते कि राजस्थान का बहुत, अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसमें आबादी काफी है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो स्पार्सली पोपुलेटेड है और जिस क्षेत्र में आबादी काफी है वहां एग्रीकल्चर होल्डिंग्ज बहुत कम हैं। जहां ऐसी हालत है वहां के लोगों के लिये एम्पलॉयमेंट, इन्डस्ट्रियल एम्पलॉयमेंट आदि का प्रश्न खड़ा होता है। इसके अलावा हम होल्डिंग्स के हिसाब से देखते हैं तो कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर काफी क्षेत्र ऐसा है जहां होल्डिंग्स काफी छोटी छोटी हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि माइन्स, इन्डस्ट्रीज़ आदि में इस प्रकार की प्रगति हो जिससे जहां दूसरे क्षेत्र उससे लाभान्वित हों वहां ये क्षेत्र उससे वंचित न रह जायं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थर्ड प्लान बनाया जा रहा है जिसके जरिये प्लानिंग कमीशन ने जो आउटलाइन पब्लिश की है उसके अनुसार रीजनल डिस्पेरिटीज़ को कम करने को कहा गया है और इसको कम किया जाना चाहिये और मैं समझता हूं हमें भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये।

राजस्थान इस वक्त पिछड़ा हुआ है। जो पोटेन्शियलिटी है, हमारी माइन्स या दूसरी इन्डस्ट्रीज़, केमिकल इन्डस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको देखते हुए हम पिछड़े हुए जरूर हैं। इसके लिये नेसेसरी फण्ड्स हों जो ऑल इन्डिया प्रासपेक्टिव्ज़ हैं उनको देखते हुए राजस्थान को अपना बहुत बड़ा हिस्सा देने के लिये तैयार होना चाहिये; इसके लिये सेक्रीफाइस करने होंगे। यह नहीं कि जो हिस्सा दूसरे राज्यों को मिलने वाला है वह हमें नहीं मिलेगा। वह तो मिलेगा ही लेकिन इसके लिये जहां एडीशनल टैक्सेज़ या एडीशनल रिसोर्सेज़ नहीं होने चाहिये; इस प्रकार की यदि किसी की मान्यता है तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा वह ठीक नहीं है। हमें तो अपने रिसोर्सेज़ लगाने ही होंगे। हमें जो भी अपने यहां के साधन जुटाने होंगे अपने एफर्ट्स करने होंगे वे

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

तो करने ही पड़ेंगे। इसके बिना हम जाकर वहां यह कहें कि हम बेकवर्ड हैं इसलिये हमें सहारा दीजिये इसके अन्दर वजन कम हो जाता है। हमें तो अपने पूरे एफर्ट्स करने ही चाहिये। उसके बाद प्लानिंग कमीशन से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से कहें कि हम बेकवर्ड इसलिये रह गये हैं कि फर्स्ट प्लान और सेकन्ड प्लान में स्पेश्यली पब्लिक सेक्टर के अन्दर हमारे यहां बहुत गेप रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हुई। इस पूर्ति के करने की तरफ भी उनकी तरफ से कदम उठायें जायेंगे; ऐसा मान कर चलना चाहिये। पब्लिक सेक्टर में रेलवेज़, इन्डस्ट्रीज़, माइन्स, कॉपर थाउजेन्ड्सटन्स के लिये स्मेलटर आदि हैं। जहां तक मुझे पता है इसके डिपोज़िट्स कई मिलियन्स टन की हैं। जबकि करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हमारी इसी की खरीद में बाहर चली जाती हैं वैसी हालत में जब राजस्थान के अन्दर इसका बहुत बड़ा भंडार है तो इसके उपयोग के बारे में भी हमें उसी तरीके से सोचना है। पैट्रोलियम गैस का काम था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसका अनुसन्धान शुरू किया था उसके बाद इसकी गति धीमी पड़ गई। आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है; यह बेसिक चीज है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स, मशीन्स, बिल्डिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स, इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़, केमीकल इन्डस्ट्रीज आदि ऐसी हो सकती हैं जिन पर विचार किया जा सकता है और विचार किया जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार का यह प्रारूप है और इसके समर्थन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है उसके पश्चात् मै ऐसा समझता हूं कि उनके भाषण को सुनने से ऐसा जरूर लगा होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के बाद राजस्थान कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से पूर्ण हो जायेगा ताकि इसको दूसरों की ओर देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हम सबको मिल कर राजस्थान का विकास करना है। राजस्थान के विकास की दृष्टि से हमारी ये योजनायें बनती हैं और इन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। भारत सरकार ने समूचे भारत के लिये योजना बनाई है, उसी के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने भी अपनी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करके तैयार किया है। ऐसी स्थिति में हमें भारत सरकार द्वारा मुख्य लक्ष्य जो निर्धारित किये गये हैं उनकी ओर दृष्टिपात करना होगा। मैं ऐसा समझता हूं, भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के पांच मुख्य उद्देश्य तय किये हैं।

पहला लक्ष्य समूचे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का है। इस योजना के अनुसार पांच प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में आय बढ़ाई जायगी।

इसके बाद दूसरा उद्देश्य खाद्यान्न की दृष्टि से इस देश को आत्म निर्भर करने

(श्री भैरोंसिंह)

का है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को चालू करना है जिससे हमारे देश में जो भी सामग्री की आवश्यकता हो वह देश में ही उपलब्ध हो जाये, उसका ठीक प्रकार से प्रयोग हो सके।

इसी प्रकार से भारतवर्ष की जितनी भी मैन पॉवर है उसको युटिलाइज़ करने की व्यवस्था है। उसका प्रावधान रखा गया है और अन्त में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि भारत सरकार ने ५४ में इस योजना के सम्बन्ध में सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की नीति अपनाई है। इसके कारण से और दूसरी परिस्थितियों के कारण से यह आवश्यक होता है कि हम जो हमारे देश के अन्दर आर्थिक दृष्टि से जो एक प्रकार का भेदभाव है इकोनोमिक डिस्पेरिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी दूर करने की चेष्टा करें।

इस आधार पर मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने अपना प्रारूप इस तीसरी योजना का तैयार किया है और इसके अन्दर भी राज्य सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि दो मुख्य बातों को सामने रखकर वे योजना का लक्ष्य निर्धारित करें। इन दो में से सबसे पहली बात जो शायद अपने प्रारूप में भी उन्होंने रखी है वह यह रखी है कि हम अपने लोगों की आमदनी बढ़ावें और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अन्दर या हमारे प्रान्त में जिस प्रकार की बेकारी है उसको दूर करते हुए जो हमारे यहां मैन पॉवर है उसको ठीक प्रकार से युटिलाइज़ कर सकें।

मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यदि इन सारी बातों की प्राथमिकता पर थोड़ा सा ध्यान दिया जावे तो आज हमारे सामने सबसे मोटा प्रश्न एक पैदा होता है और वह प्रश्न यह होता है कि हम जहां स्टेट की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, हम यहां को पर-कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को धन्धा देना चाहते हैं वहां सबसे मोटी आवश्यकता इस बात की रहती है कि हमारे देश का या हमारे राज्य का जो मैन पॉवर है वह पूरा का पूरा युटिलाइज़ हो, उसको हम प्लानिंग की दृष्टि से ठीक प्रकार से युटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं, यह प्रश्न पैदा होता है।

आज इस बात में कोई सन्देह नहीं, कि मैं समझता हूँ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी राजस्थान सरकार की एम्प्लॉयमेंट की पोटेन्शियेलिटी की ओर और इस राज्य का पिछला ढाई साल का जो अचीवमेंट था उसकी ओर संकेत करते हुए चेष्टा की है यह बताने की कि सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में शुरू के ढ़ाई वर्षों में इस प्रकार की पोटेन्शियेलिटी राज्य सरकार ने प्राप्त की है जैसी भारत सरकार ने की है। मैं सुन नहीं पाया। प्रतिशत कहना चाहिये, हमारा प्रतिशत उससे भी ऊंचा है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़ियां**(मुख्य मन्त्री): भारत सरकार का तो इसमें प्रतिशत होता ही नहीं। स्टेट वाइज़ ही होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि हमें राज्य की सारी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा

( श्री भैरोंसिंह )

और इस पर विचार करते हैं, अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान के अन्दर आज राजस्थान की मैन पॉवर क्या है और उस मैन पॉवर को युटिलाइज़ करने के सम्बन्ध में हमने किस प्रकार के साधनों को काम में लेकर उस सारे मैन पॉवर को एब्ज़ोर्व करने की चेष्टा की है, यह जानना होगा।

मैं समझता हूं कि तीसरी योजना के प्रारूप को जो हमारे सामने राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है इसके अनुसार हम इस सारे मैन पॉवर को यदि दो भागों में बांट कर इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे सामने बिल्कुल सही पिक्चर आ जावेगी। दो भागों से मेरा मतलब है हमारा प्रान्त दो भागों में बंटा हुआ है; एक है अर्बन एरिया और दूसरा है रूरल एरिया। अर्बन और रूरल एरिया-इन दोनों में हमारे जितने भी एम्प्लॉयड हैं या अन्डर एम्प्लॉयड हैं उनकी संख्या सही रूप से मैं भी नहीं बता सकता, भारत सरकार भी नहीं बता सकती और राज्य सरकार भी नहीं बता सकती, लेकिन जो भी राज्य सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने के प्रयत्न किये गये हैं और उसके फलस्वरूप जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं उनके आधार पर मैं जैसा कह सकता हूं कि हमारी इस योजना में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं वह इस प्रकार की योजना होगी कि जिस योजना के अन्तर्गत जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमने एक जो हमारे सामने कमी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण से और सेकिन्ड के प्रारम्भ में हमारे सामने जितने आदमी बेकार थे उनकी संख्या को जिसे सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में हम एब्ज़ोर्व करना चाहते थे, धन्धा देना चाहते थे और इसके बाद में तीसरी के प्रारम्भ में जो शेष रहते हैं वह इस प्रकार का शेष है कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जितने बाकी लोग थे उनसे ज्यादा हमारी तीसरी योजना के प्रारम्भ में एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से बाकी रहेंगे। अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में इस तीसरी योजना के प्रारूप में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं बेकार लोगों के उनको ध्यान से देखा जावे तो पता चलेगा कि राजस्थान के अन्दर जहां अर्बन लेबर फोर्स इस दूसरी योजना के अन्दर १० लाख बढ़ा था; वहां तीसरी योजना में १ से लेकर ११.४ और १.३ लैक्स क्रमशः अर्बन और रूरल के बेकारों का एडीशन होगा। इसको दृष्टि में रखते हुए जो सेकिन्ड के शुरू में बैक लाग छोड़ा था उसके बाद जो एडीशन हुआ है इस तीसरी योजना के पीरियड में अर्बन एरिया में दूसरी योजना का बैक लाग रहेगा। थर्ड योजना के प्रारम्भ में इस सारे एडीशन बैक लाग को जोड़ देना चाहिये। सेकिन्ड का बैकलाग यों का यों रहा जो एडीशन हुआ है। अब इन सब के सब अनएम्प्लॉयड को काम-धन्धा किसी प्रकार का आप दें तो राजस्थान में इनके लिये २६ हजार इस प्रकार के धन्धे सालाना आपको जुटाने पड़ेंगे। २६ हजार धन्धे एक साल में जुटायें तो इसका नतीजा यह होगा कि तीसरी योजना के प्रारम्भ के अन्दर दूसरी योजना के जो एडीशन हैं उनको हम खपा पावेंगे। बाकी जितना बैक लाग चलता आया है वह ऐसे ही चलेगा।

( श्री भैरोंसिंह )

अब प्रश्न है कि जो योजना आपने तैयार की है उसमें क्या ऐसी व्यवस्था है कि इन आगे के पांच वर्षों में प्रति वर्ष हम २६ हजार इस प्रकार के अर्बन जॉब्स इकट्टे कर सकेंगे और लोगों को धन्धा दे सकेंगे ? वैसी की वैसी स्थिति रूरल पॉपुलेशन की है। तो इस तीसरी योजना के सामने दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक है जो बिल्कुल बेकार हैं, दूसरे हैं वे जो पूर्णतया तो नहीं पर काफी समय जिनका फालतू बचा रहता है कि जिसको युटिलाइज़ किया जावे तो देश को और प्रान्त को बड़ा लाभ हो सकता है।

पर मेरी यह धारणा है कि पूरा उपयोग नहीं हो सकता और इसलिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि कोई धन्धा नहीं है। उस स्थिति में रूरल पॉपुलेशन में भी मैं ऐसा समझता हूं कि नेशनल सेम्पल सर्वे, १९५५ जिसके आधार पर जो ५५ का एक एनेलिसिस करके ५५ के बेसिस पर राज्य की सर्वे करके बताया था कि राजस्थान में ५.७६ पर्सेन्ट जितनी भी लेबर फोर्स है ५५ के अन्दर अनएम्प्लॉय्ड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी सेकिन्ड फाइव ईयर प्लॉन का काम करने के बाद राजस्थान में ५८ हजार इस प्रकार के व्यक्ति रहेंगे जिनको किसी प्रकार का कोई धन्धा हम नहीं दे पाये। रूरल पॉपुलेशन में भी १.२६ लैक्स इस प्रकार के रूरल जॉब्स रूरल एरिया के लिए नहीं तय कर पावेंगे तो मैं समझता हूं कि तीसरी योजना में हम लोगों को धन्धा देने की बात कहते हैं वह किसी प्रकार से भी नहीं दे पावेंगे।

तो मेरे कहने का तात्पर्य है यह कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार १.२६ लैक्स इस प्रकार के रूरल एरिया के लिये जॉब्स को हमने पर-इयर बनाने की व्यवस्था की है या नहीं ? और अगर ऐसी व्यवस्था की है तो किस प्रकार से की है ? इसके लिये किस प्रकार से धन इकट्ठा होगा, किस प्रकार की सामग्री जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से किस प्रकार की सहायता हमें मिल रही है या हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी बातों को सामने रख कर इस प्लान पर विचार करना पड़ेगा।

मैं इन आंकड़ों की सत्यता-असत्यता पर, अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं कहना चाहूंगा और जो कुछ सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े इस प्रारूप में दर्ज किये हैं उन्हें ही सही मान कर चलता हूं और उनको सही मानकर चलने की स्थिति में निवेदन करूंगा कि हमें इन सारे आंकड़ों के आधार पर विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में हमने कितनी, किस प्रकार की एम्प्लॉयमेन्ट पोटेन्शियलिटी अब तक क्रिएट की है या आगे कितनी करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान का विकास जिस प्रकार से होगा उसके साथ ही साथ राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन्धे मिलेंगे। मैं यह मानने को तैयार हूं कि राजस्थान में किसी प्रकार से हम प्रयत्न करते जा रहे हैं उसके कारण आज नहीं, वह चाहे लम्बे अर्से में जाकर किसी तरह जिस तरह माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बताया और शायद तीसरी योजना के प्रारूप में भी यह दिया है कि राजस्थान केनाल बन रही है; यह जो योजना है वह शायद उसके कमान्डेड एरिया को जो सारा कमान्डेड एरिया है उस सारे को ६ फाइव इयर प्लानों में, मतलब कि बीस

# Page No.49



( श्री भैरोंसिंह )

वर्षों के बाद में जितना कुल कमान्डेड एरिया है उसको हम ठीक प्रकार से युटिलाइज़ कर सकेंगे। तो आज कोई यह देख कर चले कि राजस्थान कैनाल बना दी तीसरी योजना में ४५ करोड़ की व्यवस्था करके तो यह समझ कर बैठे कि इसके कारण से जो रूरल पॉपुलेशन को जॉब्स के अन्दर हम युटिलाइज़ करना चाहते हैं वह सारा का सारा रूरल पॉपुलेशन का एरिया कैनाल में या सिंचाई के अन्दर किसी प्रकार से खपा पावेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का यदि विचार करके तीसरी योजना को देखने की कोशिश करते हैं तो भूल करते हैं।

राजस्थान कैनाल अच्छी कैनाल हो सकती है। राजस्थान कैनाल के कारण राजस्थान इण्डिया की ग्रेनरी सिद्ध हो सकती है। राजस्थान समूचे भारतवर्ष में खाद्यान्न की स्थिति में अपने आपको सरप्लस बना कर खाद्यान्न की सारी कमी को पूरी कर सकेगा लेकिन हमें आज की मांग देखनी है। २० वर्ष के बाद क्या होगा; आज के भूखे को २० वर्ष के बाद रोटी देंगे उसके लिए हमारी योजना नहीं है। हमारी योजना है कि आज जो भूखा है उसको कुछ तसल्ली दे सकते हैं। सुबह के भूखे को कह सकते हैं कि शाम को मिलेगी या शाम के भूखे को कह सकते हैं कि दूसरे दिन सुबह मिलेगी या तीसरे दिन सुबह मिलेगी। लेकिन आज के भूखे को कह दें कि ४५ दिन भूख हड़ताल करें और फिर ४६ वें दिन यह निश्चय करेंगे कि उसे नींबू का रस कैसे दिया जाये ? आज की योजना सब लोगों को किस प्रकार धंधा दें; इसके ऊपर तुली हुई है। मैं समझता हूं कि तीसरी योजना में जो हम खर्च करने जा रहे हैं वह इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि हम लोगों को बता सकें कि जितनी हमारे प्रान्त में भुखमरी या बेकारी है उसको हम समाप्त करने पायेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां इतनी बेकारी है वहां मेरा फर्ज भी होता है कि राज्य सरकार के समक्ष इस प्रकार के सुझाव भी प्रस्तुत करूं कि जिसके आधार पर हम इस बेकारी को दूर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि हमारे देश के अन्दर ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और उन सब का धंधा खेती करना है और या इस प्रकार के काम करने हैं जिनका कि सम्बन्ध खेतिहर या खेती से होता है। तो इस प्रकार के लोगों की व्यवस्था करनी है जो गांवों में रहते हैं। जो आंकड़े राज्य सरकार ने दिये हैं उनके अनुसार गांवों में जो बेकारी है उस गांवों की बेकारी को और राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता को सुख-सुविधा देने की दृष्टि से नहीं, बल्कि सारे के सारे लोग जिनको काम देना है ऐसे बेकार लोगों को और जिनके पास कम काम है ऐसे अर्द्ध-बेकार लोगों को पूरा काम देना है। इन सारे लोगों को किस तरह से धंधा दे सकते हैं ? इसके लिए हमारे देश के अन्दर एक ही धंधा है और वह है खेती का, इसके अलावा दूसरा काम हमारे देश में नहीं होता है।

खेती के बाद में दूसरा नम्बर आता है इन्डस्ट्रीज़ का। खेती के साथ इन्डस्ट्रीज़ का अटूट सम्बन्ध है। खेतिहर की स्थिति हमें ठीक बनानी है तो प्रोडक्शन से इन्डस्ट्री के द्वारा खाने की जो चीजें हैं उनको खाकर बाकी की चीज़ों का इन्डस्ट्री के द्वारा ज्यादा से

( श्री भैरोंसिंह )

ज्यादा और अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमें इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेन्ड करना पड़ेगा।

यह मैं मान कर चलता हूं कि हमारी जो २५७ करोड़ की योजना है उसके अन्दर प्रमुख रूप से ४५ करोड़ रुपया राजस्थान केनाल के ऊपर रखा है। राजस्थान केनाल, मैं आपको बताऊं, पहले भारत सरकार के अधीन थी और उसको एक प्रोजेक्ट मान कर उसका सारा खर्चा अपने ऊपर लेने की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन इस वर्ष तीसरी योजना में यह ४५ करोड़ रुपये का खर्चा राजस्थान सरकार के ऊपर अतिरिक्त आया है और वह उसको राजस्थान केनाल के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। मैं छोटा सा सवाल माननीय मुख्य मंत्री महोदय से करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान केनाल का काम बन्द कर दिया जाये और मैं यह भी नहीं कहता कि राजस्थान केनाल से जिस बहबूदी की सोचते हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाये। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि इस पर हम ४५ करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। हमें तीसरी योजना में इतनी धन राशि खर्च करनी पड़ेगी, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इतनी ही धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी और पांचवी योजना में भी इतनी ही राशि खर्च करनी पड़ेगी और इस प्रकार की राशि हम खर्च करते जायेंगे और जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया था कि इससे नॉन-पैरेनियल इर्रिगेशन भी बहुत लेट जाकर शुरू होगा और जितनी लैंड को कवर करना चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी नहीं कर पायेंगे तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार इस फैक्टर के ऊपर विचार नहीं कर सकती कि हमारे देश में माइनर इर्रिगेशन का भी काफी स्कोप है, बन्ध बनाने का भी काफी स्कोप है ? राजस्थान में हो सकता है कि कई ऐसे जिले हों कि जिनके अन्दर यदि सारी पॉवर और शक्ति कॉन्सेन्ट्रेट कर दें और सारा धन लगाया जाये तो राजस्थान के जो इलाके आज नहरों से बचने वाले हैं जिनके अन्दर आबपाशी नहीं कर सकते हैं ऐसे इलाकों में माइनर इर्रिगेशन से इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं कि रूरल एरिया की जितनी अनएम्पलॉयड फोर्स है उसको ठीक तरह से वहां युटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पोइन्ट के ऊपर विचार किया जाये। अगर राजस्थान के अन्दर एवरेज लगाया जाये तो आज नहीं कह सकते कि एक कुंआ बनाने में कहीं ७-८ हजार रुपया खर्च हो सकता है। लेकिन जिस क्षेत्र में सारी स्थिति को कन्सेन्ट्रेट कर सकते हैं तो २,०००) रु० की तकावी राज्य सरकार की तरफ से दी जाये तो २,०००) रु० एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में खर्चा करके कुंआ बनाता है और इस प्रकार से ४,०००) रु० के अन्दर एक कुंआ बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम २,०००) रु० के अन्दर तकावी देकर एक कुंआ बना सकते हैं और एक कुंए के अन्दर यदि हम कम से कम रखें, ज्यादा से ज्यादा नहीं कम से कम रखें तो १० एकड़ के करीब भूमि की सिंचाई हो सकती है। अब राजस्थान केनाल के ऊपर जो ४५ करोड़ रुपये का खर्चा किया जा रहा है उस ४५ करोड़ रुपये के खर्चे में यदि हम माइनर इर्रिगेशन को प्रोत्साहन दें और उसमें खर्च करें तो

# Page No.51



( श्री भैरोंसिंह )

हम उसके खर्च करने के बाद उस स्थिति में आ सकते हैं कि जिसमें राजस्थान सरकार २० वर्ष बाद राजस्थान केनाल से होने वाले इर्रिगेशन के कारण दुनिया की ग्रेनरी साबित करना चाहते हैं। अगर उसी ४५ करोड़ रुपये को माइनर इर्रिगेशन में खर्च किया जाये तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जो राजस्थान सरकार २० वर्ष के बाद टार्गेट्स पूरा करना चाहती है वह ५ वर्ष में पूरे हो जायेंगे। राजस्थान में खेती की जमीन है। लोग कुंए खोदेंगे जमीन को जोतेंगे और जमीन की सिंचाई करेंगे और जितना प्रोडक्शन आप चाहते हैं वह आपको देंगे और उसी के आधार पर हमारे प्रान्त की इन्कम बढ़ती है, हमारी नेशनल इन्कम बढ़ती है। उस बढ़ी हुई इन्कम की जिसको हम सरप्लस इन्कम कह सकते हैं यदि आवश्यकता पड़े तो हम राजस्थान केनाल के लिए भी खर्च करके जो २० वर्ष के बाद विकास की स्थिति होगी आगे जाकर उसको पूरा करने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन यहां यह विचार करना पड़ेगा कि इतना रुपया हम ४५ करोड़ रुपया नहीं बल्कि १३० करोड़ रुपया ब्लॉक करके कहीं आगे तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां देश में १,६५० करोड़ रुपये के एडीशनल टैक्सेज़ लेने पड़ेंगे, जहां डेफीसिट फाइनेन्सिंग करना पड़ेगा, जहां २२ सौ हजार की एड हमें विदेश से लेनी पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में हम अपनी योजनाओं को अपने साधनों तक ही आधारित नहीं करके दूसरों के साधनों पर आधारित करते हैं तो यह कोई ठीक बात नहीं। पैसे के आधार पर जो डेवलपमेंट करते हैं उस प्रकार का डेवलपमेंट हम नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि भावना की दृष्टि से, भावात्मक दृष्टि से विचार किया जाये तो चम्बल योजना का विरोध करना या राजस्थान केनाल का विरोध करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम माइनर इर्रिगेशन से सारी व्यवस्था करें तो इसके परिणाम बहुत सुन्दर निकल सकते हैं।

अन्त में, मैं इस राजस्थान केनाल के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। राजस्थान के जितने भी इकोनोमिक रिसोर्सेज़ हैं और जिस तरह से उन्होंने फिगर्स दी हैं, ऑल इन्डिया फिगर्स पर–कैपिटा इन्कम की, उनके आधार पर राजस्थान के व्यक्ति की पर-कैपिटा इन्कम कम है। उस दृष्टि से भारत सरकार को निवेदन करना चाहिए कि राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता आज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि राजस्थान केनाल के ऊपर खर्च करने के लिए जो ४५ करोड़ रुपये राज्य सरकार के ऊपर थोपे गये हैं वह राज्य सरकार बरदाश्त करे; बल्कि सदन को इसके लिए पुर जोर अपील करनी चाहिए कि यह खर्च भारत सरकार अपने ऊपर ले; राजस्थान केनाल को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए। इस कारण से हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन आने वाला है उससे हम किसी प्रकार बच सकेंगे।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े खेद के साथ इस सदन में कहनी पड़ती है। मैंने सारे आंकड़े देखे हैं, इसका सारा ड्राफ्ट देखा है और इसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमारी

( श्री भैरोंसिंह )

राज्य सरकार जहां बाहर गांव गांव में बेकारी को दूर करने की चेष्टा करती है, खेती के जरिये से चेष्टा करती है वहां राज्य सरकार जो हमारे प्रोडेक्शन के टारगेट्स थे उनको ५० पर्सेंट भी कवर नहीं कर पाई है । यह कैसी दलील है, हम किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं ? राज्य सरकार चाहती है कि समाज में साधन जुटाये जायें । आज उसके बावजूद भी हमारी राज्य सरकार के आंकड़े देखें तो हमें पता लगता है कि ५० पर्सेन्ट के करीब हम सारे खर्चे को पूरा नहीं कर पाये हैं और जितना इर्रिगेशन का काम होना चाहिए था वह इर्रिगेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इन टार्गेट्स को देखने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भाषण सुनने के बाद जब यह कहा जाता है कि हमारे देश के अन्दर अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारे देश के जो फूड प्रोडेक्शन के टार्गेट्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि लाखों मन से अधिक एक्सीड किया है; मैं यह नहीं समझ पाता कि राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में फूड के जो टार्गेट्स बनाए वे गलत बनाए। मैं तो यह नहीं समझ पाता जब कि फिफ्टी पर्सेन्ट इर्रिगेशन का खर्चा आप कर नहीं पाते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आपके टार्गेट्स थे वे ५० प्रतिशत भी पूरे नहीं होते हैं, फिर भी आपका फूड प्रोडेक्शन जो है वह बढ़ता ही नहीं है, शायद आठ लाख मन के करीब से एक्सीड करता है और ऐसी स्थिति के अन्दर मैं समझ नहीं पाता, अध्यक्ष महोदय, कि इन स्थितियों में इन आंकड़ों पर किस प्रकार से विश्वास किया जा सकता है ? इर्रिगेशन जितना होना चाहिए था वह नहीं होता है, जितनी भूमि सिंचित होनी चाहिए वह नहीं होती है और हमारी सरकार कहती है कि फूड प्रोडक्शन का जो टार्गेट था वह पूरा ही नहीं हुआ है बल्कि एक्सीड भी किया है; तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कुछ कठिनाइयां पैदा करती हैं और उन कठिनाइयों से निश्चित रूप से नतीजा यही निकलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े तैयार किए गए, जिस समय टार्गेट तैयार किया गया तो या तो वह गलत तैयार किया गया, जैसा हमने तय किया कि इर्रिगेटेड लैंड इतनी हो जायेगी इस योजना काल में लेकिन उसका फिफ्टी पर्सेन्ट भी हम पूरा नहीं कर पाये और इधर फूड प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि हम एक्सीड कर गए, तो या तो पहले वाले आंकड़े गलत रहे या अब फूड प्रोडक्शन के आंकड़े जो हमारे सामने रखे गए हैं वे गलत हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।

आज हमारे देश की किस प्रकार की स्थिति है कृषि की ? राजस्थान के अन्दर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस ओर काफी ध्यान देने की चेष्टा की गई है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता अन्डर एम्पलॉयड एग्रीकल्चरिस्ट्स की है।

१.३२ म.प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्या आज हम फुल टाइम एम्पलॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ? उसके लिए एकमात्र साधन है इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन्टेन्सिव

# Page No.53



( श्री भैरोंसिंह )

कल्टीवेशन से आपकी इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी बढ़ेगी, आपके कृषि के साधन बढ़ेंगे; किसानों को मौका मिलेगा कि अपनी जमीनों पर खुद पैसा लगावें। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन से ही वे पूरे एकड़ को ईल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपके देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन हमारी राज्य सरकार इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का नाम भी लेना नहीं चाहती। मैं कहता हूं कि सन् १९५४ के अन्दर सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का स्लोगन लगा कर किसानों से को-ऑपरेटिव के नाम पर जमीन छीनने की जो योजना बना रखी है, उस योजना के पीछे लार्ज स्केल फार्मिंग की जो भावना है उससे आज हमारी सरकार इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की ओर आंख उठा कर भी देखना नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि हमारे देश को इस प्रकार के नारों में फंसाने की आज आवश्यकता नहीं है। आज एक्चुअल प्रोडक्शन को देखना है कि कुल कितना लाभ इससे हमें मिला है। इन नारों से काम चलने वाला नहीं है। मैं तो यह भी कहता हूं कि हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं मैं उनको बधाई दूँगा कि उन्होंने काफी प्रयत्न करके राजस्थान में हजारों सहकारी समितियों की संख्या तो बढ़ा दी, साथ ही साथ प्रयत्न करके यह भी देखिए राजस्थान का भारतवर्ष में कोई भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं होगा कि जिसमें आप कह सकें कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग सफल हुआ। आपका यह को-ऑपरेटिव फार्मिंग बिल्कुल फैल हुआ और इसके लिए एक भी को-ऑपरेटिव फार्म उदाहरण के तौर पर भी बतावें कि उस जगह हम काम को-ऑपरेटिव फार्मिंग के जरिए कराना चाहते थे और वहां काम पूरा हुआ ?

**श्री मोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : आपकी इच्छा पूरी हुई।

**श्री भैरोंसिंह** : इसलिए मैंने सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान दिलाया है। मैं फिर माननीय सहकारिता मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे अपने दल ने, मेरी अपनी पार्टी ने को-ऑपरेटिव फार्मिंग का जो नारा था उसका विरोध किया था और उसकी पूर्ति माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने काफी हद तक कर दी है। ऐसी स्थिति में आज इस प्रकार के थोथे स्लोगन्स जो हैं उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। हमारे सामने आज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के झगड़े हैं। हमें उसमें स्पष्ट नीति अपनानी पड़ेगी। लोगों के दिमागों के अन्दर आज इस प्रकार की भावना कायम न हो जाय कि उनका रुपया ब्लॉक हो जायेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि रुपया ब्लॉक न हो, साधन ब्लॉक न हों और वे आगे आवें, पर-कैपिटा इनकम बढ़े, नेशन की इनकम बढ़ सके।

बदकिस्मती से आज हमारे देश के अन्दर प्राइवेट सेक्टर को किस प्रकार से समाप्त किया जा रहा है ? प्राइवेट सेक्टर को समाप्त करने को योजना चल रही है। आज पब्लिक सेक्टर को यह डर है कि सरकार हमारी सारी चीजें ले लेगी और उसका नतीजा यह होता है कि हमारे पास आज पूंजी है उस पूंजी का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के बाहर कुछ क्षेत्रों के अन्दर राजस्थान के उद्योगपतियों से

( श्री भैरोंसिंह )

यह कहने के लिए गए थे कि राजस्थान के अन्दर काफी इस प्रकार के रिसोर्सेज़ हैं जो एक्सप्लॉयट किये जायें तो उनके बेसिस पर राजस्थान का कम्पलीट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का यह कदम बहुत ही सराहनीय था। हो सकता है कि मुझे जो सूचनाएं मिली हैं उनमें कुछ सूचनाएं गलत मिली हों, लेकिन जो सूचनाएं मुझे मिली हैं वे मैं इस सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा। वहां शायद कुछ लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री को यह आश्वासन भी दिया होगा कि राजस्थान में हम इंडस्ट्रीज़ खोलने में कुछ सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन वे एक बात पूरी करें। हम राज्य सरकार के कहने पर प्राइवेट सेक्टर के अन्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी करते हैं और हम राजस्थान सरकार का विश्वास करके यदि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कर दें तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यहां मेरा मतलब प्रोटेक्शन से लेबरर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने के प्रोटेक्शन से नहीं है या वे अनावश्यक रूप से मुनाफा उठाते रहें और राज्य सरकार कुछ भी न करे, इससे भी मेरा मतलब नहीं है। वे इस प्रकार का प्रोटेक्शन राज्य सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहते हैं कि एक दफा हम किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद में राज्य सरकार उसे पब्लिक सेक्टर में लेने की कोशिश करती है; वह कोशिश नहीं करेगी या इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं करेगी कि जिससे जो इन्वेस्टमेंट करें वह राज्य सरकार ले ले। तो आज जो इस प्रकार की भावना लोगों के दिलों में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में पैदा हो गई है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो, इस प्रकार की बातें हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष रखी गई हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उन सारी परिस्थितियों के ऊपर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि इस सारे विकास में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण न तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, न बेकार लोगों को धन्धा मिल पाता है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमारे यहां राजस्थान में पॉवर की कमी है। पॉवर से मेरा यहां तात्पर्य सत्ता से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब बिजली से है। राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी है और यह बात सही है। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि शायद ९२ हजार या ९३ हजार किलोवाट बिजली का टार्गेट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है जिसे पूरा कर सकेंगे; इस प्रकार का आश्वासन इस सदन को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी अपोइन्ट की गई थी। मैंने उस वर्किंग ग्रुप की, उस कमेटी की रिपोर्ट को देखा है और उस रिपोर्ट में जो उदाहरण दिए हैं उनको देखने के बाद मैं ऐसा समझ पाया कि राजस्थान सरकार द्वारा जो ९२ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने की जो योजना हमारे सामने रखी हुई है और उसको पूरा करने का आश्वासन भी दिया है लेकिन भारत के दूसरे राज्य हैं, दूसरी प्रान्तीय सरकारें हैं उन प्रान्तीय

( श्री भैरोंसिंह )

सरकारों की तुलना में राजस्थान में जो बिजली के लिए काम हुआ है उसको देख कर कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान में कुछ भी काम हुआ है । इसी आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार की रिपोर्ट इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु देना चाहूंगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है । मैं यह बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर कितना और अन्य प्रान्तों में कितना काम हुआ है । आसाम के अन्दर ५ गांवों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, बिहार में ६१६ गांवों में, बम्बई में ४६१ में, केरला में ६५२ में, मद्रास में ३,०२५ में, मध्य प्रदेश में १६८ में, मैसूर में ४०७ में, उड़ीसा में ४८ में, पंजाब में १,११३ में, उत्तर प्रदेश में ६२ में, जम्मू एण्ड कश्मीर में २६ में, वेस्ट बंगाल में १३६ में, आंध्र प्रदेश में १,०८२ में और राजस्थान में एक गांव में हुआ है ।

मैं समझता हूं कि इस एक गांव ने राजस्थान की नाक रखी है । इसके लिए तो राज्य सरकार को, उस गांव को और हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग को धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन आज हम समता भारत सरकार और अन्य प्रान्तों की करना चाहते हैं, पर्सेन्टेज के बताने की हम कोशिश करते हैं ।

हैल्थ के अन्दर जो बैड्स के आंकड़े हैं वे पोपुलेशन की बेसिस के मुताबिक हम एक्सीड कर गये हैं । इस प्रकार के आंकड़े दिखा कर सही स्थिति हम राजस्थान की जनता के सामने नहीं रख पाते हैं । यह भी एक प्रकार से हमारा दोष है ।

इतना ही नहीं, मैं ऐसा चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के अन्दर सस्ती बिजली मिले । राजस्थान के लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके तो यह कहा जा सकता है और इतना भी कहा जा सकता है कि राजस्थान में जितने भी इस प्रकार के रिसोर्सेज़ हैं, मिनरल रिसोर्सेज़ हैं या अन्य रिसोर्सेज़ हैं वे ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट किये जा सकते हैं । इस एक्सप्लोइटेशन से हमारी इनकम बढ़ सकती है, और अकेली इनकम बढ़ने से हम राजस्थान का ठीक प्रकार से विकास कर सकते हैं । यह बात सही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ५० या ५५ करोड़ की इसके ऊपर खर्च करने की व्यवस्था की गई है । लेकिन आज देखते यह हैं कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि इतने लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी, एटोमिक पॉवर स्टेशन राजस्थान में बनेगा जिससे कि बिजली चौथी पंचवर्षीय योजना में मिलेगी । उस स्थिति में आज राज्य सरकार इस बात को कहने की स्थिति में है कि राजस्थान में वे रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कर सकेंगे, राजस्थान के किसानों को बिजली दे सकेंगे । राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता है, वह सस्ती बिजली किस प्रकार से दे सकेंगे ? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज से दो वर्ष पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो आदमी इन्डस्ट्री के अन्दर २०,००० किलोवाट बिजली से कम खर्च करेगा उसको दो आना पर-युनिट के बेसिस पर रियायती दरों से बिजली दी जायेगी । मैंने उस सारे स्टेटमेंट

( श्री भैरोंसिंह )

को भी भारत सरकार की जो सस्ती बिजली देने की नीति है उसके आधार पर देखा और मैं आज यह कह सकता हूं कि भारत सरकार की जो इस संबंध में नीति है वह यह है कि २० हौर्स पॉवर पर जो आदमी बिजली खर्च कर सके उसको डेढ़ आना पर-युनिट के हिसाब से बिजली देंगे। वह भारत सरकार की जो नीति है उस नीति के विरुद्ध है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस प्रकार की जो घोषणा है। मैं देखता हूं कि वह उसके बिल्कुल विपरीत पड़ती है। राज्य सरकार को हमारे इस वर्किंग ग्रुप की एक टीम थी उसने इस ओर भी संकेत किया है।

इतना ही नहीं, राजस्थान के अन्दर सस्ती बिजली देने का भी सवाल नहीं है। भाखरा से बिजली आई, सीकर में बिजली आई है; अन्य स्थानों में भी आई होगी! लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब भाखरा से बिजली मिलती है, सीकर के अन्दर पॉवर हाउस चलता है, अन्य स्थानों पर भी पावर हाउसेज़ चलते हैं और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी हमको मिलती है, उसके बाद में भी रेट्स बढ़े हुए हैं। दरें उतनी की उतनी हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब बिजली ज्यादा मिलती है तो दरें बढ़ती हैं! कायदा तो यह है कि जब बिजली मिले तो दरें कम होनी चाहिए। जितनी बिजली मिले दरें कम होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार राजस्थान में जितनी ज्यादा बिजली मिलती है उतनी ही दरें बढ़ाती है! इसके लिए कहा जा सकता है कि इस प्रकार जितना खर्चा इन पर हुआ है जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी रेट्स में कमी नहीं की जा सकती है। मैं फिर सदन को जानकारी देना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि भारत में सबसे कम बिजली की रेट्स केरल राज्य में हैं और सबसे ज्यादा बिजली की रेट्स राजस्थान राज्य में है। तो किस तरह से करना चाहते हैं राजस्थान का औद्योगिक विकास? आप चाहते हैं कि राजस्थान में बाकी धन्धों का विकास हो लेकिन बिजली की यह हालत है। आप कहते क्या हैं, गांधी सागर की सारी बिजली का उपभोग क्यों नहीं कर पाये हैं? इसलिए नहीं कर पाये हैं कि टॉवर्स तैयार नहीं हैं? टॉवर्स नहीं मिले और इसलिए बिजली का उपभोग नहीं कर पाये हैं। यह गलती किसकी है? पंजाब में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की बाढ़ आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है कि उसके अन्दर यह कह सकते हैं कि पंजाज को यदि और बिजली दी जाय। पोंगा और सुकेती का एक झगड़ा था। पोंगा और सुकेती के बान्ध से बिजली बनने को थी जिसको लेकर पंजाब सरकार यह कोशिश कर रही थी कि सुकेती के अन्दर बान्ध बने। पंजाब सरकार इतनी बिजली को युटिलाइज़ कर सकती है। जितनी बिजली उनको दें उसको युटिलाइज़ कर सकती है। राजस्थान सरकार द्वारा टॉवर्स के अभाव में ट्रान्समिशन लाइन तैयार नहीं हुई और लाइन्स तैयार नहीं होने से बिजली का उपभोग नहीं कर सके। मैं कहता हूं कि यह राज्य सरकार की अयोग्यता का प्रमाण है कि जितनी बिजली मिलने वाली है उस बिजली को लाने के साधन उपलब्ध नहीं कर सकी। यह अयोग्यता के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। उस अयोग्यता को आप कहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी कर देंगे, यह मैं किसी भी प्रकार से

Page No.57



( श्री भैरोंसिंह )

मानने को तैयार नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का यह हाल है, और अब यह कहा जावे कि हम खेती के बारे में लोगों में इस प्रकार की साइकोलॉजी निर्माण करने जा रहे हैं कि जिसके कारण स्वयं लोग यह समझें कि हमारा अपना विकास हो रहा है । उस स्थिति पर मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आज जितनी भी इस प्रकार की टैक्निकल नॉलेज लोगों को कृषि के सम्बन्ध में होनी चाहिए उतनी हम नहीं बना पाये । आज आप चाहे कई छोटे छोटे पेम्फलेट निकाल दें, मेरे पास भी ऐसे कुछ पेम्फलेट्स हैं; कुछ किताबें प्रकाशित करवादें, हम कितने ही लेक्चरार्स दे दें, बी. डी. ओ. की मीटिंग्स हो, चाहे ग्राम पंचायतों के सरपंच इकट्ठे होकर कृषि के सम्बन्ध में विचार कर लें, मैं समझता हूं इस बात से काम पूरा नहीं होनेवाला है । आज राजस्थान के गांवों के किसी किसान से जाकर पूछिये कि इन फर्टीलाइज़र्स को किस प्रकार से एप्लाई किया जायगा ? जितना खाद है उतने खाद का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने के बाद में कितनी सिंचाई होगी और सिंचाई के बाद किस प्रकार से पैदावार बढ़ेगी, इन चीजों के बारे में एक साधारण किसान आज मंत्रीजी से कह दे तो मैं यह समझूंगा कि इस सम्बन्ध में प्रचार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए वह प्रचार पर्याप्त मात्रा में हुआ है । मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आंकड़ों को देखें, तीसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जो बना है उसके फूड प्रोडक्शन के टार्गेट्स को देखते हैं तो हमने एक्सीड क्यों किया है, इसके लिए अलग अलग आंकड़े बताये हैं बीज के कारण कितना एक्सीड हुआ है, सिंचाई के कारण कितना एक्सीड हुआ, फर्टीलाइज़र्स के कारण कितना एक्सीड हुआ । मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आंकड़े गलत हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि राज्य सरकार ने बीज, फर्टीलाइज़र और सिंचाई के जो आंकड़े दिये हैं जिनकी वजह से राजस्थान का फूड प्रोडक्शन बढ़ा है वे सही नहीं हैं । जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा है वह हमने जितनी जमीन रीक्लेम की है, जितनी जमीन अन्डर प्लो लाये हैं उस सारी के कारण ये आंकड़े बढ़े हैं । उसका श्रेय आप फर्टीलाइज़र के नाम से लेना चाहते हैं, सीड के नाम पर लेना चाहते हैं, बेटर मैनेजमेन्ट के नाम से लेना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से सारा श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से श्रेय लेने की आपकी चेष्टा गलत है । ज्यादा जमीन को अन्डर प्लो लाये हैं उसके कारण पैदावार बढ़ी है । उस चीज़ को छिपाते हैं और आंकड़े बताते हैं वह फर्टीलाइज़र्स के कारण बढ़ी है । मैं निवेदन करूंगा कि उस सारी स्थिति के अन्दर हमको किसान में चेतना लानी पड़ेगी जिसके कारण से वह आज के इम्प्लीमेंट्स को उपयोग में ला सके, आज के खाद का उपयोग कर सके । किसान की सारी स्थिति को देखते हुए प्लानिंग के अन्दर इस प्रकार से किसानों को ट्रेनिंग देने का कार्य होना चाहिए । उस कार्य का इसमें पूर्णतया अभाव है ।

ऐसी स्थिति में अब इसमें जहां ८० प्रतिशत लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहते हैं वहां इस बात का विचार करना पड़ेगा कि उनका सब्सिडीयरी इस प्रकार

( श्री भैरोंसिह )

का कौन सा धन्धा है जिसको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन देना चाहिए ? किसान के सामने दो चीजें हैं। एक पशु-धन है और दूसरा किसान के सामने हैं छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़। इस तरह से इन्डस्ट्री के फिर उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने इन्डस्ट्री के लिए सेकिंण्ड फाइव इअर प्लान में जो आंकड़े रखे थे उन आंकड़ों में कमी कर दी और उन आंकड़ों में कमी बिना किसी बेसिस के कर दी, बिना किसी कारण के कर दी और बद-किस्मती यह है कि कमी करने के बाद जो बचे हुए आंकड़े थे वे आंकड़े ठीक प्रकार से पूरे युटिलाइज़ नहीं किये जा सके। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार जब कहती है कि हम राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वह ( राज्य सरकार ) यह कहती है सिर्फ फीगर्स के बेसिस पर कि हमने ६५ प्रतिशत के हिसाब से खर्च करने की उम्मीद की है, तो मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जिस राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियल ज्यादा बताते हैं, जिस राजस्थान का औद्योगिक सर्वे करवा कर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, उस राज्य सरकार के पास औद्योगिक बजट की मद के अन्दर बचत देने को प्राप्त होती है ? इसका मतलब यह है कि कहने को तो हम औद्योगिक विकास की योजना बनायें लेकिन प्रत्यक्ष में उसको ठीक प्रकार से खर्च नहीं कर पाते हैं।

राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी के आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इस संबंध में जितना विकास करना चाहती थी उतना विकास नहीं किया गया है। इस बात की मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कॉटेज इन्डस्ट्री के अन्दर, लेदर इन्डस्ट्री के अन्दर और इन चीजों के अन्दर जितना जिस प्रकार से काम करना चाहिए था वह काम नहीं कर पाये हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी राज्य सरकार ने जो इन्डस्ट्रियल टार्गेट्स तैयार किये हैं वे सारे टार्गेट्स एचीव हो जायेंगे ? कहा जा सकता है कि इसमें इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स दो बनाने की योजना थी, लेकिन दोनों के बारे में बढ़े हैं और ज्यादा बना दिये हैं, लेकिन उसके कारण राजस्थान का औद्योगिक विकास नहीं होगा। राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा कॉटेज इन्डस्ट्री के जरिये, स्माल स्केल इन्डस्ट्री के जरिये, लेकिन कॉटेज इन्डस्ट्री और स्माल स्केल इन्डस्ट्री के नाते जहां राज्य सरकार के बजट में इस मद के अन्दर बचत होती है वह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर विशेष ध्यान नहीं है। और इस कारण से राज्य सरकार के मद में इस प्रकार की बचत हुई।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के किसानों के लिये जिसका सब्सिडियरी कहते हैं वह है पशु पालन का धंधा। मैं चाहता हूं कि हम उनको सही स्थिति का मूल्यांकन करें। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में पशु धन का विकास हो, राजस्थान की जनता चाहती है कि पशु धन का विकास हो, राज्य सरकार चाहती है कि पशु धन का विकास हो। लेकिन हम करते क्या हैं ?

( श्री भैरोंसिंह )

हमने कानून बनाया, उनकी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था की, केवल प्रचार सामग्री की व्यवस्था की। लेकिन प्रत्यक्ष में किया क्या ? आज राजस्थान का पशु-धन नष्ट हो रहा है। आप चाहे इसे मानें या न मानें, लेकिन इस बात का प्रमाण मौजूद है। आज जो जमीन की पैदावार घटी है वह इसलिये घटी है कि लोगों के पशु धन का ह्रास हो रहा है। पशुओं के खाद के कारण जमीन के कल्टीवेशन पर अच्छा असर होता है वह नहीं मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोगों के पास इतने पशु नहीं हैं और इस कारण से पूरी खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। हम यह कह सकते हैं कि पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की। हमने जगह जगह डिस्पेन्सरीज़ और हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। मैं समझता हूं कि माता के रोगी पशुओं की बीमारी को मिटाने के लिये आज भी बाहर के गांव वाले मदद करते हैं। महामारी को छोड़ कर सामान्य स्थिति में पशुओं की मृत्यु के आंकड़े निकाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आज जो पशुओं की डेथ रेट है वह पहले से ज्यादा है। आप यह कहेंगे कि हमने की-विलेज सेन्टर और हैल्थ सेन्टर कायम कर रखे हैं और जानवरों के लिये दुनिया भर की दवाइयां मंगाई हैं। लेकिन आज जो डेथ रेट है वह महामारी को छोड़ कर सामान्य स्थिति में जो ज्यादा डेथ रेट आई है उसका कारण क्या है ? जो चीजें डिपार्टमेन्ट के द्वारा जनता को देने की बात कहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं। कौन कहता है कि हमारे यहां पशु-धन का विकास हुआ है ? खाली आंकड़े बताने से काम नहीं चलेगा। मैं यह निश्चित तौर से कहता हूँ कि आज पशु-धन की कमी हो रही है।

खेती के नाम पर आपने गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि साधारण आदमी जिसके पास जमीन नहीं है वह पशु नहीं रख सकता। यही कारण है कि हमारे देश में पशु धन का ह्रास होता जा रहा है और इस कारण से खेती का विकास नहीं हो रहा है।

जब राजस्थान में किसानों के पशु-धन का विकास नहीं हो रहा है, उनके लिये फुल प्रोटेक्शन नहीं, राजस्थान में पूरा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं तो इस स्थिति में विचार करें कि आगे जो थर्ड फाइव इयर प्लान बना रहे हैं उसकी पूर्ति होगी या नहीं, तो कुछ संदेह होता है।

आपका विचार सही होगा, टार्गेट अचीव कर सकेंगे। लेकिन मैं सारी स्थिति को फिर से दोहराऊंगा। हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करके व्यवस्था की और मैं इस सदन में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था चाहूंगा और सदन भी चाहता है कि की-इन्डस्ट्रीज़ को छोड़ कर राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि राजस्थान में प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट को हर प्रकार से सेफगार्ड मिलेगा, कानून से मिलेगा। जितनी उचित सहूलियतें मिलनी चाहिये उतनी मिलेंगी, तो मैं समझता हूं हमारे लोगों के पास जितनी पूंजी है वह बाहर निकल आयेगी। अभी अभी मैंने बैंक्स के फिक्स्ड डिपोज़िट के आंकड़े देखे थे। मैं उनको यहां नहीं ला

( श्री भैरोंसिंह )

सका हूं। सन् १९५७ से ५९ में फिक्सड डिपोजिट के आंकड़े बढ़े हैं। सन् '५७ के बाद लोगों के पास जो पूंजी बढ़ी है उसका उन्होंने उपयोग नहीं लिया, उसको उन्होंने खर्च नहीं किया और न उसका इन्वेस्टमेन्ट किया बल्कि उसको बैंक्स में फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा कराया। यह इस बात का सबूत है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेन्ट करने से डरते हैं। सरकार पूर्णतया उनका उपयोग नहीं कर सकी। मैं चाहता हूं कि इस बात की स्पष्ट घोषणा को जाय कि प्राइवेट सेक्टर में जो पूंजी लगाने वाले होंगे उनको राज्य सरकार की ओर से उचित संरक्षण दिया जायगा। यह नहीं कि लेबर द्वारा एक्सप्लोइटेशन हो, जो आम धारणा है कि सरकार इस प्रकार की परिस्थिति बना कर पब्लिक सेक्टर में लाने की कोशिश करती है उसको मिटाना चाहिये....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें; पहले मैं थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहूंगा। फुल प्रोटेक्शन दिया जाय; इसको जरा स्पष्ट कर दें कि आपका इससे क्या मतलब है ?

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट के संबंध में मैं जिस प्रकार का आश्वासन चाहता हूं वह इसलिये चाहता हूं कि उसके पीछे एक जबर्दस्त साइकॉलोजिकल बेक ग्राउन्ड है। कोई भी आदमी जो पैसा खर्च करना चाहता है वह पैसा खर्च करने से पूर्व इस बात की व्यवस्था जरूर करेगा कि जो पैसा वह खर्च करेगा वह सेफ रहेगा और उसको उसका रिटर्न मिलेगा और रिटर्न उसको मिलेगा उसका उचित भाग उसको मिलेगा और उचित भाग नेशनल उपयोग में लगेगा। मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। राज्य सरकार कहेगी कि हम बसेज़ या ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन करना चाहते हैं। एक छोटी सी बात है, उसका नेशनलाइजेशन क्यों हो रहा है ? राजस्थान का ही नहीं; बल्कि इंडिया का मोटर व्हिकल एक्ट और उसके अन्तर्गत जो नियम हैं उनका पालन नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि सवारियों को असुविधा होती है, उसके लिये बसेज़ का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। नेशनेलाइजेशन करने के लिये बसेज़ खरीदी गई और वे एक वर्ष तक धूप में पड़ी रहीं। लोग कहते हैं कि परमिट जिन लोगों को मिला है उनको २००) रु० के हिसाब से कम्पेन्सेशन देने का प्रोविजन किया जा रहा है। आपने क्या प्रोविजन किया है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आपके यहां ७ कपड़े की मिल्स थीं। उनमें से ३ बन्द हो गई और बची हुई ४ में कपड़े का प्रोडक्शन धीरे धीरे गिर रहा है। यह किस बात की दलील है? यह इस बात की दलील है कि इन मिलों को चलाने-न चलाने के पीछे राजनैतिक बातें हैं। मैं ऐसी स्थिति में निवेदन करने की कोशिश करूंगा कि प्राइवेट सैक्टर में तब तक इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं होगा जब तक आप उसको सेफगार्ड नहीं करेंगे और लोग अपना पैसा इसमें नहीं लगायेंगे।

मैं स्वयं अभी हैदराबाद गया था। मैंने वहां के राजस्थानी भाइयों से बातें कीं और वहां पर मैंने मुख्य मंत्रीजी के भाषण को भी क्रोट किया और उनको कहा कि मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे संसार में भारत के बाहर भी जिन राजस्थानी

( श्री भैरोंसिंह )

व्यवसाइयों ने अपनी धाक जमाई है वे राजस्थान का औद्योगीकरण करने में पीछे क्यों रहते हैं। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में यह कहा राजस्थानी भाषा में कि "राजस्थान में जावां। कठै और अगर जावां तो रैवां कठै और रैवां तो खावां कठै"। इसका मतलब यह है कि यदि हम वहां जावें तो रहें कहां? इस प्रकार की बातें उन्होंने सब लोगों के सामने रखी थीं। आज राजस्थान के इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के सामने प्रोब्लम है कि कहां जावें, कौन रखने वाला है, कौन खिलाने वाला है? खिलाने से मतलब पेट भरने वाले से नहीं है बल्कि कौन प्रोटेक्शन देने वाला है? यह एक मोटा प्रमाण है कि राजस्थान के उद्योगपति जो संसार भर में अपना उद्योग चलाते हैं वे राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये सहयोग नहीं देते। इसका मतलब यह है कि या तो राज्य के प्रशासन में कमी है, या राज्य की नीति दोषपूर्ण है या भारत सरकार की नीति में कमी है जिसके कारण राजस्थान के उद्योगपति बाहर बैठे हैं और राजस्थान के औद्योगीकरण के लिये जितना सहयोग देना चाहिये उतना सहयोग नहीं दे रहे हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे क्षमा करेंगे, मैं फिर भी नहीं समझ पाया कि आपका तात्पर्य क्या है? क्या आप यह चाहते हैं कि इस बात का एलान कर दिया जाय कि बसेज़ का नेशनलाइजेशन नहीं किया जायगा? केपिटल इन्वेस्ट नहीं करने से आपका तात्पर्य क्या है? दूसरी बात, आपने टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज के बारे में कही उसको भी मैं समझ नहीं पाया। गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया उस पर आपको ऐतराज है क्या?

**श्री भैरोंसिंह** : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह सकता हूँ कि मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मोटर-बसेज़ का नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि बसेज का नेशनेलाइजेशन हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी यह घोषणा करें या नहीं करें पर मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं कि यह वह क्षेत्र है जिसमें पब्लिक पैसा लगा कर, प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा कर इस इन्डस्ट्री को डेवलप कर सकती है और उसको अवसर देना चाहिए। मोटर ट्रान्सपोर्ट एक इस प्रकार की इन्डस्ट्री है, जिसका डेवलपमेंट वह प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा कर सकती है, पब्लिक सेक्टर में करे या नहीं करे और जो पैसा लोगों के पास पड़ा है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है।

दूसरा प्रश्न सूती मिलों के वास्ते है। सूती मिलों के वास्ते मैंने यह नहीं कहा कि सरकार को सूती मिलें नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन जो सूती मिलें बन्द हुई हैं, उसका क्या कारण है? राजस्थान में सूती मिलें बंद हुई हैं। उन्हें राजस्थान सरकार ने टेकओवर कर लिया हो, इसलिए बन्द नहीं हुई लेकिन राजस्थान में सूती मिलें चालू हों और जो चालू हैं उनका काम ठीक प्रकार से चले, उसके सम्बन्ध में जो राज्य सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। मैं कह सकता हूं अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी सुनना चाहते हैं, तो भीलवाड़ा में जो सूती मिलें बन्द हुई हैं, कोटा में जो सूती मिलें बन्द हुई हैं, और जो नये लाइसेन्स दिये गये हैं, और उदयपुर के अन्दर टेक्सटाइल मिल के लिए लोन दिया है, जो सहायता दी जा रही है उतनी सहायता की रकम से जो

( श्री भैरोंसिंह )

राजस्थान के अन्दर मिलें बेकार पड़ी हैं, जो चालू थीं और अब बन्द हो गई हैं या बन्द होने वाली हैं, इन सब मिलों को सहायता दी जाती तो राजस्थान में ये सूती मिलें चालू रहतीं और जो प्रोडक्शन आप अकेली मिल में करना चाहते हैं उससे कई गुना प्रोडक्शन ये सारी मिलें मिल कर कर सकती थीं। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है । उदयपुर में टैक्स-टाइल मिल लगानी है, तो लगा दी और बाकी सूती मिलें चली जायं, तो चली जायं, उसकी कोई चिन्ता नहीं । उस स्थिति में मैं कह रहा था कि आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सका है, तो उसका कारण यही है कि लोग सोचते हैं कि मिलें मेरे पैसे से चलती रहें, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सरकार का भी फर्ज होता है और वह फर्ज है पनपाने का, अगर सरकार इसके लिये चेष्टा कर सकती है तो चेष्टा करनी चाहिये ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकारी रिसोर्सेज के ऊपर आने का प्रयत्न करूंगा। सरकार ने अपनी योजना २१४ करोड़ रुपये की बनाई है। २१४ करोड़ रुपये की योजना में मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े बताये हैं उनके आधार पर कुछ करोड़ रुपये हम स्टेट रिसोर्सेज के बेसिस पर इकट्ठे करने वाले हैं। यह बात सही है कि राजस्थान में ८१ करोड़ स्टेट रिसोर्सेज के नाम पर इकट्ठे करने के पहले हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि हम राजस्थान में कितने और किस प्रकार के टैक्सेशन ला रहे हैं ? राजस्थान में जो सरकारी टैक्सेज़ होंगे वे २० करोड़ के टैक्सेज़ होंगे।

पिछली बार जब राजस्थान सरकार ने सेकिन्ड फाइव इयर प्लान प्रस्तुत किया था तो (सरकार ने) कहा था कि हम ६ करोड़ के टैक्स लगायेंगे । दूसरी पंचवर्षीय योजना कम्पलीट हो गई और जो ६ करोड़ का टार्गेट राज्य सरकार का टैक्सेशन का था वह बढ़ कर १३ करोड़ तक पहुँच गया। राज्य सरकार ने ६ करोड़ की योजना बना कर १३ करोड़ के टैक्स वसूल किये। अब सरकार कहती है कि पांच वर्ष के अन्दर २० करोड़ के टैक्स सरकार लगायेगी। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि यह २० करोड़ के टैक्स बढ़ कर ३० करोड़ तक पहुंचेंगे। आज जो प्लान है, कोई भी यह नहीं कह सकता कि इसमें कितनी कमी होगी, कितना प्रेशर काम में आयेगा, कौन सी स्टेट ज्यादा ताकतवर होगी ? जिस तरह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान की पर-कैपिटा इनकम के बेसिस पर हमारी योजना ४०५ करोड़ की हो जानी चाहिये वह योजना घटा कर २५७ करोड़ की बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि २१४ करोड़ रुपये की योजना बढ़ा कर ३०० करोड़ की योजना तक पहुँच जाय। जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश और बाकी की स्टेट्स की बातें करते हैं और जिस प्रकार की धमकियां, धमकियां नहीं, जिस प्रकार के आग्रह भारत सरकार के सामने करते हैं उससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि आज हमारे मुख्य मंत्रियों की दौड़ है, राजस्थान की सरकार और प्रान्तीय सरकारों की दौड़ है। इसके अन्दर राज्य सरकार जीतती है या बाकी की सरकारें जीतती है, यह सदन के देखने का काम है। मुख्य मंत्री जी को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि दूसरे प्रान्तों की दौड़ में, जिस प्रकार का सहयोग सदन से लेना चाहेंगे उतना सहयोग देने के

( श्री भैरोंसिंह )

लिये यह सदन हर समय उनके साथ होगा....

**एक माननीय सदस्य** : टैक्स लगाने में ?

**श्री भैरोंसिंह** : टैक्स लगाने में नहीं ! मैंने कह दिया था कि जो २० करोड़ के टैक्स लगाने की बात है वह ३० करोड़ तक पहुंचेगी क्योंकि जो केन्द्रीय सरकार १,६५० करोड़ के टैक्स लगा रही है, उसके अन्दर ५५० करोड़ के टैक्स स्टेट के जिम्मे में आये हैं। राजस्थान के जिम्मे नहीं; समूचे स्टेट्स के जिम्मे ५५० करोड़ के टैक्स आये हैं। अभी अभी लोक सभा में केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने टैक्स के बारे में नीति बताई। उस समय डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्स की प्रोब्लम लोक सभा के एक माननीय सदस्य ने रखी ! उसका उत्तर मिला कि ऐसा लगता है कि एक टैक्स देने की जो ताकत होनी चाहिये, सामर्थ्य चाहिये, इस प्रकार की हमारी सामर्थ्य है, तो हमको टैक्स देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे प्रान्त की पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है, १६५७ से लेकर १६६१ तक, १६५६ से लेकर १६६१ तक, इन पांच वर्षों के अन्दर पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है। बाकी समूचे देश की पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है उसकी तुलना में जो टैक्सेशन का प्रोविजन है यह उसी अनुपात में है या नहीं ? मैं समझता हूं कि वह उस अनुपात में नहीं है। जब सरकार ने नो करोड़ के टैक्स लगाये तो थोड़ी इनकम बढ़ी है। वे इनकम के आंकड़े देखें और टैक्सेज़ के आंकड़े देखें। पहले पर-कैपिटा इनकम जो २४४ थी यह २४४ से बढ़ कर २६४ हो गई। २६४ पर-कैपिटा इनकम के आधार पर सरकार कहती है कि पर-कैपिटा बेसिस के अनुसार यदि सारा प्लान ४०५ करोड़ का हो जाय तो उस स्थिति के अन्दर ३३१ पर-कैपिटा इनकम हमारे प्रान्त की होगी। अगर वह नहीं होती है तो उस स्थिति में २८५ पर-कैपिटा इनकम होगी। इनका मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि केवल २० पर-कैपिटा इनकम की वृद्धि हुई, २० करोड़ के टैक्स लगाने के बावजूद। जब कि पहले १३ करोड़ के टैक्स लगाने के बाद २० रुपये आमदनी में बढ़े हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि २० करोड़ के टैक्स लगाने के बाद भी २० रुपये पर-कैपिटा इनकम में और बढ़ेंगे। अब कैसे कह सकते हैं कि २० करोड़ के टैक्सेज़ का प्रोविज़न रख कर उसको ३० करोड़ तक नहीं बतायेंगे ? इसका मतलब यह है कि जो टैक्स लगा रहे हैं वह जो आमदनी में वृद्धि हुई है उसके अनुपात से नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हेवी टैक्सेशन हमारी जनता पर होगा, आज राज्य सरकार भले ही कह दे कि हम २० करोड़ के टैक्सेज़ लगायेंगे।

उसके साथ ही मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की आज तारीफ करते हैं, जिसके लिए सारा विश्व, सारा देश राजस्थान की ओर आंख उठाये देख रहा है। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर यह कहें कि एक हजार, दो हजार के टैक्स लगावें, तो यह बात नहीं है, लाख, दो लाख के टैक्स लगायें, यह बात भी नहीं है, इस योजना काल के अन्दर, आज तो नहीं, क्योंकि आज इलेक्शन का प्रलोभन सामने है, अक्टूबर, नवम्बर में पंचायत समितियों के इलेक्शन करने वाले हैं, इस कारण पंच और

( श्री भैरोंसिंह )

सरपंच को कॉम्प्लेक्शन है कि अगर टैक्स लगाये तो अक्टूबर, नवम्बर में वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए पांच वर्ष का पीरियेड जो इलेक्शन के बाद आने वाला है उसमें जो रिसोर्सेज़ कट करके राजस्थान सरकार ने ले लिये हैं और जो २० करोड़ के टैक्स राजस्थान सरकार ने लगाये हैं उसको कम नहीं कह सकता। उसके अतिरिक्त तीन करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ के टैक्स, ये लोकल बॉडीज़, म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें, ये सारी मिल कर लगायेंगी, जो टैक्स गरीब जनता को देना है। इसके कारण सारे लोगों पर अतिरिक्त भार आयेगा।

भारत सरकार का १,६५० करोड़ का इनडाइरेक्ट टैक्स, राज्य सरकार का २० करोड़ का टैक्स और लोकल बॉडीज़ का इस प्रकार का टैक्स, राजस्थान की गरीब जनता की जो पर–कैपिटा आमदनी बढ़ रही है उसके अनुपात में बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार चाहे उसको किसी प्रकार मजबूर करे लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार के टैक्सेशन से निश्चित रूप से खराब करेगी। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की ५५० करोड़ की डेफिसिट फाइनेन्सिंग योजना है और आज की स्थिति में जो ५५० करोड़ की डेफिसिट फाइनेन्सिंग योजना है उसके लिये यह नहीं कह सकते कि यह इतनी ही रहेगी! यह आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि आज जो इन्टरनेशनल सिचुएशन है उसके आधार पर २,२०० करोड़ की जो फॉरिन एड की उम्मीद करते हैं उसमें किसी समय भी कमी आ सकती है। क्योंकि उनका जो एड के कारण डिक्टेशन है उस डिक्टेशन को मानने से इन्कार कर देंगे उस समय ही यह एड देने से इन्कार कर देंगे। उस स्थिति में जो डेफिसिट योजना है वह और ज्यादा बढ़ेगी और लोगों के सामने मंहगाई की प्रोब्लम खड़ी होगी। उस समस्या को आप नहीं रोक सकेंगे। पिछले वर्षों में मंहगाई बढ़ी है जिसके आधार पर हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ ने स्ट्राइक की थी। राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ स्ट्राइक करें या न करें लेकिन जो उनकी तनख्वाहों में कमी है उसके कारण दुःखी हैं। राजस्थान की गरीब जनता की मंहगाई के कारण दशा गिर रही है। जो मंहगाई बढ़ रही है उसको आप कन्ट्रोल नहीं कर सके, प्राइसेज़ के स्टेबिलाइज़ेशन के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर सके, राजस्थान के लोगों को सस्ती चीजें नहीं दे सके। इस सारी स्थिति में हम कहते हैं कि लोगों को इन्कम के जरिये देने में और बढ़ती हुई प्राइसेज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं यह समझता हूं कि आप तभी यह कर सकते हैं जब आप प्राइसेज़ को स्टेबल कर पायेंगे। बगैर प्राइसेज़ को स्टेबल किये आप लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकते और इसी प्रकार से इन्क्रीज़ इन प्राइसेज़ जो हो रही है उनको किसी भी प्रकार से बगैर प्राइसेज़ स्टेबिलाइज़ किये दूर नहीं कर सकते।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि प्राइसेज़ को स्टेबिलाइज करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की व्यवस्था करें जिसके आधार पर आप रेट्स

( श्री भैरोंसिंह )

को अपने कन्ट्रोल में कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि जिस प्रकार आपने फूड ग्रेन पर स्टेट ट्रेडिंग की बात अपनाई थी उसी प्रकार रेंट को चैक करने के लिये आप उसी प्रकार के तरीके को अपनाएं। सरकार इसको एसेन्शियल कॉमोडिटीज़ को कन्ट्रोल करके इसको रोक सकती है। मैं मानता हूँ कि इससे करप्शन अवश्य बढ़ेगा। मैं यह कहूंगा कि इसके लिये हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करनी चाहिये कि ऑल इन्डिया बेसिस पर कोई कार्य करें जिससे हम प्राइसेज़ को स्टेबिलाइज़ कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम गरीब लोगों को सस्ती चीजें नहीं दे सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमको अपने जो टार्गेट्स तय किये हैं उनमें कुछ खामियें नजर आती हैं और उनको बताने के लिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं यह कहूंगा कि सोशियल सर्विसेज़ में कुछ कार्य किया है और एजुकेशन में भी इस थोड़े समय में कुछ कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सोशियल सर्विसेज़ के बारे में कुछ कहूँगा और यह कहना चाहूंगा कि जितना टार्गेट रखा उसको पूरा किया; यह कहा जाता है। मैं मुख्य मंत्रीजी को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जितनी प्राइमरी स्कूलों को खोलना था और जितनी हाई स्कूल्स व हायर सेकिन्डरी और बेसिक स्कूल्स खोलनी चाहिये थी उसके लिये जितना टार्गेट था उसको पूरा किया और जितने लोगों को शिक्षित होना चाहिये उसके लिये प्रयत्न किये। लेकिन केवल शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूलें खोल दें या हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोल दें या थर्ड इयर की क्लास खोल दें या बेसिक एजुकेशन चालू कर दें! अगर शिक्षा का केवल यही मतलब है तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की सरकार इसके लिये अवश्य धन्यवाद की पात्र है और मुख्य मंत्री भी। लेकिन आज हमारी भारत सरकार की नीति और भारतवर्ष के शिक्षा शास्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में केवल एक बात कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि आज हमारी शिक्षा का स्तर है वह लोगों को बेकार बनाता है और लोगों में बेकारी पैदा करता है। उनमें जो नैतिक पतन होता है उसको छोड़ दें! बेकारी को रोकने में शिक्षा ने क्या सहयोग दिया है? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। मैं यह कहूंगा कि बेसिक ट्रेनिंग के लिये ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत है। मगर आपके यहां आप खुद कहते हैं कि ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं। आज राजस्थान के सामने इस वर्ष हायर सेकन्डरी के रिज़ल्ट्स रहे हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि या तो इसकी तरफ छात्रों का मेन्टल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है या एग्जामिनर्स की गलती है या कोई एडजेस्टमेंट की गलती है या यह ग्राउन्ड ठीक नहीं है। आज सरकार शिक्षा देती है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग यही सर्विस की सोचते हैं। अगर कोई खाती का काम करने वाले का लड़का है या किसी बंजारे का लड़का है तो वह मैट्रिक पास करने के बाद राज नहीं बनेगा। खाती का लड़का कभी भी खाती का काम करना पसन्द नहीं करेगा। वह तो बाबू बनना पसन्द करेगा। इसी प्रकार

( श्री भैरोंसिंह )

बंजारे का लड़का है वह भी बाबू बनने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आज हमारी हायर सेकन्डरी की व्यवस्था है उसके बारे में कितनी कमी है और कितनी कमी पूरी कर पाये हैं, मैं कहूँगा कि जितना कहा जाए उतना कम नजर आता है।

इसी प्रकार चिकित्सा संस्थाओं के आंकड़े लगाने में समय लगेगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हॉस्पिटल्स आदि के विषय में ऊपर के पेज पर बनाया गया है उसको पढ़ा जाय तो ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान में कोई बीमार नहीं रहा और राजस्थान में कोई बीमारियों को दूर करने लिये दुनिया भर के डॉक्टर्स इक्ट्ठे हो गये हैं। लेकिन आगे चल कर हम देखें तो हमको मालूम होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी ७५० डॉक्टरों की कमी रहेगी। इन ७५० के फिगर्स में गलती रह सकती है। अगर कोई गलती हो तो मैं उसमें करेक्शन करने को तैयार हूँ। ६५० हैं या ७५० हैं; मुझे पूरा याद नहीं है कि ७५० हैं या ६५० हैं। लेकिन यह सत्य है कि डॉक्टर्स की कमी तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी रहेगी। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब डॉक्टर्स नहीं होंगे तो कौन से हॉस्पिटल्स चलेंगे ? कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स आपने बनाये हैं जिनमें बिना डॉक्टरों के वे चलेंगे ? आप कहते हैं कि कम्पाउन्डरों की कमी है, नर्सों की कमी है, मिड वाइव्ज़ की कमी है। ये सारी कमियें आपके सामने हैं। जब डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होगा तो हॉस्पिटल क्या होगी ?

मैं माननीय चीफ मिनिस्टर की बात को मंजूर करता हूँ। वे कहते हैं कि हम मेडिकल एज्युकेशन के लिये कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। जयपुर और बीकानेर में मेडिकल कॉलेज हैं और अब जोधपुर और उदयपुर में खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे जल्दी ही इन स्थानों पर भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अगर सरकार यह चाहती है कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना है तो सोशियल सर्विसेज़ में इसके लिये युनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी खोले और मेडीकल कॉलेजेज खोले जावें। इस प्रकार को राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

आयुर्वेद को मैं समझता हूँ कि सरकार ने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है और इसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। जितना एलोकेशन पिछले और पहली योजना के अनुपात से बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ पाया है।

कभी कभी माननीय मुख्य मंत्री ने आज नहीं राजस्थान के बाहर भी और सदन में भी कई बार बताया है कि राजस्थान में कुछ विकास की बातें हो रही हैं। वे उदयपुर के प्लान और तांबे की खानों की तरफ और हनुमानगढ़ में फर्टिलाइज़िंग फैक्टरी की बातें करते हैं। मुझे इत्तला मिली है और अगर मेरी इत्तला गलत हो और मैं गलत कहता हूं तो वे मुझे करेक्ट करेंगे, वे श्री शांतिप्रसाद जैन से समझौता करने की कोशिश में हैं और करने वाले हैं और वह समझौता जल्दी ही हो जावेगा। भारत सरकार की तरफ से हमारी सरकार श्री शांतिलालजी से बातचीत में आगे बढ़ सकती है। मगर मैं हमारे राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा और वह यह कि

( श्री भैरोंसिंह )

आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि वे लोग अधिक मुनाफा पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। जिस समय आप उनसे बात करें उस समय उनसे उचित मुनाफे की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में फर्टिलाइज़र की कमी है और इसकी खपत ज्यादा होगी। यदि एग्रीकल्चरिस्ट्स को ज्यादा रेट पर मिलेगी तो फिर वे लोग नहीं लेंगे और आगे चल कर झगड़ा हो सकता है। इसलिये, इसके लिये मैं समझता हूं कि पहले ही माननीय मुख्य मंत्री व्यवस्था करेंगे।

अन्त में, क्षमा चाहूंगा कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है लेकिन एक विषय पर मैं अपने विचार ५ मिनट में सदन के समक्ष व्यक्त करूंगा। चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने भी इसके बारे में अन्त में ही कहा था इसलिये मैं भी इस पर अन्त में ही कहूंगा और वह है डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन।

जिस समय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कल्पना हमारे सामने आई हम सभी ने विचार किया था कि हमारा देश इस प्रकार के परिवर्तन से समूचे विश्व के सामने एक नमूना प्रस्तुत करेगा। मैं समझता हूं कि इसका जो कानून बना उस समय लोगों ने इसमें जो कमियें थी बताईं। कानून बना उस समय सरकार की ओर से दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसमें बताया गया कि प्लान के एग्ज़िक्यूशन में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण से बहुत फायदा होगा। मैं समझता हूं कि इसके लिये हमें लोगों को समझाने की जरूरत थी और जब लोग यह समझने लगें कि यह प्लान हमारा है, यह स्कीम हमारे यहां से पास होती है, हम इसको बनाते हैं और इससे जो फायदा होगा वह हम लोगों को होगा, अगर यह होता तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं अवश्य बढ़ते। बाहर के लोगों को जब बताया जाता है कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन में तरक्की की है तो मैं कहूंगा कि लोगों को किस प्रकार से रटाया जाता है और रटा कर कहा जाता है कि अमुक अमुक गांव में इस प्रकार कार्य किया गया है और इस प्रकार के इनिशियेटिव लिये गये हैं। लेकिन हमें एक बात को देखना होगा। पिछले हमारे जो अनुभव हैं और जिसके बारे में मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने भी महसूस किया और अभी कुछ समय पहले फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था और उस प्रस्ताव में उन्होंने मांग की थी कि जिला स्तर पर जितने डेवलपमेन्ट्स के काम हैं वे जिला परिषद् के हाथ में सौंप दिये जायं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उसका विरोध किया और उसके पीछे यह मुख्य बात उन्होंने कही कि वह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है। उन्होंने एक बात यह भी कही कि जिला परिषद् की कुछ बातों को हम नहीं मान्य करते। क्यों नहीं मानते? उसके अन्दर एम. एल. एज़. होते हैं, पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं और बाकी के लोग होते हैं, जिनका इलेक्टोरेट से टच है। जैसे एक अमुक गांव में यदि औषधालय खोलना है तो बाकी के लोग कहेंगे कि वहां क्यों नहीं? बाकी की लिस्ट में पीछे राज्य सरकार न खोले तो वे कह सकते

( श्री भैरोंसिंह )

हैं। डेमोक्रेसी में बहुमत से कोई भी चीज़ तय करने का सिद्धान्त मान्य है। उसको डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की आड में पूरा नहीं कर सकें और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसको महसूस किया है कि नहीं कर पाये। उनका महसूस करना उचित है, नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये ?

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी राजस्थान का विकास लोगों की नजरों में नहीं आया। जनता पर जो जिम्मेदारी डाली उसने टैक्स और अन्य साधन दिये।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

पांच मिनट और लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले पांच मिनट कहा और उनको कायम रखूं....

खैर, आरम्भ रखिये।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता को कई कष्ट हुए हैं, फिर भी जनता ने सहयोग और कॉन्ट्रिब्युशन के रूप में हमारे प्लान्स को पूरा करने में मदद दी है, सहयोग दिया है, टैक्स दिया है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की असफलता; विकास होगा। ऐसा लोगों को आज तक भी आभास नहीं हुआ, उस असफलता की जिम्मेवारी सरकारी मशीनरी द्वारा लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के जो संचालक हैं उनके ऊपर डालने की कोशिश की। संचालक का मतलब हर उस व्यक्ति से है जो हमारे देश का, राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। उस प्रशासन को बनाये रखने के लिए, एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी के नाम पर, सरकारी मशीनरी के नाम पर, बोझ लोगों पर बेजा टैक्स का भार, डाल रखा है उनके नाम पर मैं कहता हूं कि जिन चीजों को डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के जरिये अचीव करना चाहिये था, उनको एचीव नहीं किया है और इसके लिए जो अनप्लेजेन्ट बात नहीं कहनी चाहिये मुझे सदन में, उसको कहने के लिए तैयार हूं। जिसकी आलोचना होगी लेकिन विरोधी दल में बैठ कर यदि मुझे अनप्लेजेन्ट ड्युटी भी करनी पड़े तो मुझे उसके लिए कोई डर नहीं है और इसलिए मैं कहूँगा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की हवा हमने बनाई। वह स्पिरिट राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के कारण जनता में ठीक तरह से फैल नहीं पा रही है और मशीनरी के कारण धीरे धीरे फैल्योर हो रही है। आज जिला परिषद् और पंचायत समितियों के प्रधान राजस्थान के विकास की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार से ही दिल्ली से टार्गेट निकलते हैं, दिल्ली से निकल कर राजस्थान सचिवालय के पास पहुँचते हैं और राजस्थान सचिवालय से निकल कर कलेक्टर के दफ्तर में पहुंचते हैं। कलेक्टर के दफ्तर से निकल कर बी. डी. ओ. की जेब में चले गये और बी. डी. ओ. ने कह दिया, पांच हजार का काम करना है तो कर लो। आप फिर कैसे कहते हैं कि ये-नीचे बनाई जाती हैं ? आपने तो रुपया और क्षेत्र तय कर दिया और बांटने का क्षेत्र पंचायत समितियों को दिया और बांटने तक ही सीमित रहा। यदि उन्हीं ऊपर से बनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायत समितियां

# Page No.69



( श्री भैरोंसिंह )

हैं तो आज पंचायत समितियां भी इसी ब्यूरोक्रेसी के कारण से असफल रही हैं। जो इन्डिपेन्डेन्ट इनिशियेटिव इनके द्वारा लोगों में पैदा करना चाहिये था वे नहीं कर सकी हैं और नहीं कर पा रही हैं। जो जनता में भावना इनके द्वारा निर्माण की जानी चाहिये थी वह भावना भी गिरती जा रही है। ऐसी चीजों में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन प्रमुख चीज़ है। उसके पीछे इतिहास है, इससे डेमोक्रेसी का पूरा सम्बन्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बारे में विचार करने के लिए फुलफ्लेज्ड डिबेट रखनी चाहिये जिससे कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जा सके। यदि डिबेट नहीं रखी जाये तो निवेदन करूंगा कि इस मूल प्रश्न पर सोचने की चेष्टा करने की कोशिश करनी चाहिये कि प्लान को इस प्रकार से एग्ज़ीक्यूट भी कर सकेंगे या नहीं ? यदि इस चीज़ पर विचार किया गया तो यह माना जा सकता है कि हम इसको काफी लागू कर सकेंगे। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जनार्दनराय नागर।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय आयोजन का जो निवेदन मुख्य मंत्री महोदय की ओर से इस सदन में जानने को मिला उस पर यह कहा जाना बिल्कुल उचित है कि हमारे राजस्थान के आयोजन का इस महत्वपूर्ण रूप से सरकार की ओर से सम्पूर्ण निवेदन था जो सरकार की ओर से पहली बार निवेदन किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय आयोजन की मूलभूत समस्या और उलझन को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, स्पष्ट रूप से, मैं यह मानता हूं, प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने रखा है। उससे हमको तृतीय पंचवर्षीय आयोजन के विषय में विचार करने के लिए न केवल एक दृष्टि प्राप्त हुई है लेकिन हम यह समझ गये हैं कि हमारा राजस्थान आयोजन की दृष्टि से किधर प्रगति कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान तृतीय आयोजन में प्रवेश कर एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन से राजस्थान में विकास का एक युग, वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है।

पहला पंचवर्षीय आयोजन ऐसा था जिसे मैं एक दुर्भाग्य आयोजन कहता हूं। वह इतना सीमित था, कम था उस समय राजस्थान के बनते हुए वातावरण में और उसकी आवश्यकता की दृष्टि से। मैं समझता हूं पहला पंचवर्षीय आयोजन काफी विस्तृत होना चाहिये था। आयोजन की दृष्टि से, मैं समझता हूं, काफी विकास की आधार-शिला होनी चाहिये थी। लेकिन वह नहीं हो सकी।

दूसरे आयोजन की जो आधारशिला थी वह साहसिक थी। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के साथ में हमने न केवल राजकीय प्रशासन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया बल्कि राजस्थान के बहुत ही विकास की आवश्यकता थी, आधारभूत मनोरथ थे राजस्थान के उनको हमने जाग्रत किया, सोचा, समझा और इस प्रकार का एक प्रबन्ध विकास की दृष्टि से राजस्थान में हमने करने की कोशिश की जिससे राजस्थान तृतीय

( श्री जनार्दनराय नागर )

पंचवर्षीय आयोजन के द्वारा विकास के निश्चित भविष्य पर आकर खड़ा हो गया ।

आज तृतीय पंचवर्षीय आयोजन का जो मशविदा हमारे सामने है और जिस पर हम आज विचार करने जा रहे हैं । हम में स्वयम् के प्रति शंका नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय आयोजन पर विचार हो रहा है, अनेक स्थलों और जगहों से विचार चलते चल रहे हैं । एक हिम्मत के साथ तीसरे आयोजन को करने जा रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजन राजस्थान को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में, विकास के एक निश्चित भविष्य पर लगायेगा । जब हमारी इस ओर निश्चित जिम्मेदारी है तो हमारे विकास और साहस की दृष्टि से राजस्थान एक ऐसे प्रसंग पर चला आ रहा है जिसमें सदन में न केवल विचार करना पड़ेगा बल्कि उसके विकास के लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा । तृतीय पंचवर्षीय आयोजन हमारी परीक्षा का एक आयोजन है और इस आयोजन पर हमारे आगे के आयोजन निर्भर करते हैं ।

आयोजन के अनेक मुद्दे हैं । जो विकास के कार्य राजस्थान में चालू किये हैं उनका तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में समाहार होता है ।

( २. ३०. म. प. )

दूसरी पंचवर्षीय योजना की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें तीसरी योजना में ली जा रही हैं । इसी तरह से थर्ड फाइव इयर प्लान में भी फोर्थ फाइव इयर प्लान का कोई न कोई आधार मान कर चल रहे हैं । समूचे राज्य के विकास की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजन है । इसी पर मैं समझता हूं हमारे राज्य के विकास का भविष्य और सर्वांगीण विकास का भविष्य निर्भर है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो हमने मुख्य मंत्री महोदय के मुख से चिन्ता के साथ सुनी वह यह कि राजस्थान नहर पर जो ४५ करोड़ रुपया हम खर्च करना चाहते हैं उसके बारे में निश्चित स्थिति हमारे सामने नहीं है । जहां तक इस नहर के निर्माण का सवाल है इसके बारे में जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा उसको समस्त माननीय सदस्यों ने चिन्ता के साथ सुना है । राजस्थान नहर केवल राजस्थान का ही एक प्रोजेक्ट है, इस प्रकार मान कर चलना, ऐसी परिस्थिति भारत सरकार के सामने नहीं होनी चाहिये । यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से भारतवर्ष के सबसे ऊंचे और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है । जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा यह हमारा राष्ट्रीय महत्व का और राष्ट्रीय स्तर का प्रयोग है । यदि इसके पूर्ण करने में जो आर्थिक प्रश्न है वह यदि हमारी तृतीय योजना में मिली धन राशि से होता है तो मैं समझता हूं राजस्थान की अपनी जो आयोजना है इसके कारण वह समाप्त हो जायेंगे । इससे हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो विकास की आशायें हैं, हमारे जो निश्चय हैं उनमें बहुत पिछड़ाहट आ जायेगी । स्वाभाविक रूप से इसको अधिक विस्तृत और विकसित की जानी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात रखें कि जहां तक

( श्री जनार्दनराय नागर )

इस नहर का सवाल है वह भी उसी प्रकार का सवाल है जिस प्रकार का गांधी सागर बान्ध का, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का सवाल है। इसलिये इनके बारे में भारत सरकार को और प्लानिंग कमीशन को विशेष तौर से प्रावधान करना चाहिये। हमारी हालत ऐसी नहीं कि इसके लिये हम दूसरी मदों को, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि को रोक दें या इनका विस्तार कम करें। इसलिये सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिये कि हम इस मामले में हमारे मुख्य मंत्री महोदय के हाथ मजबूत करें ताकि वे मजबूती से राजस्थान के केस को प्लानिंग कमीशन के सामने व भारत सरकार के सामने रख सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी सावधान करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान नहर का खर्चा हमारे तीसरी प्लान पर पड़ा तो हमारा जो प्लान का विस्तार होगा वह आधा ही होगा और वैसी हालत में जो विकास की आशायें हम लगा कर बैठे हैं वे नहीं हो सकेगी। आज हम राजस्थान में विकास की दृष्टि से जनता में काफी जोश उत्पन्न कर पाये हैं। इसके बारे में जो इम्पेट्स लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से हुआ है, जो साहस उत्पन्न हुआ है वह हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक एक तहसील और हरएक जिला, हर पंचायत आदि में उत्पन्न कर। पाये हैं। अगर हमारी राजस्थान नहर का आयोजन का प्रावधान हमारी योजना में से ही करना पड़ा तो यह जो जनता में पंचायत समितियों और जिला परिषदों से जो यह जागृति आई है और उन्होंने यह निश्चय घोषित किया है कि जितना अनुदान उन्हें तीसरी योजना के अन्दर अलग अलग विकास की दृष्टि से मिलेगा उतना ही धन वे जनता से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उसमें कमी आ जायेगी। राजस्थान नहर का मामला अगर लिया जा सकता है तो लिया जाना चाहिये और यदि नही लिया जा सकता है तो नहीं लिया जाना चाहिये और मीडियम और माइनर इर्रिगेशन को काफी महत्व दिया जाना चाहिये, यह भी यहां कहा गया। इससे कुछ ऐसा भ्रम होता है कि राजस्थान नहर ऐसी चीज है जिसको हम रोक सकते हैं और उससे ज्यादा यहां मीडियम और माइनर इर्रिगेशन के लिये स्कोप है। उनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मीडीयम और माइनर इर्रिगेशन के बारे में कुछ सोच–समझ कर बातें कही हों, लेकिन मैं माननीय मित्र को यह सूचना देना चाहता हूँ कि माइनर और मीडियम योजनाओं के बिना तो यह प्लान अधूरा ही है। राजस्थान नहर को हम इसके साथ नहीं मिला सकते। यह तो सारे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। सारे एशिया में राजस्थान नहर के मुकाबले और कोई दूसरी नहर नहीं होगी। इससे परोक्ष रूप से सारे भारतवर्ष को लाभ होने वाला है। इसके लाभ की तुलना म लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई की योजना का हम ज्यादा महत्व देकर चलें, यह उचित नहीं है : यह तो आधारभूत आयोजन है। इसे आयोजन की दृष्टि से विचार करना नहीं कहा जायेगा। यह निश्चित मान कर चलना चाहिये कि राजस्थान नहर का जो हमने काम शुरू कर दिया है उसको किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते। यदि इसके लिये

( श्री जनार्दनराय नागर )

रुपया नहीं मिलता है तो इसका भार हमारे आयोजन पर आता है। जब हमने राजस्थान नहर को शुरू कर दिया है तो इसको बराबर जारी रखना चाहिये जिस पर राजस्थान का काफी बड़ा विकास और भविष्य निर्भर करता है।

राजस्थान का विकास खास तौर से दो बातों पर निर्भर करता है एक तो विद्युत शक्ति पर और दूसरा कृषि के विकास पर। जहां तक राजस्थान नहर का ताल्लुक है, यह कृषि योजना के अन्तर्गत आता है। इसका लाभ बहुत अर्से के बाद मिलने वाला है। जहां तक बड़ी योजनाओं का संबंध है उसका लाभ एक युग के बाद मिलता है। आप अमेरिका की टीनेन्सी वेली की योजना को ही ले लीजिये। उससे दो जेनरेशन के बाद लाभ मिलने लगा है। आज उससे अमेरिका के उस हिस्से में काफी परिवर्तन आ गया है। बड़े बड़े राज्य वहां कायम हो गये हैं। हमारी राजस्थान नहर योजना भी उसी प्रकार की योजना है। इससे भारत के इस अंचल को वह हराभरा करेगी और यहां के लोगों की आर्थिक क्षमता है उसमें वह वृद्धि करेगी।

इसके अतिरिक्त जहां तक लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई योजनाओं का संबन्ध है, हमारी इस तीसरी योजना में काफी प्रावधान किया गया है : सिंचाई के बड़े कामों के लिये ३२ करोड़ रुपया माइनर इर्रिगेशन के लिये, १५ करोड़ रुपया मैं समझता हूं यह काफी धनराशि है। यह ठीक बात है कि हमारे यहां कुछ हिस्सा ऐसा है जहां मध्यम सिंचाई योजना से काफी लाभ हो सकता है। उदाहरणार्थ; ऐसी योजनाओं की संख्या १८ के करीब है जिनको हम मध्यम सिंचाई योजना कह सकते हैं। जैसे खारी फीडर योजना, बड़ा गांव ब्रिज की योजना ये जो मेरे क्षेत्र के अन्दर हैं जिनकी मुझे जानकारी है, वह मैं अर्ज कर रहा हूं जिनको हम मध्यम श्रेणी की योजना कह सकते हैं। इसी दृष्टि से यहां का समुचित विकास हो सकता है। ये योजनायें मन्जूर हो चुकी हैं। खारी फीडर के बारे में सात लाख रुपये की योजना है। इसको राज समन्द से भरा जायेगा। इससे १८.१६ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। जैसी कि मुझे सूचना है इसको भारत सरकार ने मन्जूर कर लिया है और जल्दी से जल्दी इस पर काम-काज शुरू होने वाला है।

इसी तरह की योजना बड़ा गांव ब्रीज योजना है। बल्लभनगर ब्रिज योजना है इसको भी आर्थिक दृष्टि से उपयोगी मानता हूं। इसी प्रकार की १८.१६ मध्यम श्रेणी की योजनायें हैं। कुछ तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हो गई थी और कुछ थर्ड फाइव इयर प्लान में शुरू की जायेंगी। इसलिये यह कहना कि मध्यम और लघु सिंचाई योजना के लिये कोई प्रावधान नहीं है, उचित नहीं है।

जहां तक इस तीसरी योजना का ताल्लुक है यह कोई सेक्रेटरीज़ ने बना कर रख दी हो, यह बात नहीं। हमारी यह योजना हमारी हर पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् से होकर आई है। उसके बाद प्लानिंग बोर्ड ने उस पर विचार किया और महीनों के बाद हमारे सामने यह प्रारूप आया है।

इस योजना के बनाने के लिये मूलभूत

( श्री जनार्दनराय नागर )

हमारे सामने समस्याएं थीं। वृहत्तर राजस्थान में निरन्तर हमारा घाटे का बजट रहा। इसी घाटे में हमने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल समाप्त किया। दूसरी योजना का भी दो साल का समय घाटे में गया। हमारे सामने दो समस्याएं थी। एक तो यह कि हमारे विकास के अनुकूल खर्च करने की हमारी शक्ति को विकसित करना और दूसरी हमारी आर्थिक सम्भावनाएं और सम्भूतियों का निरन्तर विकास करना। दूसरी योजना काल में हमने इन समस्याओं को हल करने की दिशा में काफी उल्लेखनीय प्रगति की। हमने इस काल में जनता पर टैक्स भी लगाये।

अब यह कहना कि राजस्थान टैक्स लगाने के मामले में सेचुरेशन पॉइन्ट पर आ गया है, यह उचित नहीं है। यह कहते कि अब अधिक टैक्स लगाना मुमकिन नहीं तो कुछ बात समझ में आती। पर यह कहना कि बिल्कुल टैक्स लगाने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ वोट प्राप्त करने का स्टन्ट मात्र है। टैक्स की बात से वोट मिलने में दिक्कत हो जावेगी। लोग वोट की प्राप्ति की कामना से सही वस्तु से इन्कार करें और इस प्रान्त की प्रगति के लिये इसके भविष्य के लिये अत्यावश्यक प्रगति के सत्य के विकास के लिये अनिवार्य इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करते और स्पष्टता से सदन में बात नहीं करते तो यह राजस्थान की जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और न उसके साथ यह कोई उचित बर्ताव ही है! बेशक; इस प्रान्त के भविष्य के विकास के लिये हम निर्णय करने और अपनी स्पष्ट राय देने जा रहे हैं। इसके लिये हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे। यदि सेचुरेशन पॉइन्ट पर भी आ गये हैं तो भी लगाना पड़ेगा। यह अनिवार्य सत्य है कि ११४ करोड़ की हमारी लगभग की जो प्लान है तो उसके लिये हमें अपने रिसोर्सेज़ भारत सरकार को बताने पड़ेंगे। अगर हम अपना यह कर्त्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो सारा का सारा रुपया भारत सरकार से मिलने वाला नहीं है।

आज मामूली से मामूली योजना के लिये जब हम रुपया जनता से मांगते हैं तो यह बहुत बड़ी योजना है। सारे देश के लिये इसका महत्व है। इसमें हर राज्य को कुछ न कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस योजना के अन्तर्गत ८५ करोड़ के हमें रिसोर्सेज़ कायम करने पड़ेंगे। इसमें बीस करोड़ के टैक्सेशन आने वाले पांच सालों में लगाये जावेंगे। इस साल ग्यारह करोड़ के टैक्स लगाने से हमारी आर्थिक स्थिति में, आर्थिक क्षमता में बल आया है। अब ज्यादा नहीं बढ़ते हैं तो १६–१७ करोड़ तक का तो वातावरण हमने पैदा किया है। जब दूसरी योजना काल में टैक्सेशन की बात आती थी तब भी बराबर विरोध करते थे हमारे कुछ माननीय सदस्य। मैं समझता हूं कि ८१ करोड़ के रिसोर्सेज़ को डेवलप करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जो ले-आउट रखा है उसमें भी थोड़ी सम्भावनाएं हैं कि हम उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके अन्दर रिसोर्सेज़ पहले ६३ करोड़ के बढ़ाने की बात रखी गई थी। यह फाइव इयर प्लान की अवधि में इसलिये बढ़ावेंगे कि प्रान्त को सीलिंग विकास को अधिक से अधिक मिले। आज कई बातों की खामियां महसूस करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कई ऐसी मदें हैं जिनमें हमें काफी रुपया मिलना चाहिये।

# Page No.74



( श्री जनार्दनराय नागर )

फिर यह भी कहते हैं कि प्लान को ३०० करोड़ का बनाना है। इसके लिये २०-२२ करोड़ के टैक्स लगाने चाहिये। इसका साथ देने को वे तैयार हो गये। मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई यह सुन कर कि वे कहने लगे कि हम माननीय मुख्य मन्त्रीजी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं और कन्धे पर उठा कर दिल्ली ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी योजना को ३०० करोड़ की कर दे। यह वे करना चाहते हैं पर इसकी अनिवार्य शर्त जो यह है कि ८१ करोड़ के रिसोर्सेज़ यहां जुटाने होंगे। तो यदि इसके लिये तैयार नहीं हैं और केवल वैसे ही मुख्य मन्त्रीजी को दिल्ली ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ८१ करोड़ भी भारत सरकार दे दें तो यह होने वाला नहीं है। इसकी आड़ में मैं समझता हूँ कि वे ऐसी झूठी सहानुभूति बताना चाहते हैं जिसका मतलब कुछ नहीं। वास्तविक बातें उनको करनी चाहिये।

स्वयं राज्य सरकार ने अपना प्लान फ्रेम भेजा है उसमें ६३ करोड़ के रिसोर्सेज़ की बात कही है। पर इस पर वहां कुछ समस्याएं उलझ गई हैं प्लानिंग कमीशन के सामने जिन्हें काफी परसुएशन से और धीरज से सुलझाने की आवश्यकता होगी। जैसे राजस्थान नहर की बात और अन्य प्रोजेक्शनों की बातें जिनमें पब्लिक सेक्टर में अधिक से अधिक रुपया लगाया जा सके, इसकी आवश्यकता है। अब इसके बारे में क्या करें? माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपना ट्रेन्ड आपके सामने रखा है। तीसरी योजना के बारे में अब न्यूनतम दृष्टि से निश्चित है कि हमारा प्लान २१४ या २२० के आसपास है और इससे कम नहीं होगा, यह इन्डिकेशन मिलता है। पर मैं मानता हूं कि हमें कई दृष्टियों से इसे आगे बढ़ाना होगा।

हमें यह सलाह भारत सरकार को दे देनी चाहिये कि राजस्थान नहर का खर्चा हमारी प्लान से अलग होगा। जैसा माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा इससे लगता है वे समझौता करना चाहते हैं कि मान लीजिये हमारा २१४ करोड़ का प्लान है और ४५ करोड़ राजस्थान कैनाल पर खर्च होने हैं तो हम अपनी प्लान को और आगे नहीं बढ़ावेंगे, आप इस ४५ करोड़ को इस २१४ में मिला दीजिये। यह एडजस्टमेन्ट की दृष्टि से ठीक मालूम होता है। पर मैं मानता हूं कि यह ऐसी नीति का आरम्भ होगा कि जिससे आगे चल कर हमें काफी दिक्कतें आने वाली होंगी। राजस्थान कैनाल को सेन्ट्रल सेक्टर में ही, इसलिये बनाना चाहिये और इसी पर हमें जोर देना चाहिये। इसका खर्चा सेन्टर से अलग लेना चाहिये जैसा औरों के लिये मिला व मिलता रहा है पहली और दूसरी योजनाओं में। ४४ करोड़ हमें चम्बल-भाखरा का मिला। वह हमारी प्लान में नहीं था। इसी तरह दूसरी में भी सेन्ट्रल सेक्टर से हमें मिला। इसलिये कोई कारण नहीं रहता कि आज इस प्लान में भी हमें राजस्थान कैनाल का खर्चा सेन्ट्रल सेक्टर से नहीं मिले। इसलिये मेरी माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह प्रार्थना है कि इस बात को वे भारत सरकार के सामने रखें।

यदि वे ऐसा करेंगे और प्लान के सीलिंग में इसे भी इन्क्लूड करने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अन्ततोगत्वा हमें इसमें लेना

( श्री जनार्दनराय नागर )

पड़ेगा। मेरी आशंका है कि इससे अपने प्लान अनिर्णीत स्थिति में पहुँच जावेगा। राजस्थान के प्लान का, सामाजिक सेवाओं का जो लक्ष्य है. औद्योगिक विकास का लक्ष्य है उन पर धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता जावेगा, क्योंकि आज मनोविज्ञान बनता चला जाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मन के विकास की दृष्टि से और खर्चे की दृष्टि से आ जाते हैं तो छोटे, लघु श्रेणी के विकास के कामों पर इसका असर पड़ेगा। उनका आज जो महत्व नजर आता है वह तब नहीं आवेगा। इसलिये यह मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि राजस्थान नहर के सवाल पर हमारी सरकार अड़ी रहे और बराबर इस मांग पर अटल रहे कि इसका सारा खर्चा राजस्थान पर नहीं रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो टैक्सेशन की बात यहां पर आई है ८१ करोड़ की, मैं मानता हूं कि हमारे रिसोर्सेज़ के ऊपर हमें यदि २१४ करोड़ मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे रिसोर्सेज़ को और अधिक डेवलप करना चाहिए। अभी आज क्या परिस्थिति है, मैं नहीं कह सकता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निवेदन से मैं यह समझूं कि इस मामले में रिसोर्सेज़ की दृष्टि से अभी हमारी कोई निर्णायक स्थिति नहीं है। कुछ इन्डीकेशन हमारी सरकार को मिला है वह हमारे सामने सरकार ने रखा है। कुछ ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे रिसोर्सेज़ के अन्दर भी कुछ कमियां हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी जो देने की साइड है, हमारा जो कमिटेड एक्सपेन्डीचर है उसका वजन हमें कुछ बढ़ता हुआ नज़र आता है। यदि यह बात है तो आज हम तृतीय योजना काल को ११ या ११॥ करोड़ के सरप्लस से शुरू कर रहे हैं। यदि ऐसी हालत नहीं होती है और डेबिट साइड की तरफ हमारा वजन बढ़ता है तो हम तृतीय योजना काल के पहले दो वर्षों में माइनस में जायेंगे और हम इस माइनस की स्थिति में रहते हैं लेकिन जहां एक ओर हम अपने तृतीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में माइनस में जायेंगे वहां आगे के तीन वर्षों में हमारी स्थिति प्लस की होती जा रही है। यदि, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी डेबिट साइड का वजन बढ़ गया और सारा का सारा रेवेन्यू में ही खर्च करना पड़ा तो तृतीय योजना काल में जो आर्थिक सम्भावनाओं को अधिक दृढ़ कर सकते थे उसके ऊपर असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि १२–१४ करोड़ के करीब पैसा पब्लिक लोन से लिया गया। आज भी ५ करोड़ का लोन गवर्नमेन्ट ने एप्रूव कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी सम्भावना है कि लोन की दृष्टि से तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें मुश्किल होने वाली है। जहां तक मैं इसका अध्ययन कर पाया हूं वह यह है कि अखिल भारतीय परिस्थिति से यह दिक्कत पैदा हुई है। इसमें राजस्थान के ऋण लेने की स्थिति में विश्वास और अविश्वास का प्रश्न तो नहीं है दृष्टि, पंचवर्षीय योजना में राजकीय दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका असर हमारे रिसोर्सेज़ के ऊपर और खास तौर से उसके डेवलपमेंट के ऊपर, स्मॉल सेविंग्स के ऊपर और दूसरी योजनाओं के ऊपर अधिक से अधिक पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना पड़ेगा कि हम टैक्सों की मिकदार को थोड़ा बढ़ा दें

( श्री जनार्दनराय नागर )

और सेविंग को कुछ कम रखें । तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हम करेंगे तो एक तालमेल रख सकेंगे । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर रिसोर्सेज़ की दृष्टि से लगान में वृद्धि करनी चाहिए । इसी प्रकार बैटरमेन्ट लेवी के बारे में मैं समझता हूं कि दृढ़ता के साथ सारे राजस्थान में वृद्धि करनी पड़ेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इर्रिगेशन के लक्ष्यों को तो हमने पूरा कर लिया लेकिन जितने रिटर्न थे और जो उनसे आय होने को थी उसकी ओर से हम निराश ही हुए हैं, उसमें हमें प्राप्ति नहीं हुई है । इसका मूल कारण यह है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे सिंचाई नहीं हुई हो, ऐसी बात तो नहीं है । वह तो होती चली जा रही है लेकिन यह निश्चित राय है कि हमारी आय बढ़ी नहीं है । मैं समझता हूं कि बैटरमेन्ट लेवी की दृष्टि से और कुल जमीन की सुविधा की दृष्टि से जो कि किसान को मिल रही हैं जो लगान के चार्जेज़ हैं उनके अन्दर परिवर्तन होना चाहिए और आज की रेवेन्यू साइड को इस दृष्टि से काफी बढ़ाना चाहिए ।

तीसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि स्मॉल सेविंग के बारे में तीसरी आयोजना में राज्य सरकार को धन अधिक से अधिक देना पड़ेगा । यह किस प्रकार से होगा? इस प्रकार कि जनता द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों में जितना जनता देती है उतना ही राज्य सरकार की ओर से लगेगा । जनता में विश्वास पैदा होता है । ऋण वही आदमी उस आदमी को देता है जिन पर इस प्रकार का विश्वास हो कि जिनको ऋण देते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं । जितना भी ऋण हम जनता से प्राप्त कर सकें वह प्लान के बारे में जनता की ओर से विश्वास प्रकट करना होगा और यह इस बात का परिचायक भी है ।

मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान इस बात के लिए खींचना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में राजस्थान में काफी इन्डस्ट्रीज़ होनी चाहिए और काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकें इस बात की कोशिश तृतीय पंचवर्षीय योजना में की जानी चाहिए । मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी राज्य सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न हो रहा है । अभी कहा गया कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय जहां जाते हैं वहां तीन-चार बातें करते हैं । तांबे की बात करते हैं और कहीं कुछ ऐसी ही बातें करते हैं । मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भ्रांति हुई कि शायद ऐसा कहा गया कि वह अखबार वालों को खुश करने के लिए ऐसी बात कहते हैं । लेकिन वास्तव में ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है । उन्होंने हमारे सामने जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से कहा । बहुत सी बातें उन्होंने फर्टीलाइज़र फैक्टरी के बारे में बताई कि उसके लिए निश्चित स्थिति है । कॉपर स्मैल्टर के बारे में बताया कि १० हजार टन के स्मैल्टर की बात चल रही है और उसकी सम्भावना बहुत है ।

मैं मानता हूं कि जितनी सम्भावना है उसके विकास की दृष्टि से तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक पब्लिक सेक्टर की इन्डस्ट्री मांगनी चाहिए । मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि यहां कहीं पर वैगन बनाने की इन्डस्ट्री बनने वाली है, गैस के लिए कुछ

# Page No.77



( श्री जनार्दनराय नागर )

आने वाला है । मैं समझता हूं कि ये ऐसी बातें चल रही हैं कि इसका मुझे मालूम नहीं कि किस स्थिति में ये बातें हैं । मैं समझता हूँ कि इस मामले में सदन को जानकारी दी जानी चाहिए क्योंकि हम यह मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जैसा राज्य सरकार ने बताया कि काफी रुपया पब्लिक सेक्टर का राजस्थान में लगना चाहिए और ५०४ करोड़ की जो पूंजी लगनी है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वह इसलिए कि पर-कैपिटा इनकम बढ़े, दूसरे राज्यों के मुकाबले में वह आये और तृतीय पंचवर्षीय योजना तक उसका गैप कम से कम रहे; ७ पर्सेन्ट रह जाये या ८ पर्सेन्ट रह जाये । इसलिए जो ५०४ करोड़ की लगाने की बात कही है मैं समझता हूं कि पब्लिक सेक्टर में काफी प्रगति होनी चाहिए ।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मजेदार कही गई कि कुछ हैवी इन्डस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर में लगाना चाहिए, बाकी सारे राजस्थान का औद्योगिक ढांचा प्राइवेट पूंजी से होना चाहिए, ऐसी बात कही गई । हमें मालूम है कि आज हिन्दुस्तान के स्तर के ऊपर दो विचारधाराओं के चक्कर हैं । एक विचार धारा तो उनकी है जो यह मानते हैं कि उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी लगनी चाहिए । उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ थे और अब वह हमारी तरफ से निकल कर उस तरफ चले गये । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जब आज हम तृतीय आयोजन का प्रारम्भ करने जा रहे हैं हिन्दुस्तान में विचारधारा की दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है । हम मानते हैं और समझते हैं कि हिन्दुस्तान में सामाजिक दौर में एक स्थिति आयेगी जब कि हिन्दुस्तान का एक तबका कहेगा कि को-ऑपरेटिवज़ का विकास होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का विस्तार होना चाहिए । तब एक आवाज आयेगी जो कहेगी कि एक घर से लेकर, खेत से लेकर, चौराहे से लेकर हर पूंजी व्यक्तिगत होनी चाहिए । एक हलके, फुलके अनायास ही समाज और व्यक्ति का संघर्ष हर जगह शुरू हो गया है और आर्थिक क्षेत्र में यह संघर्ष हमारी राजनीतिक समस्या का एक प्रकार का वैंगार्ड है और उसका जवाब मैं समझता हूं दूसरी तरफ से मिलना चाहिए ।

हमारे जो सार्वजनिक हित के काम हैं उनकी संख्या के विस्तार का इसमें प्रावधान है । लेकिन कुल मिला कर इसका जो असर होता है हम अगर पब्लिक सेक्टर को राजस्थान में स्थापित कर दें लेकिन हमें नीति की दृष्टि से यह ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हम ऐसी आयोजना न करें कि पब्लिक सेक्टर में और प्राईवेट सेक्टर में कौन कौन से उद्योग होने चाहिए; लेकिन प्लान की दृष्टि से यह ठीक नहीं है । हमारे जो प्लान का मूल आधार है वह यह भी है कि पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे दृढ़ होगा । जितना पब्लिक सेक्टर दृढ़ होगा उतना ही मैं मानता हूं कि हमारे सामाजिक स्तर की स्थिति की सम्भावना आगे होगी । आज राजस्थान की ऐसी परिस्थिति है कि वहां व्यक्तिगत पूंजी लगाने के लिए बहुत से लोगों को लाना है । इसके लिए निश्चित किया है तो मैं कहूंगा कि उनको और अधिक कन्सेशन्स दीजिए और रियायतें दीजिए । लेकिन दो बातों की दृष्टि से मैं समझता हूं कि

( श्री जनार्दनराय नागर )

इसका ख्याल रख कर चल पायेंगे कि कुछ ऐसे उद्योग हैं कि जो राजस्थान की सामग्री से उत्पन्न किये जा सकते हैं और लगाये जा सकते हैं। उनको क्या हम व्यक्तिगत पूंजी के हाथों में जाने देंगे, जिसका उदाहरण आज हम देना नहीं चाहते ? कुछ उद्योग ऐसे होंगे जिनको हमें पब्लिक सेक्टर में रखना होगा और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको हमें प्राइवेट सेक्टर में रखना होगा ! अभी कहा गया, ट्रांसपोर्ट के नेशनेलाइजेशन की बात कही गई कि इसको प्राइवेट उद्योग मान लेना चाहिए । एक समय था जब इसको प्राइवेट उद्योग मान कर चले । आज इसके साथ रेल्वे की बात जोड़ी गई और उसे प्राइवेट सिद्ध करने की कोशिश की गई। कहा गया कि आज इसको प्राइवेट सेक्टर के आधार पर, एक स्टेट के आधार पर चलाया जाता है । मैं समझ नहीं पाया कि रेलवे स्टेट ओनर का प्रोजेक्ट है, रेलवे शताब्दी से चलती आ रही है। यह जो मोटर रोड्स हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके नेशनलाइजेशन की बात रखी गई थीं; उसका क्या आधार हो सकता है ? मैं मानता हूं कि कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको निश्चित रूप से व्यक्तिगत पूंजी में, व्यक्तिगत मिल्कियत के रूप में मानना पड़ेगा और हम मानते हैं। जब रेलवे सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो कोई वजह नहीं हो सकती कि यह रोड ट्रांसपोर्ट जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा क्यों नहीं चले ? मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेन्ट देरी कर रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइजेशन की बात थी, लेकिन नेशनलाइजेशन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कानूनी अड़चनें हों तो उनको भी दूर करना चाहिए। आखिर यह एक बड़ी विकसित इण्डस्ट्री है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बस ट्रांसपोर्ट जो है वह विकासोन्मुख उद्योग है । यह ठीक है कि आज हमारी उसमें काफी पूंजी, करोड़ रुपये से भी ज्यादा की पूंजी लगी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि कोई करोड़ रुपये सवा करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है लेकिन नीति की दृष्टि से भी यह जरूरी हो जाता है कि हमको रोड ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन करना चाहिए। मेरी सूचना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे राजस्थान के तमाम रूट्स का नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं। यह सही है कि कानूनी उलझनें हैं लेकिन उनको भी दूर करना चाहिए । यह हमारी अहम नीति का प्रश्न है।

मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की दृष्टि से भी हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। हम लाइट हार्ट से विचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सारे भारत का, सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का, हमारी आर्थिक नीति का आधार है उसका यह एक अहम प्रश्न है जिसके ऊपर हमारे सिद्धान्तों को देखते हुए इसके अन्दर हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि आगे जाकर हमें पछताना पड़े। राजस्थान के अन्दर एक ओर कैपिटलिस्ट स्टेंड हैं और एक ओर सोशियलिस्ट स्टेंड है। ऐसा न हो कि कैपिटेलिस्ट स्टेंड का विकास हो जाय और सोशियलिस्ट स्टेंड का विकास न होने पावे और इसके लिए फिर

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमें पछताना पड़े। दूसरे पक्षवालों के लिए अपने आदर्श हो सकते हैं, उनकी अपनी आर्थिक नीति हो सकती है, जो भी वे कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन हम तो यह मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में ज्यादा विस्तार होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में पब्लिक सेक्टर का निरंतर विस्तार होता चला जायेगा, लेकिन कुछ उद्योग निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनको हम प्राइवेट सेक्टर में मानें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का भी एक सवाल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायेगी, इसका प्रावधान किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मैं समझता हूँ कि ६३ हजार किलोवाट के करीब बिजली पैदा करने का प्रावधान जो है वह पूरा हो जायेगा। लेकिन सारी समस्या यह है कि हमको यह पॉवर मिलनी चालू हो जायगी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम तीन लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न कर लें और हमने इसको प्राप्त भी कर लिया तो भी मेरी ऐसी मान्यता है कि बिजली की हमारी कमी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जैसा कि अभी हमें बतलाया गया कि बहुत सारे उद्योगों का हमारे राजस्थान में विकास होगा और जिसकी बहुत बड़ी सम्भावनाएं दिखाई देती हैं। हमारे कृषि के विकास की स्टेज भी आ गई है कि एक न्यूनतम यंत्रीकरण राजस्थान के खेतों में होता चला जायेगा। इसके अलावा भी हमारे जितने सिविल वर्क्स के काम हैं उनके लिए भी बिजली की आवश्यकता होगी। केवल उद्योगों के विकास के लिए हम बिजली की आवश्यकता की बात करते हैं लेकिन सिविल पर्पजेज़ के लिए भी बिजली की निरन्तर आवश्यकता है। इसलिए इस दृष्टि से भी इसमें प्रावधान होना चाहिए और इस दृष्टि से यह प्रावधान तीन लाख किलोवाट का बहुत कम मालूम होता है। लेकिन इसके साथ में यह भी मानता हूँ कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिजली का सबसे ज्यादा प्रावधान है और दूसरे नम्बर का प्रावधान शिक्षा का है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हमारे दो, तीन जो स्थानीय महत्व के विकास के कार्य हैं मैं कहना चाहता हूं कि हमें उन पर विचार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनके बारे में मैं यह आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि पहले संस्कृत की शिक्षा के विकास की एक नीति बनाई और एक बोर्ड भी कायम कर दिया है। आज से तीन वर्ष पहले सरकारी नीति भी घोषित कर दी गई। जो संस्कृत के आचार्य हैं उनको तनख्वाह देने की बात भी घोषित करदी गई, यह भी बतला दिया गया कि संस्कृत के जो आचार्य हैं उनको अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूल्स हैं उनके मुकाबले में लाया जायेगा। इस प्रकार नीति घोषित कर दी गई लेकिन जो प्रावधान तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है वह ऐसा है जिससे मुझे कतई विश्वास नहीं होता कि संस्कृत के प्रसार की जो राज्य सरकार की मनोकामना है, संस्कृत के विकास के लिए, इसके प्रसार के लिए राज्य सरकार की जो मनोकामना है, शिक्षा की जो समायोजना है, उसके अनुसार संस्कृत के विकास के लिए एक रेस्पैक्टेबल प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। आज संस्कृत पाठशाला के लिए

( श्री जनार्दनराय नागर )

मकानात नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है लाइब्रेरी नहीं है। आपने सम्भवत: आठ लाख रुपये रखे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में; लेकिन आप उनको डिवाइड किस प्रकार से करेंगे? करीब पौने दो लाख रुपये मकानात, फर्नीचर आदि में लगायेंगे। संस्कृत एडवाइज़री बोर्ड ने भी यह सिफारिश की है कि संस्कृत का एक उपयुक्त प्रतिष्ठान हो।

दूसरे, अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले जो प्रतिष्ठान हैं उनके बराबर संस्कृत के प्रतिष्ठान को लाया जाय। संस्कृत के मिडिल स्कूल्स होंगे, हायर सेकिन्डरी स्कूल्स होंगे। जब संस्कृत एडवाइज़री बोर्ड ने राज्य सरकार को यह सलाह दी तब तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो आठ लाख रुपये का या दस लाख रुपये का प्रावधान किया है, उससे आप क्या करेंगे? आठ लाख या दस लाख रुपये में आप संस्कृत पाठशाला के मकानात पूरे नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि कोई पचास लाख या एक करोड़ का प्रावधान इसके लिए कीजिए; लेकिन मेरा कहना यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप इतना प्रावधान तो कीजिए कि एक हाई स्कूल बिल्डिंग संस्कृत के लिए हो, उनको फर्नीचर तो ठीक दे सकें, लाइब्रेरी का विकास कर सकें, इस मामले में एक उत्साहजनक वातावरण विद्यार्थियों को दे सकें। इसके लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान होना चाहिए था। संस्कृत के प्रसार की मान्यता होते हुए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषित नीति होते हुए और हिन्दुस्तान के सामने यह बात होते हुए कि संस्कृत के लिए राजस्थान कुछ करने जा रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान रखा गया है वह बहुत कम है, निराशाजनक है।

इसी प्रकार मैं आयुर्वेद के बारे में भी कहना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पचास लाख रुपया आयुर्वेद के विकास के लिए रखा गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उससे अधिक प्रावधान है और वह अस्सी लाख का प्रावधान है। आयुर्वेद एडवाइज़री बोर्ड ने लिखा है कि हमारी मिकदार कम से कम दो करोड़ की होनी चाहिए। हमें मालूम है कि दो करोड़ रुपये तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी नहीं होंगे। लेकिन जो अस्सी लाख का प्रावधान किया गया है जिसका मतलब है कि कुल तीस लाख रुपया आपने बढ़ाया है; जहां पहले दस लाख था वहां अब पन्द्रह लाख कर दिया है। आपको मालूम है और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि राजस्थान में डॉक्टरों की कमी है और इसके लिए दो मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से अधिक प्रावधान रखा गया है डॉक्टरों के लिए। लेकिन आज जैसे आपके डॉक्टर हैं अप्टूडेट, छैल छबीले, अब वे गावों में जाते हैं तो उनके लिए पक्का मकान चाहिए, फ्लश चाहिए और क्या क्या चाहिए। जब इधर तो डिफिकल्टी है कि डॉक्टर मिलते नहीं हैं और उधर आप एलोपेथी के लिए प्रावधान रख रहे हैं बहुत बड़ा। ठीक है, आप सर्जरी की दृष्टि से बड़े प्रतिष्ठान कायम कीजिए, लेकिन आपके सामने एक प्रश्न जन-स्वास्थ्य की चिकित्सा का और, जिसके लिए आप बराबर रुपया बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि हर छः हजार की जन संख्या वाले गांव में चिकित्सा की सुविधा मिल जाय। इधर आप आयुर्वेद के लिए रुपया पूरा नहीं रख रहे हैं, उधर आपके

( श्री जनार्दनराय नागर )

पास डॉक्टर नहीं हैं तो यह एक प्रकार का कन्फ्यूज़न है, जो स्पष्ट होना चाहिए। चिकित्सा के सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीय स्तर की नीति होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद गलत प्रणाली नहीं है। राजस्थान के गांवों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा पहुँचाना चाहते हैं तो केवल आयुर्वेद ही हमारे सामने रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप दो कॉलेज खोल रहे हैं, ३ कॉलेज और आप खोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आप एलोपेथिक को राजस्थान के जन पदों तक, राजस्थान के उन खपरेलों तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एलोपेथिक की सारी प्रणालियां मंहगी और खर्चीली हैं। उसकी सर्जरी का मैं कायल हूं। तहसीलवाइज़ २-३ सर्जरी के केन्द्र होने चाहिए। लेकिन ३००–४०० अपूमन रोग जनता में हुआ करते हैं। ३००–४०० रोगों का, मैं मानता हूं कि आयुर्वेद के द्वारा मूलाधार स्थापित करना पड़ेगा। जिसमें इन रोगों की परिभाषा, लक्षण और औषधियां हमारे सामने होतीं तो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में यह शक्ति है, यह विश्वास है; जहां तक रोगों के निवारण करने का सवाल है आयुर्वेद एलोपेथी से कम नहीं है। अब तक जो कुछ हुआ वह हम भी भूल जाते हैं, "बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेहु।" हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के औषधालयों की तहसीलों के अन्दर अधिक संख्या हो। एक तहसील के अन्दर ६–७ औषधालय हों और २–३ ऐसे एलोपेथिक के सर्जीकल सेन्टर्स हों कि जहां मीडियम साइज़ के ऑपरेशन हो सकें। इसलिए इस नीति पर चलेंगे तो आयुर्वेद के लिए स्वभाविक रूप से प्रावधान अधिक करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की कितनी सहानुभूति है और मुझे मालूम है कि हमारी केबिनेट भी उसके साथ कितनी सहानुभूति रखती है, लेकिन रुपया चाहिये आयुर्वेद के विकास के लिए और एक नीति चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि इसमें मेटीरियल टार्गेट्स....

**श्री उपाध्यक्ष** : I hope you will now have consideration of time.

**श्री जनार्दनराय नागर** : मैं तो अभी मूल पर ही आ रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : I think you have now concluded.

**श्री जनार्दनराय नागर** : जो ट्रेन्ड है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मैं समझता हूं काफी प्रावधान है। पहले पंचवर्षीय आयोजन और दूसरे पंचवर्षीय आयोजन के बाद तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में इस बात के निश्चित रूप से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है इसके अन्दर काफी प्रावधान तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखे गये हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और एक बात, मैं समझता हूं सारी बातें रखी गई हैं।

हाउसिंग; मैं समझता हूं ग्राम्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में मकानात के लिए जो आयोजन

( श्री जनार्दनराय नागर )

रखा है, मैं समझता हूं यह नई ट्रेन्ड है गांवों के विकास की दृष्टि से। अब तक दूसरी पंचवर्षीय योजना से घर बनाने के लिए, हाउसिंग के लिए हमारी लेबर एमिनिटीज़ की ओर दृष्टि रही। जहां तक लेबर वैलफेयर का प्रश्न था वहां हाउसिंग के बारे में सोचा। हमने सिटीज़ में हाउसेज़ बनाने के लिए कुछ आयोजन सिटीज़ में विवृत किये। उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के कई शहरों का विकास हो गया है। लेकिन गांवों और कस्बों की स्थिति के लिए और गांवों में, मैं समझता हूं हाउसिंग स्कीम को लागू करने की बहुत जरूरत थी ! आज शहरों में हाउसिंग के लिए लोन मिलता है। जिस प्रकार मकानात की स्थिति बढ़ती हुई देखते हैं तो गांवों के अन्दर इस प्रकार का आयोजन लागू हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इस मामले की ओर ध्यान दिया गया है और १७ करोड़ की रकम पांच वर्षों के लिए रखी। १७ करोड़ नहीं तो १० करोड़ से कम नहीं होगी।

मेरा यह कहना था कि पंचायतों के लिए केवल ३ करोड़ रखा है। मैं समझता हूं कि पंचायतों के लिए इसके अन्दर ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। आज हमने कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काफी रकम रखी है। लेकिन मैं समझता हूं कि पंचायत की दृष्टि से इतने में काम नहीं चलेगा जितना कि तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में रुपया रखा जा रहा है। मेरी सारी दलील यह है कि अब तक राजस्थान में पंचायत बनाने का जो परिमाण था उसकी नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अब २,००० तक की बस्ती पर पंचायत रखी गई है। इसलिए पंचायत समिति के बाहर भी मैं समझता हूँ कोई न कोई किसी तरह मार्ग दर्शन की आवश्यकता होगी और राजस्थान में पंचायतों की संख्या आज से तिगुनी हो जायेगी। राजस्थान के अन्दर ऐसी दृष्टि से यह प्रावधान किया मालूम होता है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं यह कहना चाहता था कि जहां तक कुल मिला कर शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग, पंचायत और अर्बन डेवलपमेंट के लिए १ करोड़ रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक नया ट्रेन्ड है। हमारे प्लानिंग में पंचायत समितियों द्वारा ग्राम्य क्षेत्रों का विकास होगा। उसका खाका खींच दिया, लेकिन शहरों का भी मैं समझता हूँ कि कॉम्युनिटी डेवलपमेंट के आधार पर विकास होना जरूरी है। मुझे खुशी है कि इसमें उसके लिए एक करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन प्लानिंग के अन्दर कॉम्युनिटी डेवलपमेंट पर एक थीसिस लिखा हुआ है, एक प्रवचन लिखा हुआ है कि यह प्लानिंग का मूल आधार है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां कॉम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक चल रहे हैं।

तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में मैं समझता हूं कि हमारी जो सोशियल सर्विसेज़ हैं, जिनको हम ब्रिडल कहते हैं, जिनके अन्दर बहुत कम डेवलपमेंट किया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। उनके बारे में एक प्रावधान किया गया है। हमारी शिक्षा, सिंचाई आदि में तमाम में विकास हो। इसमें जो फाइनेन्शियल प्रावधान किया है उसके अलावा मैं कहता हूं कि

# Page No.83



( श्री जनार्दनराय नागर )

इसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जिसमें विकास खण्ड नहीं खुला हो। इस दृष्टि से इसके अन्दर काफी प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रावधान है: ये संतुलित प्रावधान हैं, भविष्य को इंगित करने वाला प्रावधान है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए और प्रतिभावालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है इसके अन्दर। यह कहा गया कि मुतफरिक में इसका प्रावधान हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष, इस मुतफरीक से मुझे नफरत है। मुतफरीक के अन्दर कोई प्रावधान होगा। मैं यह मानता हूं कि मिस्लेनियस के अन्दर इस बारे में प्रावधान करेंगे। वह मुझे डिग्नीफ़ाइड नहीं मालूम होता है। मेरा यह सेन्टीमेंट हो सकता है, लेकिन कलाकारों, साहित्यकारों के लिए, प्रतिभा वालों के लिए, उनका खर्चा मुत्तफरीक में पुराने जमाने के राज्यों के अन्दर जिस प्रकार..

**श्री उपाध्यक्ष** : उसका ही तो रीफॉर्म्ड हुआ होगा।

**श्री जनार्दनराय नागर** : ऐकेडेमीज़ की स्थापना की गई है। राजस्थान के कलाकारों का, साहित्यकारों का, राजस्थान के प्रतिभावालों का समाज के अन्दर महत्व माना है। उतना ही महत्व माना है जितना कि एक श्रमिक का महत्व मानते हैं, जितना कि एक पूंजीपति का महत्व है, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का महत्व है। कोई कारण नहीं दिखता कि राजस्थान के कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए और प्रतिभावालों के लिए एक निश्चित रूप से प्रावधान क्यों नहीं करें। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने एकेडेमीज़ के विषय में तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस दृष्टि से सोचा है। लेकिन जो सोचा है वह ऐसा ही सोचा है कि काम हो तो ठीक ढंग से हो, तबियत से हो। कितने बे मन से ३ ऐकेडेमीज़ को निबटाया है? २४–२५ लाख में निबटाया है तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में। लेकिन यह जो हमारी एकेडेमीज़ हैं, जिनको राज्य सरकार ने बड़ी तबियत से कायम किया है और जिनके विकास का कुछ जिम्मा हम लोगों को दे रखा है; उनको आखिरकार रुपया देना चाहिए। तीनों एकेडेमीज़ को ८–८ लाख रुपया दिया गया है। वह बहुत कम है, शायद दो-एक लाख और बढ़ जाये, लेकिन तीसरे पंचवर्षीय आयोजन काल में दूसरे विकास का वातावरण फैलेगा, इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि तीनों एकेडेमियों ने दूसरे पंचवर्षीय आयोजन काल में जो कुछ भी काम किया है उस दृष्टि से राजस्थान के साहित्यकारों, कलाकारों और प्रतिभावालों के लिए एकेडेमियों का अधिक से अधिक विकास करना पड़ेगा। मेरी नम्रतापूर्वक और साग्रह प्रार्थना है कि तीनों एकेडेमियों को कम से कम १२–१३ लाख और रुपया दिया जाय। उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन काल में तीनों एकेडेमियों ने जो खाका खींचा है उससे उन्हें कुछ नई दिशाएं प्राप्त हुई, कुछ परम्पराएं विकसित की हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि तीसरे पंचवर्षीय आयोजन काल के अन्दर एकेडेमीज़

श्री जनार्दनराय नागर )

के कामकाज को, उनके प्रोग्राम को आगे विकसित करना है। इस दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का और हमारी सरकार का ध्यान खींचूंगा कि ८-१० लाख से काम चलने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने स्पोर्ट्स कौन्सिल को २८ लाख रुपया दिया है। मैं समझता हूं कि २५-२५ लाख नहीं तो कम से कम १५-१५ लाख रुपया देना चाहिए। आप इनको रुपया देते हैं तो क्या करते हैं कि तमाम राजस्थान के अन्दर सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से, सांस्कृतिक कार्यक्रम की दृष्टि से, एक अच्छे वातावरण की दृष्टि से, विकास की जो संभावनाएं हैं उस दृष्टि से, मैं समझता हूं ये एकेडेमीज़ बड़ा काम कर रही हैं। मैं सहर्ष गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से एकेडेमीज़ का निर्माण किया है, जिस तरह से उनकी स्थापना की है, मैं समझता हूँ, वे भारत के अन्य राज्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा वजनी हैं। उस वजन को कायम रखना चाहिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : I would like from you now to wind up the debate.

**श्री जनार्दनराय नागर** : Yes, Sir, I am doing it now.

**श्री उपाध्यक्ष** : You have exceeded more than one hour and I have to...

**श्री जनार्दनराय नागर** : I supposed there was presumably no time limit.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have my discretion to do that.

**श्री जनार्दनराय नागर** : अंत में, मैं यह कहना चाहता था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी राज्य सरकार के सामने तीसरे पंचवर्षीय आयोजन के विकास की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ही नहीं; कुछ उलझनें भी हैं।

सारे भारतवर्ष के चित्र में तृतीय पंचवर्षीय आयोजन का सारा प्रकाश प्रक्रिया है। मुख्य मंत्रीजी ने ठीक कहा कि हम लोग आयोजन के साथ कई प्रक्रियाएं शुरू कर रहे हैं, प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं, विशेष ऐसी स्थिति आये जैसा कि उन्होंने कहा, हमें सारे राजस्थान में प्रयोग करना पड़ेगा। उसके साथ एक संकल्प करना पड़ेगा जिसके द्वारा आयोजन को सफल कर पायेंगे; जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना ही जनतांत्रिक समाजवादी समाज की ओर बढ़ेंगे।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू)** : उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को संपूर्ण करके हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके ऊपर काफी कहा भी गया है और कहा भी जायेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा जो दृष्टिकोण है यह वह है कि जहां तक इस बारे में, ऐसे मामले में कहा जाय कि जिसके ऊपर आलोचना, आलोचना के लिये न होकर वह कार्य सुचारू रूप से चलने के वास्ते हो; यह हमारा सिद्धान्त हम लोगों को इजाजत देता है और वह प्रश्न जो इस समय आ रहा है गवर्नमेंट के सामने: जैसे बांधों का, जैसे जल योजनाएं हैं और दूसरी चीजों का मामला सामने आया है, यह जरूरी बात है कि इसमें धन और हर प्रकार की चीजों की

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

सुविधा और सामान मुहैया करने की जरूरत रहेगी। लेकिन यदि देखा जाय तो राजस्थान में इस समय और सब चीजों को छोड़ कर मैं 'बैक बोन' समझता हूं कृषि की उन्नति को। इसके ऊपर कम से कम राजस्थान में, गौण रूप में भारतवर्ष और वैसे विश्व में सब की केन्द्रीभूत एक ही चीज हम लोगों के सामने आती है, राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ मुल्क रहा है। बांध और तालाब कि जहां जहां भी आवश्यकता होती है मेवाड़ में, कोटा, बूंदी; करोली, अलवर और जयपुर में जहां जब भी जरूरत हुई इन चीजों के वास्ते आज से ही नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले से उदाहरण उपस्थित कर दिया था। खेती और पीने के पानी के लिये व्यवस्था की गई। इस चीज़ को मद्दे नज़र रखकर ही गवर्नमेंट ने चंबल प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके अतिरिक्त जो पंजाब की पेरेनियल नदियां हैं उनसे पानी लेना शुरू किया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जवाई वगैरह चल रहे थे उनके लिए भी काफी प्रयास और प्रयत्न किया है। मैं यह समझता हूं कि दुनिया के अन्दर यह इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। क्योंकि इससे होने वाला गेन अनकेल्कुलेबल है, जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती, जिसको हम सोच नहीं सकते कि इसे क्या २ गेन हो सकता है। पहले इसमें खेती की ही व्यवस्था मुख्य थी लेकिन अब बिजली व्यवस्था और दूसरी इससे ताल्लुक रखने वाली व्यवस्थाएं उपस्थित रहती हैं और यह अत्यन्त आवश्यक है।

राजस्थान में खेती को आगे बढ़ाने के लिये और उसके अन्तर्गत दूसरे जितने आयोजन हैं तरक्की करने के वास्ते, अगर जरूरत है तो जैसे दूसरी चीजों के लिए साथ साथ जरूरत होती है उसी तरह कृषि के वास्ते भी कृषि के साथ साथ आवश्यकता होती है। हमारे यहां एक समय ऐसा उपस्थित था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मेरा ही या मेरे सर्कल का सवाल उपस्थित करूं जिसके लिए आज वक्त लोगों का ख्याल हो जाता है कि यह अपने दायरे तक ही महदूद रहता है, लेकिन यह बात नहीं है, सभी ऊंचे विद्वान् आज के जमाने में मानते हैं कि कृषि शास्त्र को सब चीजों से ज्यादा ऊंचा दर्जा देना चाहिये। जिस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से बीकानेर में आज से १२ वर्ष पहले कृषि का कॉलेज स्थापित किया था उस समय दूसरा सवाल भी आया था कि उदयपुर में भी एग्रीकल्चर का कॉलेज खोल दिया जाय। समय यह आया कि दूसरे कॉलेज की चाहे आवश्यकता हो या नहीं हो, एक ही उस समय बहुत था। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को महसूस किया है कि दो के बजाय कतिपय और भी कॉलेज वर्तमान हों तो भी आगे की समस्या को देखते हुए भी बी. डी. ओ. वगैरह कृषि से सम्बन्धित ऑफिस का नम्बर बढ़ते हुए और भी कॉलेजेज़ की जरूरत हो सकती है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा कि तीसरा कॉलेज अजमेर में और चौथा एग्रीकल्चर कॉलेज सांगरिया में खोलने की व्यवस्था की है।

मैं यह कहूंगा कि यहां स्थिति और आवश्यकता को देखा जाय तो शायद कृषि के चार कॉलेज भी कम होंगे। यह सवाल शुरू में आता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज एक होना चाहिये या अनेक हों। मैंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अ, आ, इ, ई का

# Page No.86



( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

अनुभव किया है। उसके जरिये कह सकता हूं कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि दूसरे प्रान्तों में चाहे एक गवर्नमेंट कॉलेज पर राजस्थान की परिस्थिति इसके थोड़ी विपरीत है। यदि हम सिन्ध से लेकर पंजाब तक, इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब से यू. पी. तक और यू. पी. से लेकर बिहार, बंगाल और आसाम तक जाते हैं तो पेशावर से लेकर शिलोंग तक का प्रान्त है यह सब का सब एलयूवियल एकसा रहा है। यहां मोनोटोनी एक ही तरह की प्रचलित है, वहां एक ही इन्टेन्शन है, हर जगह जुड़ा हुआ होना चाहिये। लेकिन राजस्थान में मोनोटोनी मिल सकती है। अच्छी तरह से देखा जाय तो यहां २ माइल में बदलने का सवाल है, ऐसी परिस्थिति में एक विशेषता हो सकती है। इस वास्ते उस वक्त की जो चीज़ थी वह पुरानी हो चुकी उसको दोहराने की विशेष आवश्यकता इसलिये नहीं है कि एक दिन मेरे से टिनेन्ट्स कुछ और तकाजा करते थे लेकिन आज से ७ वर्ष पहले जब जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज गवर्नमेंट का हो चुका था,

३.३० म.प.

संस्था तो मैंने गवर्नमेंट को सौंप दी, तो जैसे एक पिता अपनी पुत्री को ससुराल के अन्दर भेज देता है, उसके बाद ससुराल वालों का काम है कि उसको वह ठीक ढंग से रखे या न रखे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : लेकिन थोड़ा दहेज और दे दें साथ में।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दहेज का सवाल खत्म हो गया है, दहेज दे रहे हैं आपकी पार्टी वाले।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member will not disturb.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने जैसा पहले अर्ज कर दिया है कि नितान्त मेरिट्स के ऊपर मैं जाऊंगा। मैं यह भी कहूं कि जैसा हमारे धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर उस लड़की के दहेज के अन्दर कमी होने से उसको दुख पैदा हो जाता है और इसके अलावा ....

श्री उपाध्यक्ष : कॉलेज रूपी लड़की।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हां, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कॉलेज रूपी लड़की से आपका तात्पर्य है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कॉलेजरूपी लड़की! जब उसके साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट होता है ससुराल में, तो माता-पिता, बन्धु उसका बन्दोबस्त नहीं कर सकते। आज तो कानूनन यह भी हो सकता है, लेकिन यह बात जरूरी है कि वह लड़की क्लेश में पड़े बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि जैसा सेपलिंग्स के बारे में कहा, मैं अर्ज करूंगा कि थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा होते हुए, मैं गौरव के साथ कहता हूं और घमंड के साथ भी कहता हूं कि बारह वर्ष के काल के अन्दर जोबनेर के कॉलेज में, जहां दूसरे साइन्स और एग्रीकल्चर कॉलेज में आधे पास होते हैं, वहां जोबनेर में सेन्ट पर्सेन्ट रिज़ल्ट रहा है। इसके अतिरिक्त जोबनेर में एक भी लड़का फैल नहीं हुआ है और एक भी लड़का थर्ड डिविजन में पास

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

नहीं हुआ है। तो सदा से यह चीज चली आ रही है वह अब भी चल रही है। इसके वास्ते स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो मेरे कथन में कोई अत्योक्ति मालूम नहीं होगी !

मैं एक बात और भी निवेदन कर दूँ कि कि मैंने इस संस्था के सामने यह विचार रखा है कि गवर्नमेन्ट फोर्गिव एन्ड फोर्गेट और "टू लिव एंड लैट वलि"की पॉलिसी अपनावें। इस संस्था के अलावा चार संस्थाएं और चल रही हैं, तो बल के साथ कहने का मुझे अधिकार है। यह चीज हमारे सामने कई दफा आ चुकी है कि जब जब सवाल आया तो तीन-चार प्रश्न इसके वास्ते उपस्थित होते रहे हैं कि जोबनेर इसके वास्ते वाजिब जगह है या नहीं ? तो उस समय युनिवर्सिटी ने अपने कमीशन को गवर्नमेन्ट के चाहने से भेजा और उस कमीशन ने जाकर यह तय किया और कहा ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बहुत पुरानी बात हो चुकी है।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : पुरानी तो हो चुकी है, लेकिन मेरे लिये नई है। मैं जब तक जिन्दा रहूंगा उस समय तक इस चीज को कहता रहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय और असमय का ख्याल नहीं रखा जायगा ?

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): वसीयत में लिख कर जायेंगे।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : जैसे महामना मालवीयजी ने कहा था, अगर मेरी संस्था के ऊपर कोई दिक्कत पैदा होगी तो मेरे बाद में मेरी आत्मा चक्कर लगायेगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ऐसी कॉम्युनिटी में जन्म लिया है, राजपूत घर में कि मेरी आत्मा चक्कर नहीं लगायेगी, मैं भूत होकर चक्कर लगाऊंगा ....

**डॉ० बहादुरसिंह** : मुख्य मंत्रीजी को परेशानी हो जायगी।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : हो जाय तो हो जाने दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : शुद्ध आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : हो जायगी, तो हो जायगी। मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में युनिवर्सिटी ने उस समय जब कमीशन भेजा तो उन्होंने कहा : "We have seen each and every inch of the land which was given by the Thakur of Jobner and we can safely say that not only one Agricultural College, but several Agricultural Colleges can easily run there, and few Agricultural Colleges in India have such potentialities."

**श्री उपाध्यक्ष** : And every debate of yours, over the Budget Session contains this reference.

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : लेकिन बजट सेशन का सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि वह साल भर के अन्दर एक दफा आता है। तीन दफा के बजट तो मैं देख चुका हूं

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

और दो बजट और देख लूंगा एक–दो; और अब के बाद नहीं देख सकूंगा । लेकिन जो पंचवर्षीय स्कीम है,....

**डॉ० बहादुरसिंह** : इसमें व्यवस्था है आपके लिये ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : यह पांच वर्ष में आती है । मेरा निवेदन है, एक चीज़ जानना चाहता हूं कृषि मंत्री महोदय से कि इसमें १० पेज के ऊपर यह लिखा गया है कि राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है वह, और जोबनेर का कॉलेज है, इसके लिए ४६ लाख रुपया दिया जायेगा पंचवर्षीय स्कीम में और इसके अलावा ४६ लाख और युनिवर्सिटी के वास्ते खर्च होंगे । इसमें यह तो होवेगा नहीं कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी जोबनेर में होने वाली है या उदयपुर में होने वाली है, लेकिन यह बात जरूर है कि जहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी होगी उसको बहुत कुछ देना है । जहां डिग्री और पोस्ट डिग्री की क्लासेज़ होंगी उनके ऊपर भी खर्च पड़ेगा । बराबर की इन्स्टीट्युशन्स होते हुए भी हमारे मुख्य मंत्री ने कई दफा इस सदन के अन्दर कहा है कि "Both the institutions will run in absolute parity with each other." तो इस बात के वास्ते, मैं जानता हूं, वे कभी भी अपनी विचारधारा को बदलेंगे नहीं । मैं यह भी जरूर कहूंगा कि हमारे कृषि डिपार्टमेंट ने भी जब जब संस्था के वास्ते जरूरत हुई है उसके वास्ते काफी प्रयास किया है, और इसके लिए मैं ही नहीं, जोबनेर की जनता ही नहीं, लेकिन हजारों को तादाद के अन्दर ओल्ड स्टूडेन्ट्स, सब धन्यवादार्य अपने आपको समझते हैं । ऐसी परिस्थिति के अन्दर मेरा निवेदन है कि इस चीज़ से साफ नहीं हुआ कि वह ४६ लाख रुपया है, वह दोनों संस्थाओं के अन्दर बंटेगा या दर-असल में अकेले जोबनेर के कॉलेज को मिलेगा क्योंकि मेरा इसमें ज्यादा हक है । मैं तो यह समझता हूं कि मेरे और जोबनेर के किसी आदमी की डिक्शनेरी के अन्दर 'एन्वी' शब्द नहीं है लेकिन इमुलेशन है । ऐसी स्थिति के अन्दर कहा जा सकता है कि कि जब दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर जोबनेर को एक पाई नहीं मिली, टी. सी. एम. की तारीफ के अन्दर हम लोग आये नहीं हैं....

**श्री विशम्भरनाथ जोशी** (चांदीकुई) : Pie has been abolished now.

**श्री उपाध्यक्ष** : He means to say the least coin of rupee.

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : इसके लिए अर्ज करता हूं कि इस वास्ते आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा और सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन इस बात के लिए संकेत करे और गवर्नमेंट यह सोचे कि ४६ लाख की मदद जोबनेर को दे । वहां दो करोड़ के करीब ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं....

**डॉ० बहादुरसिंह** : दो करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : टी. सी. एम., जैसे हिमालय के ऊपर बारिश होती है, समुद्र में बारिश होती है, तो यह रकम जोबनेर कॉलेज को सुपुर्द कर दी जाय तो कोई हर्ज नहीं । मैं यह भी कहे बगैर नहीं रहूंगा कि यह तो मेरे क्षेत्र की बात है ; मेरा क्या मत-

# Page No.89



( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

लब, लेकिन एक बात जरूर है कि एक दफा शायद गवर्नमेंट का छोटे से लेकर बड़ा आदमी, कमीशन के आदमियों के अलावा, जाकर जोधपुर के वातावरण को देखे, वहां की चीजों को जाकर आंख से देखे। जो आंख से नहीं देखता है, मैं समझता हूं आंख और कान में एक बालिश्त का फर्क रहता है। मैं अपील करूंगा, कि अब यह बात नहीं होगी, आईन्दा जब मैं कहूंगा, इसके पहले यह बात हो जायगी।

शिक्षा के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है और यह बहुत बड़ा आयोजन है। इसके अतिरिक्त दूसरी भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कृषि से ताल्लुक रखने वाले, लाइव स्टॉक के वास्ते और जैसे पशु—धन के वास्ते व्यवस्था करने की बड़ी आवश्यकता है तो इसके लिये भी धीरे धीरे प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रयास एक दिन में सम्पन्न नहीं होता; जैसे कि उपमाएं दी जाती हैं, उदाहरण पेश किये जाते हैं कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे मुल्कों और गवर्नमेंटों के। मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट सैकड़ों वर्षों से इस चीज़ के लिये कार्य कर रही हैं। यहां यह कार्य थोड़े अर्से से हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी एडिफिस खड़ा किया जावे, जो भी महल खड़ा किया जावे तो उसकी नींव इस प्रकार की हो कि आइन्दा के लिये इसमें कमजोरी नहीं रहे। मैं मेरे मावली से आनेवाले माननीय सदस्य से इत्तफाक करूंगा और जहां तक हो सके, शिक्षा का प्रश्न है उसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। शिक्षा का प्रश्न है उसमें भी थोड़ी सी नकल नहीं करने के बजाय उसकी पद्धति को बदलना चाहिये और इसको बदलने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि आइन्दा काम करने वाले भारत के नवयुवक निकलेंगे वे मैकॉले के स्कूल के से नहीं लेकिन जो हमारे महामना महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाले हों और यहां के हिसाब से सम्बन्ध रहेगा वैसे होंगे। तो ऐसे मामलों में इसका आमूल चूल परिवर्तन करना उचित नहीं होगा, मगर इसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। समय आता और समय जाता है किन्तु इस चीज़ की आवश्यकता रहती है।

इसके अलावा हमारे यहां खनिज पदार्थों के लिये काफी गुंजाइश है और इसकी काफी जरूरत है। इसमें राजस्थान की भूमि बहुत रिच है, रत्नगर्भा है। इसलिये इसके लिये जहां तक हो सके इस तरफ उन्नति की जावे और इसके लिये प्रयास चालू है और ये प्रयास ठीक दिशा में चलते रहने चाहियें। यह सब की विचार—धारा है।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और निवेदन किये बिना नहीं रहूंगा कि राजस्थान में एक प्रश्न इन—कॉन्टेम्पटेशन का बहुत अर्से से चल रहा है और मैं भी इसकी आवश्यकता समझता हूं कि सवाई माधोपुर या धौलपुर में से ब्रॉडगेज रवाना होकर लालसोट—दौसा जावे और जयपुर से सांभर जावे....

**डॉ० बहादुरसिंह** : धौलपुर में ज्यादा अच्छा रहेगा।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : ठीक है, यह आपके लिये। वहां से दौसा होकर सीधी जा सकती है। इसलिये यह भी व्यवस्था

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

करना बहुत जरूरी चीज़ है। इसके लिये साभर में नमक और नमक से सोडा-एश फैक्ट्री का प्रश्न है। इसके लिये जरूरी है क्योंकि ट्रान्सशिपमेंट ट्रान्सपोर्ट में काफी दिक्कत पैदा होती है। तो इस प्रकार का प्रबन्ध हो जाए तो ठीक है। इसलिये यह विचारधारा चल रही है।

बाज वक्त इस प्रकार के पॉइन्ट्स आवेंगे, मैंने जैसे दूसरी चीजें देखीं, उस पर विचार होंगे और भगवान् महा विराट रूप धारण करें कि यह पंचवर्षीय योजना अच्छी तरह चल जाय क्योंकि दुनिया का वातावरण सेकिन्ड और मिनटों में बदलता रहता है। यह १२ वर्ष और १३ वर्ष में जिस प्रकार राजनीति यहां पर रही है उसको मैं थोड़ी सी बड़ी ऊंची दृष्टि से देखता हूं और दूसरे लोग भी देखते हैं। यहां पर आज तक कोई दूसरी गवर्नमेंटों में दिक्कत पैदा हुई उतनी नहीं हुई। बस, इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं। इसके पेश्तर कि हम इसकी पृष्ठ भूमि पर विचार करें इस पर भी हमें गौर करना चाहिये कि राजस्थान २२ रियासतों और अजमेर राज्य से मिल कर बना है। इसके साथ साथ यहां पर कितनी समस्याएं थीं उनको भी हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया है। जिस समय राजस्थान बना यहां पर डकैतियों का बहुत जोर था। जागीरदारियों और जमींदारियों का जोर था। उन सभी समस्याओं को हल करने में राजस्थान सरकार सफल हुई है और इसके परिणाम हमें मालूम होते हैं कि आज हम अपनी योजना को आगे बढ़ाने में अग्रसर हो रहे हैं। आज जबकि भूमि की समस्या, अन्न उत्पादन की समस्या हमारे देश में है उसको सुलझाने में बहुत कुछ किया है और सफलता प्राप्त की है। जब कि इस प्रदेश में जागीरदारियें थी उनका उन्मूलन किया, जमींदारियों का उन्मूलन किया। यही नहीं कि जागीरदारी प्रथा को ही समाप्त की हो बल्कि जो जमींदार और जागीरदार आलसी हो गये थे और जो कुछ भी श्रम नहीं करते थे उनको इस गति में पहुंचाया कि वे श्रम करने लग गये, व्यापार करने लग गये; यह भी हमने सुधार किया है। जहां हमने जागीरदारियों को समाप्त किया है और काश्तकारों को मालिक बनाया है वहां पर हमने जागीरदारों को भी काश्तकार बनाया है। जहां हमने जमींदारियों और जागीरदारियों को समाप्त किया है वहां पर हमने उनको काम पर लगाने की भी चेष्टा की है। इससे यह प्रकट होता है कि हमने जो कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिया था उसको सफल करने में पूरा पूरा प्रयत्न किया है। हमने जो जमीन जिसके कि काश्तकार मालिक होते हैं उनको भी हमने काफी हद तक अधिकार दिये हैं और इसी आधार पर हम सोचेंगे कि हमने बहुत कुछ सुधार किया है। हमने उनके लिये उनकी भूमि में कुंए खोदने के लिये तकावी और दूसरे प्रकार के साधन आमदनी को बढ़ाने के लिये किये हैं। इसके अलावा लगान भी हमारे यहां अलग अलग तरीके के थे और उनमें असमानता थी। कहीं ६

# Page No.91



( श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा )

गुना लगान था तो कहीं दो गुना लगान था यानी लगान में बहुत असमानता थी। कहीं १।६ बांटा लिया जाता था, इस सब को निश्चित किया है।

इसी प्रकार हमने भूमि समस्या को सीलिंग लगा कर ठीक किया है। साथ ही साथ काश्तकारों को खातेदारी राइट्स भी हमने दिये हैं। अब वे लोग भी समझने लगे हैं कि हम जमीन के मालिक हैं। इसके अलावा लाखों बीघा भूमिहीनों को जमीन हमने अलॉट की है जिससे बेकारी का प्रश्न हल होने में सहायता मिली है। आज हम यह कहें कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा; यह कहना गलत है। प्रोडक्शन बढ़ा है। हमारी स्थिति काफी इस मामले में सुधारी है। हम दूसरे प्रदेशों से अनाज मंगाते थे और अब हम दूसरे प्रदेशों को अनाज भेजते हैं; यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज हम यह सोचते हैं कि काश्तकारों को सिंचाई के साधनों से और जो तकावी आदि उनको मिलती है और बीज आदि उनको मिलने के साधन दिये हैं उनसे उनकी आमदनी अवश्य बढ़ी है। इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हम इसमें भी आगे बढ़े हैं। पहले हम बाहर से अनाज आयात करते थे और आज हमारा देश निर्यात करता है। इसलिए यह कहना कि काश्तकारों की भूमि में काश्त नहीं बढ़ी, यह बिल्कुल गलत है। अब यह कहना कि इर्रिगेशन के साधनों के लिये जो रुपया रखा गया था वह पूरा खर्च नहीं कर सके; मैं यह कहूंगा कि खर्च किया है और जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उनको हमने भूमि दी और उनको तकावी दी। हमने कुएं व छोटे छोटे नाडे—नाडियों के लिये तकावी देकर काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया है। हमने उन काश्तकारों के लिये अच्छे बीज और खाद के साधन जुटाये हैं। इसलिये काश्तकारों की आय बढ़ी है। इसलिये ऐसी स्थिति में यह कहना कि हमने जो इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टार्गेट रखा था वह पूरा नहीं हुआ, गलत है।

इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने ६४ करोड़ खर्च करने को रखा था और उसमें से ५४ करोड़ खर्च हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १ अरब, ५।। करोड़ रुपये रखे थे। उसमें से हमने १ अरब खर्च किये। इससे भी हम देख सकते हैं कि हमने इसमें पूरी सफलता प्राप्त की है।

अब हम तीसरी योजना को कार्यान्वित करने के लिए चल रहे हैं और उसके लिए आज हम यहां पर विचार—विनिमय भी कर रहे हैं। यह निश्चित है कि जो हमने सिंचाई के साधन जुटाये हैं वे माकूल जुटाये हैं और उसके साथ साथ चम्बल, राजस्थान नहर की योजना और दूसरी योजनायें चल रही हैं वे उपयुक्त हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान केनाल का जो राजस्थान सरकार पर खर्चा रखा गया है वह उपयुक्त नहीं है। राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं। भारत सरकार भी इसको पिछड़ा हुआ इलाका मानती है और जब मानती है तो जिस प्रकार पिछड़ी हुई जातियों के लिए जितने साधन जुटाते हैं और उन्हें ज्यादा तरज़ीह देते हैं उसी तरह से भारत सरकार को यह पिछड़ा हुआ इलाका होने के नाते राजस्थान के इस भार को वहन

# Page No.92



(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करना चाहिये। यदि यह ४५ करोड़ रुपया राजस्थान सरकार पर लाद दिया जावेगा तो राजस्थान की जनता पर करों का भार इतना बढ़ जावेगा कि उसको उसके लिए वहन करना मुश्किल हो जावेगा। भारत सरकार इसलिए खुद रुपया दे। राजस्थान अपने लिये अन्न उत्पादन में आत्म निर्भर है। राजस्थान के अलावा जो भारत की अन्न की समस्या है उसको हल करने के लिए भारत सरकार हमारे प्रदेश में जो साधन हैं उनको उपयोग में लाना चाहती है। इसलिए भी यह जरूरी है कि भारत सरकार राजस्थान नहर के कार्य को और खर्चे को अपने हाथ में ले और इस योजना को शुरू करे। प्रदेश के लिये इस योजना से बेकारी कुछ दूर होगी, मंडियां खुलेंगी, मिल; कारखाने खुल सकेंगे। उसके साथ साथ भारत सरकार को भी अन्न की समस्या को हल करने के लिए लाखों, करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा में देना पड़ता है उनमें कमी आवेगी। राजस्थान भारत का एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और यहां की जनता पर लगे कर भार की दृष्टि से भी यह खर्च का भार भारत सरकार को अपने यहां ही रखना चाहिये और राजस्थान पर नहीं डालना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार नई २ सिंचाई योजनायें बनाती है, उसके साथ २ हमारे राज्य में पुराने नाडे, तालाब, सिंचाई के जो साधन उपयुक्त हैं उनको सुधारने की व्यवस्था इसमें करें और दस करोड़ रुपयों का स्पेशल प्रोविज़न इस योजना में रखे तो उन साधनों को कायम रखा जा सकेगा। आज हम देखते हैं कि हर गांव में तालाब और पुराने नाडे बने हुए हैं जो कि पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिये गये हैं लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि उनको वे दुरुस्त करा सकें। वे कर भी नहीं लगा सकतीं क्योंकि करों का भार इतना पहले से ही लदा हुआ है कि वे अब नये कर नहीं लगा सकती। इसलिए ऐसे पुराने जो साधन हमारे यहां सौभाग्य से उपलब्ध हैं उनका सरकार को उपयोग करना चाहिये और इसलिए स्पेशल प्रोविज़न तृतीय योजना में रखना चाहिये जिससे कि वे नाडे, तालाब पंचायत समितियों के जो आज कब्जे में हैं उनको दुरुस्त किया जावे। उनको दुरुस्त करा देने से भी हमारे यहां अन्न का उत्पादन दुगुना बढ़ जावेगा। तालाबों की पालें व पानी आने की आवें टूटी हुई हैं, बेकार हो रही हैं लेकिन दूसरी ओर हम नई कई योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और पुराने साधनों पर तवज्जोह नहीं देते हैं। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए जरूर प्रावधान रखना चाहिये; यह मेरा सुझाव है।

कोई भी नई योजना लागू करें उसके बारे में पहले सोचें कि इस योजना से किस इलाके को लाभ होगा और वह कितना लाभ होगा और इससे किस इलाके को नुकसान होगा और वह कितना होगा। अजमेर में कापड़ का बांध बना तो पांच सौ कुएं गांवों के सुखा दिये गये और अभी ऊंटड़ा का बांध बना तो रूपनगढ़ के बहुत सारे कुंए सूख गये। इसका सर्वे कराया जाय कि क्या क्या आपत्तियां इससे आने वाली हैं। लेकिन यह कहा गया कि इसको देख लिया है, एक्सपर्ट

( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

से जांच करा ली है। ऊंटड़ा का बांध बना और रूपनगढ़ का सरसब्ज इलाका सूख गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नई योजना बनावें तो पहले इस पर पूरा ध्यान रखें। एक्सपर्ट की राय हो जाने से ही यह विचार न कर लें और जनता एक बांध बनाना चाहती है इसलिए उस ओर विचार कर लें और बना लें। लेकिन यह सोचना चाहिये कि एक इलाका सरसब्ज करते हैं तो कहीं दूसरा इलाका तो नहीं उजाड़ देते हैं। वहाँ भी जनता की केवल इच्छा पर ही यह फैसला नहीं किया जावे। यदि दूसरा इलाका उस योजना से सूखता है तो उस योजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहिये। जहां ऐसी योजनाओं से नुकसान हुआ है वहां के लिए अवश्य ही आपको इस योजना में प्रावधान रखना चाहिये और उसके लिए पानी के साधन जुटाने चाहिये।

मैं यह बात मानने लिए तैयार नहीं हूं कि लोगों में फर्टीलाइज़र को काम में लेने की अक्ल नहीं है, जैसा कि श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा था कि लोगों में ज्ञान नहीं है कि फर्टीलाइज़र को कैसे डालें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि फर्टीलाइज़र की मांग बढ़ रही है और यह मांग १ लाख टन तक हो गई है। यदि जमीन में फर्टीलाइज़र डालने का उनको ज्ञान नहीं होता तो वे कैसे मांग कर रहे हैं और क्यों जमीन में डाल रहे हैं? उनकी मांग का यह स्पष्ट अर्थ है कि उनमें यह बुद्धि आई है। फर्टीलाइज़र का वे उपयोग करना चाहते हैं और जमीन में उसको डालना चाहते हैं। हनुमानगढ़ में जो फर्टीलाइज़र का कारखाना खुलने वाला है उसके लिए जल्दी से जल्दी भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये कि जल्दी से जल्दी इसको खोलें क्योंकि वहां पर वह मेटीरियल मौजूद है और यह दूसरी जगह जाता है, हमारे यहां भी काम आ सकता है।

हमारे खाद्यान्न के साथ साथ हम यह सोचें कि औद्योगिक विकास भी होना चाहिये। अगर औद्योगिक विकास नहीं होता है तो हमारे उत्पादन को लगाने के लिए साधन नहीं रहते हैं। यह कहा जाता है कि हमारे यहां उद्योगों की कमी रही है। निश्चित रूप से कमी रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन हां, जो साधन पॉवर के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलने चाहिये थे उतने वे नहीं मिले। जो चम्बल और भाखरा से हमको बिजली मिलेगी उससे साधन पूरे पूरे हो सकेंगे। टेक्सटाइल की मिलें बन्द होने का कारण यह नहीं था कि सरकार ने सहयोग नहीं दिया। किशनगढ़ की मिल के लिए मैं कह सकता हूं। उसको सरकार सहायता देने के लिए तैयार थी लेकिन उसकी अर्थ व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि कोई भी हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था और भारत सरकार ने उसको कबाड़खाने में बेचने की राय दी। यह कहना गलत है कि राजस्थान सरकार ने सहयोग नहीं दिया। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान सरकार बड़े बड़े उद्योगों के लिए लोगों को सहयोग प्रदान करती है। किशनगढ़ में कपड़े की ऑटोमेटिक मिल लग रही है वह उद्योग के विकास की परिचायक है। उद्योग में तरक्की हो रही है। उसमें यह नहीं कि चक्कर देने का सवाल हो।

उद्योगपतियों के लिये कहा गया कि

( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

उनको किसी प्रकार से उत्साहित नहीं किया जाता। आप देखिये किशनगढ़ में नया मिल खुल रहा है। राजस्थान सरकार ने पॉवर के लिये उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि उद्योगपतियों की सेवायें नहीं ले रहे हैं, यह गलत बात है। उदयपुर में कारखाना, मिल खुलने जा रही हैं, यह इस बात का संकेत है कि उद्योगपति यहां कारखाना व मिल खोलने में रुचि ले रहे हैं। इसके साथ साथ ब्यावर का मिल और भीलवाड़ा के मिल बन्द हो गये थे। उनको सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो उससे फायदा हुआ है, यहां का उत्पादन बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में उद्योगों की उन्नति नहीं हो रही है, यह कहना ठीक नहीं है।

हम उद्योगों को इस प्रकार से शुरू करें जिससे हमारे देश की अर्थ नीति में रुकावट नहीं हो। विदेशी मुद्रा की जो कमी आज हमें दिखाई दे रही है उसकी पूर्ति किस प्रकार के उद्योगों से हो सकती है; इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। जिस समय दूसरी योजना चालू की गई उस समय हमारी विदेशी मुद्रा ७४४ करोड़ रुपये की थी। आज हमारे पास करीब केवल १४४ करोड़ तक रह गई है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिये कि हम ऐसे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दें जो हमारे देश की जरूरियात को पूरा कर सकें, जिन वस्तुओं का निर्यात विदेशों में हो उसका ध्यान हो सके तभी हमारे उद्योगों को ज्यादा बल मिल सकता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो उद्योग खोले जायं, जो कार्य किया जाय उससे देश के निर्यात को फायदा हो! देश के उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ साथ राजस्थान में जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है इससे राजस्थान के लोगों के जीवन-स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि आज जितने भी कर हैं उनका भार सामान्य जनता बर्दाश्त करती जा रही है। आज वह भिखमंगापन नहीं है जैसा संवत् १६५६ में जब कि १० सेर का अनाज बिकता था उस समय बच्चों को बेचने की नौबत आ गई। लेकिन आज दो सेर का अनाज होते हुए भी लोग उसको खरीद रहे हैं और अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारे यहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, आर्थिक स्तर ऊंचा उठा है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हमारा देश पीछे जा रहा है कतई उचित नहीं है।

लेकिन इसके साथ साथ यह निश्चित् बात है कि अफसरों को जो कार्य सौंपा गया है उसमें केन्द्रीकरण बहुत ज्यादा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। यदि हम इनके कार्यों में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर देते हैं तो हमारे उद्योग धंधों की योजनायें हैं वे पूरी तरह से सफल हो सकती हैं। आज एक योजना को शुरू से लेकर आखिर तक मन्जूर करवाने में ही काफी समय लग जाता है।

( ४.३ म० प० )

( श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन )

इसलिये हमारी योजनायें पड़ी रहती

( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

हैं। इसका खास कारण यह है कि हमने सत्ता का केन्द्रीकरण कर रखा है, इसका विकेन्द्रीकरण नहीं किया है । जब हमने पंचायतों का निर्माण किया उनकी संख्या ४ हजार से भी ऊपर जाने वाली है; ऐसी हालत में पंचायतों के जरिये विकेन्द्रीकरण किया है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार उनको दिये हैं जिससे वे अपनी योजनायें आदि मन्जूर कर सकती हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकती हैं। तो हम क्या अपने आॅफिसरों पर विश्वास करके उनको ज्यादा अधिकार नहीं दे सकते ताकि वे समय पर मन्जूरी दे दें और योजनायें पूरी तरह से कार्यान्वित हो सकें ? हम पहली योजना में और दूसरी योजना में इसी कारण पिछड़े रहे हैं। यदि हम अफसरों को अधिकार ज्यादा नहीं देंगे तो कहीं हम तीसरी योजना में भी पिछड़ न जायं, यह भय रहेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हम पूरा पूरा ध्यान दें । सत्ता के विकेन्द्रीकरण का जो कार्य हुआ है उसके साथ साथ जितने भी कार्य जिला स्तर या पंचायत स्तर के हों पंचायत समितियां करना चाहती हैं उन पर किसी प्रकार का अंकुश न रखें ताकि वे काम करने से रुक न जायं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का असली मकसद तभी हल होगा जब कि हमने जिस प्रकार से पंचायत समितियों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है उसी प्रकार से पूरा नियन्त्रण रखते हुए अफसरों में भी अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर दें । फिर यदि कोई बेईमानी करता हो तो उसको शीघ्रातिशीघ्र सजा दें, काम में जो अक्सर रुकावट डालता हो तो उसे सजा दें, तभी योजनाओं को सफल बनाने में हम अग्रसर हो सकते हैं।

आज हमारे सामने तीसरी योजना है । इसमें बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता है । हमको बहुत सारे कर लगाने पड़ेंगे । जहां तक कर लगाने का सवाल है इसमें किसी को हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये ; लेकिन कर लगाते वक्त यह तो जरूर सोचना होगा कि आखिर इन कर का भार किस प्रकार की जनता पर पड़ता है । आज सामान्य जनता जो कर के भार से पहले से दबी हुई है सेल्स टैक्स, मनोरंजन व यात्री टैक्स आदि इतने प्रकार के टैक्स हैं कि वह ज्यादा टैक्स और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या यह कर का भार उन्हीं पर पड़ने वाला है या जो इस कर को सहन कर सकती है उस जनता पर इसका भार पड़ने वाला है ? इसके साथ साथ हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि दूसरी योजना में जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि हुई है आखिर वह किसकी जेब में गई है ? इसके लिये भारत सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी चाहिये कि वह इस तरह की कमेटी का निर्माण करे जो वह जांच करे कि इन पंचवर्षीय योजना से जो आय की वृद्धि हुई है वह आखिर किसकी जेब में गई है। जहां हम समाजवादी समाज के लक्ष्य की स्थापना का उद्देश्य सामने रखते हैं तो इस ओर कदम अवश्य उठाना चाहिये; नहीं तो हम किये हुए वायदे से विचलित होते हैं।

आज यह कहा जाता है कि दूसरे देशों-चीन इत्यादि ने काफी प्रगति की है। लेकिन

( श्री पुरूषोत्तमलाल मर्शा )

वहां की शासन प्रणाली हमारे यहां से भिन्न है। आप साम्यवादी देशों को ही ले लीजिये। चीन ने अपनी समस्या का हल कर लिया लेकिन वहां की शासन प्रणाली हमारे से भिन्न है। जब कि हम प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखते हैं तो हमें उसी तरीके से काम लेना होगा तभी हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिये अवश्य कमेटी बैठाई जानी चाहिये; प्रति व्यक्ति जो आय की वृद्धि हुई है आखिर वह किसकी जेब में गई है ?

यह निश्चित है कि हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और वह किसान है। आज उनके घरों में खुशहाली है। किसान के पास जो पहले साधन थे आज उनके पास उससे कहीं अधिक साधन हैं ; पहले से हालत ज्यादा ठीक है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां किसान की हालत में कम सुधार हुआ हो। अधिकतर किसान लोग आज अच्छी हालत में हैं। आज वे अपने पैरों पर खड़े होने लग गये हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने उनको कई तरह की सहायता दी है जैसे तकावी ऋण, कुंओं के लिये ऋण। इनसे उनको बहुत कामयाबी हुई है। इससे हमारा जो लक्ष्य था आगे बढ़ने का उसमें हमने कामयाबी हासिल की है; हम पीछे नहीं हटे हैं।

इसके साथ साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमने एक गलती अवश्य की है वह है पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने की। हमने टीनेन्सी एक्ट में एक धारा रखी है। एक काश्तकार पांच साल के लिये अपनी भूमि लगान पर दूसरों को काश्त के लिये दे सकता है। यह पूंजीवादी व्यवस्था का अंग है। इससे बड़े बड़े पूंजीपति जमीन को लेकर दूसरों को लगान पर काश्त के लिये दे देंगे। इससे पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां हमारा समाजवादी समाज का लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता। होना यह चाहिये कि जो खुद काश्त करता हो उसी के पास भूमि रहनी चाहिये और जिसके पास ज्यादा हो उससे ली जाकर भूमिहीन को दी जानी चाहिये। इससे हम समाजवादी समाज की स्थापना करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो दूसरी योजना में कृषकों के लिये कानून बनाये, जो साधन जुटाये उनके साथ साथ इसमें जो प्रोविज़न रखे हैं वे नितान्त अनावश्यक हैं; उन्हें उठा देना चाहिये। इसलिये निवेदन करूंगा कि तीसरी योजना काल में ऐसा प्रोविज़न रखा जाना चाहिये कि जो खुदकाश्त करने की इच्छा रखते हैं वे ही जमीन रख सकेंगे यानी जमीन वे ही रख सकेंगे जो खुदकाश्त करेंगे या नौकरों के द्वारा करावेंगे, अन्यथा भूमि सरकार के कब्जे में आ जावेगी। ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह पूंजीवादी वृत्ति कायम रहेगी। इन लक्ष्यों को सामने रखते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ती जावेगी।

इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो चिकित्सा में जहां बहुत कुछ प्रोविज़न रखा है वहां आयुर्वेद के लिये एक करोड़ और कुछ लाख रुपया ही रखा है जो बहुत कम है। हमें याद रखना चाहिये कि हमारा प्रदेश गरीब है और इसमें भी हमारे प्रदेश में आयुर्वेद का महत्व बढ़ा हुआ है। इससे लोग ज्यादा प्रसन्न हैं। इसको चिकित्सा में

( श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा )

विश्वास रखते हैं । ऐसी स्थिति में आयुर्वेद चिकित्सा के लिये ज्यादा पैसा रखना चाहिये और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये । हमारा मुल्क गरीब है । दूसरे पूंजी पति मुल्कों की तरह यहां बड़े बड़े डॉक्टरों की बड़ी बड़ी अस्पतालों और ऊंची ऊंची दवाइयों की व्यवस्था में करोड़ों रुपया खर्च करने में हम आगे चल कर असमर्थ रहेंगे । अगर आज इसे काफी रुपया खर्च करके लागू भी कर देंगे और बढ़ाते रहेंगे तो भी लोग इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा पावेंगे । इस पर हमें सोचना चाहिये । इसलिये आयुर्वेद पद्धति पर ही ज्यादा जोर देना है ।

इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्द्धन किया गया है और बड़े बड़े साधन जुटाये हैं वह अच्छी बात है; पर अभी हमें यह सोचना चाहिये कि आज जो शिक्षा हम दे रहे हैं उससे हमारे देश की प्रगति हो रही है या नहीं, इस पर पूरा पूरा विचार करना चाहिये । शिक्षा पर हम रुपया खर्च कर दें : यह दूसरी बात है, अक्षर ज्ञान दे दें यह दूसरी बात है हालां कि यह भी आवश्यक है । लोकतन्त्र में अक्षर ज्ञान का भी नहीं होना बहुत बड़ा, भारी पिछड़ापन माना जाता है । इसलिये अक्षर ज्ञान देते हैं यह तो अच्छा है ही; पर इसके साथ साथ ऐसा ज्ञान भी प्राप्त करावें जिससे कि वह पढ़ कर अपने कार्य में आगे बढ़े । आज हमने जो बेसिक स्कूलें खोली हैं यह ठीक है; पर उनमें साधन पूरे नहीं दिये । आज मैं देखता हूं बेसिक शिक्षा के नाम पर स्कूलों में तकली चलाना सिखाया जाता है । आज के इस रॉकेट के जमाने में इन बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मिलों के जमाने में इस बढ़े हुए बड़े मशीनरी के युग में खाली तकली चला कर....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आप भी खद्दर पहिने हुए हैं न आज के ही जमाने में ?

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बच्चों की जिधर रुचि है अगर उनकी रुचि तकली चलाने में है तो अवश्य उनको तकली देनी चाहिये, पर हमें आज मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चों की रुचि को देखने की व्यवस्था करनी चाहिये और उनकी जिधर रुचि हो उनको उधर ही ले जाने के पूरे पूरे साधन देने चाहिये । पर आज हम हर बच्चे को तकली चलाने बैठावें और कहें कि बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, यह गलत है ।

आज हम बेसिक स्कूलें चलाते हैं, टीचर देते हैं फिर भी आज क्या है ? कोई साधन नहीं, कार्पेन्टरी, लुहारी इत्यादि का साधन नहीं है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें इन साधनों को देने की तरफ ध्यान देना चाहिये । बजाय तीसरी योजना में नये स्कूल खोलने का काम कम करके आप मौजूदा स्कूलों के साधनों को और अधिक बढ़ावें । यह मेरा निवेदन करना है ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके और बच्चे शिक्षालयों से निकल कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें । आगे जाकर वे नौकरी के लिये लॉर्ड मैकॉले की पद्धति पर न जाकर देश की बेसिक पद्धति पर जिस पर हमने अपने को आधारित किया है उसकी ओर जावें । तो ऐसी योजना आप बनाएं तो

( श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा )

ज्यादा अच्छा होगा ।

मैं एक निवेदन और कर देना अवश्य चाहूंगा कि हमें भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहिये कि रेलवे वे नई निकाल रहे हैं तो इसके लिये परबतसर से किशनगढ़ तक एक रेलवे लाइन का टुकड़ा निकालने की योजना बनाने के लिये भारत सरकार से अवश्य निवेदन करना चाहिये । परबतसर से किशनगढ़ तक इतना ट्राफिक रहता है मारवाड़ का कि उसको देखते हुए यह १५–२० मील का टुकड़ा मिला दिया जाना बहुत जरूरी है । इससे मारवाड़ के लोगों को राजधानी में आने में काफी सहूलियत होगी । इसलिये निवेदन करूंगा कि इस ओर भी आप ध्यान दें ।

सरकार ने कृषि के लिये और उद्योग के लिये जो भी प्रयत्न किये हैं आज तक वे काफी सराहनीय हैं और इसके लिये मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । राजस्थान सरकार ने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में काफी परिवर्तन किये हैं और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिये काफी लोगों को सहायता दी है । मैं भी मेरे इलाके की ओर से धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि जो इलाका हमारा दुखी था वहां राजस्थान सरकार ने एक उद्योगपति को बुला कर प्रोत्साहित किया और ऑटोमेटिक मिल–कपड़ा मिल लगाने का लाइसेन्स दिया और उसे बाध्य किया कि वह किशनगढ़ में लगाओ । तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरफ अगर प्रोत्साहन देंगे तो प्रान्त आगे बढ़ेगा । इसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती । आज भी हम यह नहीं कह सकते कि हम इन अर्थों में पीछे रहे हैं । हमारे प्रदेश की प्रगति हो रही है बल्कि कई बातों में प्रगति करने के लिये हमने देश का मार्गदर्शन किया है । हां, यह कहें कि हम उद्योगों में व बिजली के पॉवर में दूसरों से कुछ पिछड़े हुए हैं तो कुछ ठीक....वैसे हम अपने यहां की जो पहले स्थिति थी उससे काफी आगे ही बढ़े हैं । मैं निवेदन करूं कि राजस्थान बनने से पहले हमारे पास क्या साधन थे, आज नये ही जुटाये और लगाये हैं । ऐसी स्थिति में कह देना कि हम पिछड़े जा रहे हैं; यह सही नहीं है । पॉवर के ही बारे में कहना चाहता हूँ, जितना पहले खर्च होता था उससे आज चौगुना खर्च होता है । वह पॉवर हाउस ही तो दे रहे हैं । तो ऐसी स्थिति में कह देना कि पॉवर की बढ़ती नहीं हुई, ठीक नहीं है । कह देते हैं न कृषि उत्पादन हुआ, न इन्डस्ट्री हुई । हो सकता है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पीछे रहे हों । पर यह भी ख्याल रखें कि हमारा राजस्थान किस आकार–प्रकार से बना है । दूसरे इलाके पहले से आगे बढ़े हुए थे और हम कितने उनसे पिछड़े हुए थे । उन सब को दृष्टि में रखते हुए कहें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमने अपनी पिछली दो योजनाओं से अपने साधन जुटाये हैं और आगे बढ़ने में हमने पूरा पूरा प्रयत्न किया है ।

**श्री सभापति** : श्री लक्ष्मीचन्द ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : सभापति महोदय, आज जो हमारे सामने तीसरी योजना का लक्ष्य रखा गया है इसको बनाने से पहले हमको यह सोचना चाहिये कि पहले जो हमने लक्ष्य बनाये थे वे पूरे हुए हैं या

( श्री लक्ष्मीचन्द )

नहीं ? पहले से ही लक्ष्य इस ढंग से बनाना चाहिये कि जिन्हें हम पूरा कर सकें। हमें उतनी ही हिम्मत करनी चाहिये जितनी ठीक ढंग से कर सकते हैं; यह नहीं कि हम अभी तो बातें बहुत कर लें पर उनको पार नहीं डाल सकें आगे चल कर। हमने पहली योजना बनाई; पर इसमें प्लान के माफिक पूरा पैसा खर्च नहीं कर सके आप। दूसरी बनाई, उसमें भी पूरा नहीं कर पाये; ऐसा प्लान की आपकी रिपोर्ट से पता चलता है। इसलिये मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि हम कोरी प्लानें बनाते हैं। बाद में तो हमारे काम प्लान के अनुसार ठीक तरह से लागू ही नहीं होते; बिना विचारे बनाते हैं। इसलिये पहले पूर्णतया सोचना चाहिये कि जो प्लान बनाने जा रहे हैं; उतना रुपया उसके अनुसार उतने समय में हम खर्च भी कर सकते हैं या कर सकेंगे या नहीं। आप थोड़ा बनाइये, पर उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट करिये। यह नहीं होगा तो रिज़ल्ट क्या होगा ? प्लान बनाने भर से और किताबें छाप देने भर से कुछ नहीं होने का। तीसरी योजना में आपने सड़कें बनाने का प्लान बनाया; पर इसके मुताबिक आप करते नहीं तो इससे यही जाहिर होता है कि आप योग्य नहीं हैं, आपकी मशीनरी अयोग्य है। आपको पहले उसको ठीक तरह से सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।

इसी तरह सिंचाई के बारे में मैं बताऊं। जवाई के बारे में आपने योजना बनाई थी। पर आप देखें, क्या हुआ ? जवाई की योजना पूरी हो चुकी है पर जल का संग्रह पर्याप्त नहीं हुआ है, आपकी यह रिपोर्ट है। फिर क्या योजना आपने बनाई ? आपको यह पूरा पता नहीं लग पाता कि योजना बनाने जा रहे हैं पर पानी इसमें पूरा आवेगा या नहीं। जब यह पता नहीं तो आपने फिर क्या तो योजना बनाई और क्या उस पर अमल किया ? जब आपके पास पूरा प्लान नहीं है, आपको यही पता नहीं कि यह बनाने जा रहे हैं बन जाने के बाद इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा या नहीं तो फिर इतना पैसा खर्च करना और योजना बनाना; इसका क्या मकसद है ? जितना कर सकते हो, उतना ही हाथ में लेना चाहिये।

इसमें खुशी है मुझे कि मेरे जिले के लिये, सांचोर तहसील के लिये हमारे राज्य के मुख्य मन्त्रीजी ने केबिनेट की मीटिंग के वक्त में इस किस्म का ऐलान किया था कि सांचोर में लूनी नदी की योजना चालू की जावेगी। और इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इस योजना को दिखाया गया है। इस बात की मुझे जरूर खुशी है लेकिन यह योजना कहीं कागजातों में न रह जाये। मैं इस योजना के बनाने से पहले इस योजना के लिए कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, यह योजना जो आप बंध बना कर बनाना चाहते हैं उसके लिए उस जगह पर पानी को रोकेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां की भूमि ऐसी है कि पानी इकट्ठा होने से खराब हो जाती है। आपको इस तरह का बंध बांधना चाहिए कि जिससे पानी टकराये और फैल जाये। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि पानी बहुत आता है और पानी का बंध होने से नदी का

( श्री लक्ष्मीचन्द )

बहाव गहरा भी हो गया है। पहले सांचोर जिले में हजारों मन गेहूँ पैदा होता था आज वह गेहूं पैदा होने कम हो गए हैं। कारण यह है कि जगह जगह बंध हो गए हैं और नदी का बहाव गहरा हो गया है। यह योजना जो सरकार ने बनाई है उसमें इस तरह के बंध बनने चाहिये कि जिससे पानी इकट्ठा नहीं हो और पानी आये, टकरा जाये और फैल जाये ताकि पैदावार भी ज्यादा होने लग जाये।

सभापति महोदय, सड़कों के लिए जैसलमेर, सांचोर से बोर्डर तक का....

**डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) :** यह बात बहुत पुरानी है।

**श्री लक्ष्मीचन्द :** इस जमाने में नई है। तो सभापति महोदय, सड़कों के बारे में हमारी सरकार ने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में बहुत कम पैसा रखा है। मैं इसके लिए सुझाव दूँगा कि राजस्थान के तहसील हैड-क्वार्टर्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स डामर रोड से कनेक्ट होने चाहिए...

**डॉ० बहादुरसिंह :** इसके लिए इसमें व्यवस्था है।

**श्री लक्ष्मीचन्द :** व्यवस्था तो है लेकिन जो पैसा रखा है वह बहुत कम है। इसका नतीजा यह होगा कि हमारा पैसा खर्च हो जायेगा और सड़कें पूरी नहीं हो सकेंगी। क्योंकि राजस्थान में कई जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां कि मेटीरियल उपलब्ध नहीं होगा। मेरे जिले में ही कई जगह सरकार को दुविधा आयेगी कि जहां मेटीरियल उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए जो प्लान में आपने पैसा रखा है वह बहुत कम रखा है। इसलिए विशेष पैसे के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भारत सरकार से इसके लिए मांग करनी चाहिए कि हमारे राजस्थान को सड़कों के लिहाज़ से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। जब तक हमारे रोड कनेक्शन्स ठीक ढंग के नहीं होंगे तब तक हमें पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आज मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र में जाना हो तो उनको दो दिन कम से कम लगेंगे और अगर यातायात और सड़कों के साधन ठीक तरह से उपलब्ध हो सकें तो २४ घंटे में भी पहुँचा जा सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बाजी दफा तो डाक भी बन्द हो जाती है बरसात में और १५-१५ रोज तक डाक नहीं मिलती है।

रोड्स बनाने के साथ ही साथ आपने ग्रेवल रोड का सुझाव दिया है। मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में ग्रेवल रोड सक्सेसफुल नहीं होती है। आप तो इसलिए कंकरीट रोड और डामर रोड ही बनवायें। ऐसा नहीं कि जैसा आपने रानी-कुंआ और बड़ गांव के बीच सड़क बनवाने में खर्चा कर दिया और यह रोड नहीं बनी और उसमें गड्ढे पड़ गये हैं। ऐसी रोड्स बनाने से तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। हम जो टैक्स से पैसा देते हैं वह पैसा व्यर्थ जायेगा और हमारा जो पर्पज़ है वह सर्व नहीं होगा। इसलिए हम रोड चाहे कम बनवायें लेकिन जो भी बनवायें वह मैटल्ड रोड बननी चाहिए।

आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं पर

( श्री लक्ष्मीचन्द )

जो भी काम होता है उसको खुद नहीं देखते और इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स पर ही सारी बात छोड़ देते हैं और उनके भरोसे पर लाखों रुपयों का पेमेंट कर देते हैं। वास्तविक उन सड़कों की क्या हालत है, वह स्वयं जाकर देखें।

इस प्लान में जो पैसा रखा है उससे भी और विशेष पैसा मांगना चाहिए। अगर हमारी रोड्स ठीक होंगी तो हमारे कॉम्युनिकेशन्स ठीक होंगे और इससे हमारे यहां के बाजार भाव पर असर पड़ेगा और वह कम हो जायेगा क्योंकि रोड ठीक बन जाने से काफी चीजें मिलने लगेंगी और भाव कम होंगे।

इसके अलावा आजकल इस प्लान के माफिक हम देखते हैं कि मुख्यत: पैसा शहरों में ही खर्च हो रहा है। मेरा यह विरोध नहीं है कि यह पैसा यहां खर्च क्यों हो रहा है, लेकिन जहां तक ग्रामीण जनता का प्रश्न है एक तरफ तो हम कहते हैं कि शहरों में राज्य की १८ प्रतिशत जनता रहती है और गांव में ८२ प्रतिशत रहती है। आप शहरों में बिजली देते हैं, दीजिए; लेकिन जहां तक ग्रामीण जनता का प्रश्न है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा कीजिए। राजस्थान में कम से कम आप ऐसी योजना बनायें कि दस–बीस गांवों को बिजली तो उपलब्ध हो जाये। आप केवल यह इरादा लेकर बैठे रहें कि हमको शहरों में ही बिजली देनी है या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर ही बिजली देनी है तो यह तो एक प्रकार से भेदभाव की नीति हो गई। आपको ग्रामीण जनता की सुविधा की बातों को भी ध्यान में रखना है। हम कहते हैं कि आज ८२ प्रतिशत ग्रामीण जनता है और १८ प्रतिशत शहरों की है। तो अगर आप ग्रामीण जनता पर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो खर्च करें जितना कि आप शहरों में खर्च करते हैं। इतना तो कम से कम ग्रामीण जनता के लिए प्रावधान होना चाहिये। ग्रामों की जनता चाहती है कि तेल के दीये आंधी के दिनों में बुझ जाते हैं और कई दफा आग लग जाती है उसके बदले में अत: हमें भी बिजली का उजाला चाहिए।

इसके अलावा मुझे स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना है। इस पुस्तक में इस प्रकार का संकेत किया गया है कि स्वास्थ्य के बारे में हम काफी उन्नति कर रहे हैं। हम इतने बैड्स देना चाहते हैं। उसके लिए मैं इसमें से एक लाइन पढ़ कर सुना देता हूं: "जिन लोगों ने अस्पतालों के बाहर रह कर इलाज करवाया है उनकी संख्या ६४ लाख, १६ हजार है और जिन्होंने अस्पतालों में रह कर इलाज करवाया है उनकी संख्या १ लाख,७६ हजार है।" यह तो आपकी स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति है ....

**डॉ० बहादुरसिंह** : वह तो आउट डोर पेशेन्ट्स के बारे में है।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : आउट डोर नहीं हैं।

**श्री सभापति** : आप कौनसी किताब रेफर कर रहे हैं ?

**श्री लक्ष्मीचन्द** : तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी बैड्स देने हैं वे तो ठीक हैं लेकिन लोग बाहर क्यों इलाज

( श्री लक्ष्मीचन्द )

कराते हैं ? लोगों को इलाज सस्ता सुलभ नहीं होता है। यह इतना महंगा हो गया है कि एक मरीज़ को मामूली सी बात के लिए अगर वह डिस्पेन्सरी जाता है तो डॉक्टर उसको फौरन कह देगा कि यह इन्जेक्शन ले आओ। तो इसका मतलब तो यह होता है कि या तो दवाखानों को पूरी तरह से दवाइयां नहीं मिलती हैं और अगर मिलती हैं तो उसका बराबर युटीलाइजेशन नहीं होता है।

प्लान का जो इम्पलीमेन्टेशन करनेवाले हैं यह तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्लान में जो भी पैसा रखते हैं उसका उपयोग ठीक तरह से होता है या नहीं, यह देखें। आपने डिस्पेन्सरीज़ के लिए कहा है कि हमें विशेष डिस्पेन्सरीज़ भी खोलनी पड़ेंगी। मैं तो यहां तक बताने के लिए तैयार हूं कि जालोर जिले का किस्सा है कि वहां का आदमी ४०,००० का डोनेशन लेकर आया और कहा कि हमारे यहां पर डिस्पेन्सरी खोल दी जाये लेकिन हमारी सरकार ने टोटल्ली रिफ्यूज़ कर दिया और कह दिया कि हम तो हमारे प्लान के अन्दर एक ब्लॉक में एक ही प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलते हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमें इलाज की सुव्यवस्था करनी है और दूसरी तरफ जब जनता का सहयोग प्राप्त होने को होता है तो कह देते हैं कि प्लान में स्कीम नहीं है। तो आपको अपनी स्कीम ऐसी बनानी चाहिए कि जहां पब्लिक डोनेशन आपको मिलता है और पब्लिक से किसी प्रकार की मदद मिलती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए और उस पैसे का प्रयोग करने और सही उपयोग करने के लिए आपको प्लान में ऐसा प्रोविजन रखना चाहिये कि अगर पब्लिक मदद मिलती है तो वहां वह डिस्पेन्सरी खोल दी जायेगी। उसमें सरकार का बिगड़ता ही क्या है ?

मैं आपको बताऊं कि कई लोग तो अपने नाम के खातिर लाखों रुपया खर्च करने को तैयार रहते हैं। कई ऐसे सामाजिक लोग हैं कि केवल उनका नाम डिस्पेन्सरी पर लिख देने मात्र से ही लाखों रुपये का दान दे सकते हैं। तो हमारी सरकार को ऐसे दान की भी कद्र करनी चाहिये। यदि आप ऐसे दान की कदर नहीं करना चाहते और जब आप से चिकित्सा सुविधा के लिए कहा जाता है तो आप कह देते हैं कि एक पंचायत समिति या ब्लॉक के अन्दर एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम कर देंने जो साठ हजार की आबादी को कवर करने वाला है। इससे जनता को कोई राहत नहीं पहुँच सकती है। पब्लिक डोनेशन देने को तैयार है, जनता वहां पर ज्यादा इलाज कराने को तैयार है तो आपको या तो इन डोनेशन्स की कद्र करनी चाहिए या फिर डिस्पेंसरीज़ को बढ़ाना चाहिए।

आपका इस तरह की व्यवस्था करना चाहिये कि हर पंचायत क्षेत्र में एक एड-पोस्ट कायम होना चाहिये। हम सबसे पहले स्वास्थ्य चाहते हैं। कहते हैं कि "पहला सुख निरोगी काया"। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा और दूसरे साधन नहीं हुए तो उनको भी हम प्राप्त कर लेंगे, उसको भी उपलब्ध कर सकेंगे। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, हमारे स्वास्थ्य की हिफाजत ठीक ढंग से नहीं की गई तो हमारे दूसरे जो साधन हैं, आप एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना चाहते हैं सड़कें

( श्री लक्ष्मीचन्द )

बनाना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं तो उनके सुखों को कौन भोगेगा ? इसलिये हमारे स्वास्थ्य की अगर रक्षा करनी है तो प्लान के अन्दर अमाउन्ट ज्यादा बढ़ाना चाहिये । हर पंचायत क्षेत्र में एक एड पोस्ट हो; जहां जाकर इलाज करा सकें । एक कम्पाउन्डर वहां रहे जहां पर लोगों को मामूली मेडीसिन्स मिल जायं और आवश्यकता हो तो नजदीक में उपलब्ध डॉक्टर के पास पहुंच जायं और वहां से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर लें ।

दूसरा, सभापति महोदय, हमारे यहां जल की, पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या है ! राजस्थान में जल की बहुत कमी है और इसके लिए कई दफा लोग प्रयत्न करते हैं । सरकार सैंक्शन भी करती है अमाउन्ट । मैं तो यह भी कहता हूं कि मेरे गांव हडीचा के अन्दर २० हजार रुपया सैंक्शन किया गया बोरिंग के लिए और पब्लिक डोनेशन हुआ पांच हजार का, लेकिन साल भर से वह सारा पैसा लटक रहा है । कारण क्या है कि हमारे पास मशीनें नहीं हैं । सरकार को जल के कष्ट निवारण के लिए ज्यादा से ज्यादा बोरिंग की मशीनें मंगानी पड़ेंगी, इसके लिए आपको साधन बढ़ाने होंगे ! आप जल कष्ट निवारण करना चाहते हैं और एक जिले के अन्दर एक मशीन भी नहीं होगी तो जल कष्ट निवारण कैसे होगा ? राजस्थान के अन्दर इस तरह से तो दस-पन्द्रह साल में बारी आयेगी तो फिर यह अमाउन्ट स्वीकृत करने का क्या मतलब ? इसलिए सबसे पहले पीने का पानी मिलना चाहिये । हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा से तादाद में मीठा पानी मिले; नल से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सींच कर भी मिले, लेकिन पानी तो हरएक को चाहिये । हरएक गांव में ऐसे पानी के बेरे बनाने चाहिये ।

मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे इलाके में बाडमेर-जालोर में बहुत, विशेष पानी की कमी है । हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि राजस्थान में पानी की कमी है और इसका लक्ष्य निर्धारित करने के लिए श्री हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी बनाई उसके समक्ष भी सुझाव दिया : मगर उन सुझावों का परिणाम क्या होगा ,उस अमाउन्ट को देखते हुये हम देखते हैं कि बहुत कम धन-राशि रखी गई है: हम भी पानी पीना चाहते हैं । हमारे लिए पानी पीने के लिए चाहिये । हमारे यहां पानी बहुत गहरे में मिलता है, यहां तक कि बाडमेर इलाके में दो सौ फीट गहरे बेरे हैं । यदि इतना गहरा खोदा जाय तो पानी उपलब्ध हो जाय । लेकिन जब तक मशीनें नहीं होंगी, जब तक बोरिंग मशीनें ज्यादा तादाद में नहीं होंगी, एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बोरिंग मशीन देते हैं तो देहातों की तादाद को देखते हुए दो, चार साल में एक गांव की बारी आयेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है इस तादाद में पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिये, इस मद में ज्यादा पैसा रखना चाहिये ।

अब ज्यादा समय न लेते हुए, सभापति महोदय इन बातों को आपके समक्ष रखते हुए एक बात हमारे सार्वजनिक ,निर्माण मंत्रीजी से कहना चाहता हूं जिसे वे कान देकर सुन लें कि हमारे यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पब्लिक प्लेट फार्म पर इस किस्म का आश्वासन दिया था कि तृतीय पंचवर्षीय

( श्री लक्ष्मीचन्द )

योजना के अन्दर जोधपुर से जालोर, रानी वाड़ा–भीनमाल होते हुये सांचोर तक पक्की सड़क का प्रोविज़न रखा जायेगा । आप यदि उस वक्त में वहां मौजूद होते तो आपको मालूम हो जाता कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या संकेत किया था । उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ १२ मील की ही पक्की सड़क है जालोर से आहोर तक पक्की सड़क जाती है और बाकी सब कच्ची सड़क है । मुख्य मंत्रीजी ने जो इस किस्म का आश्वासन दिया था इसलिए आप कान देकर सुन लें कि इसके लिए भी आपको विचार करना है और इस योजना में इसकी व्यवस्था करानी है ।

इन शब्दों के साथ, मैं, सभापति महोदय जो तृतीय योजना का प्रारूप पेश है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उसका प्रोपर युटिलाइजेशन होना चाहिये । जिन जिन मदों में पैसा कम रहा है उनको बढ़ाने की मांग करनी चाहिये ।

**डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है उस पर विचार हो रहा है । योजना निर्माण करने के लिए खासतौर से हम इकॉनोमी प्लान्स तैयार करते हैं। इन इकॉनोमी प्लान्स के कारण भी कुछ होते हैं । क्योंकि जब तक हमारी योजना-बद्ध अर्थ व्यवस्था नहीं होगी हम कभी भी अपनी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिये राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था की अवश्यकता होती है । इस प्लानिंग के बारे में भी अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं । उनमें से केवल एक विद्वान् का मत सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । जॉन रिक्सन का जो मत इस बारे में है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं :

"व्यक्तिगत या सार्वजनिक अर्थ व्यवस्था श्रम का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबन्ध करना है विशेषयथा तीन अर्थों में श्रम की विचारपूर्ण आयोजना, इसके उत्पादन की सावधानी से सुरक्षा तथा इसके उत्पादन का उचित-वितरण ।"

इस प्रकार हमारी योजना जो है वह इस प्रकार से तीन विभागों में विभक्त हो जाती है ।

अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व प्रथम पंच-वर्षीय योजना जिसका उद्देश्य मुख्यतया यह था, यह मूल रूप में एक तैयारी की स्थिति प्राप्त करने की योजना थी और हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इस बात का लक्ष्य रखा कि जो है वो इन्डस्ट्रीज हैं और उनमें भी खास तौर से बेसिक इंडस्ट्रीज उनको प्रोत्साहन देंगे। लेकिन हम इन दोनों योज-नाओं में सफल हुए या नहीं, इस पर विचार कर लें । जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है हमने कृषि को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की थी । लेकिन इस पर विद्वानों और दूसरे आलोचकों का मत है कि हम सफल नहीं हो सके और यह कुछ मायनों में सही भी है और जहां तक हमारी दूसरी योजना का प्रश्न है हम अपने औद्योगीकरण और उद्योगों के विकास में भी सफल नहीं हो सके । इस कारण हमारे पास विदेशी पूंजी का अभाव था; हम कृषि की योजना में भी असफल रहे । इसका मुख्य

( डॉ० बहादुरसिंह )

कारण जन-संख्या में वृद्धि है। जनसंख्या की वृद्धि की तरफ हमने ध्यान नहीं रखा उसके कारण हम इसमें असफल रहे। क्योंकि योजना बनाते समय हमारी आबादी की सम्भवतः १.३ प्रतिशत वृद्धि होगी, ऐसी आशा थी और उसकी जहां तक गणना का प्रश्न है १.३५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। लेकिन अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी जब हिन्दुस्तान की आबादी २प्रतिशत बढ़ जायेगी। इस तरह हिन्दुस्तान की आबादी सन् ६१ में करीबइक्तालीस करोड़ हो जावेगी। इस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है....

**श्री पुरुषोतमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : डॉक्टर साहब के क्या विचार हैं, इस बारे में?

**डॉ० बहादुरसिंह** : इस तरफ से हमें आबादी की वृद्धि का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

अब मैं राष्ट्रीय आय के बारे में निवेदन करूं कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई उस पोइन्ट के बारे में भी हम कुछ सफल हुए। क्योंकि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में साढ़े अठारह प्रतिशत का अपना लक्ष्य रखा था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पच्चीस प्रतिशत था वह जाकर बीस प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार से जहां हम अपनी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि नहीं कर सके वहां बेकारी का प्रश्न भी है।

बेकारी के प्रश्न के सम्बन्ध में भी हम पूर्ण सफल नहीं हो सके। क्योंकि हमारी जब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस समय बेकारों की संख्या जैसा कि गणना से प्रतीत होता है ५० लाख थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होते २५ लाख की कमी हुई लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी तो बेकारों में वृद्धि होगी और ७५ लाख तक पहुंच जायेगी। इस तरह से जो लक्ष्य अपनी दो योजनाओं में हमने रखे थे उनके अन्दर भी बेकारी की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने समाजवादी समाज के ढांचे को कायम करना चाहा जिसके अन्दर हम बहुत कामयाब भी रहे और इसके लिए देश के अन्द इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण और राज्य व्यापार निगम की स्थापना के रूप में इस ओर कदम बढ़ाए।

हमारी सहकारी खेती के लिए जो प्रयास किया गया वह भी इसका एक प्रमाण है और इस सम्बन्धी जो राज्य की नीति है इसकी ओर हम काफी अग्रसर हुए हैं।

अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस ओर खींचूं कि योजना में मूल रूप से किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि अभी जनसंख्या की वृद्धि के बारे में मैंने कहा कि हमें जनसंख्या की वृद्धि का बराबर ध्यान रखना चाहिए, उसको कन्ट्रोल कर लें। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर और लक्ष्य करके अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, उसी प्रकार से हमारी योजना जब निर्मित हो तो उसके अन्दर जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के अन्दर जो बेरोजगारी बढ़

( डॉ० बहादुरसिंह )

रही है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है।

तीसरी चीज़ योजनाएं बनाते वक्त कृषि की है। कृषि अपने देश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, अपने देश की अर्थ व्यवस्था का मुख्य मूल रूप है। कृषि उत्पादन की ओर, एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन की ओर विशेष ध्यान रखना है। इसके ह्रास का मुख्य कारण कुछ अव्यवस्था और दूसरा, कुछ साधनों का अभाव है तथा इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोपों के कारण हम एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन के अन्दर लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ हमारी आबादी के बढ़ने के कारण भी है।

अब एक और जो चीज़ योजना बनाते वक्त हमारे ध्यान में होनी चाहिए वह है हमारे वित्तीय साधन ; इसके लिए हमें अपने आन्तरिक और बाह्य दोनों साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जहां तक आत्म-भरित, आत्मनिर्भरता का प्रश्न है उस व्यवस्था से ही विकास हो सकता है। जब हम स्वयं अपने अन्दर से सारे रिसोर्सेज़ पैदा करेंगे-तभी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जहां तक विदेशी अर्थ व्यवस्था का प्रश्न है और विदेशी जो सहायता है उसके ऊपर जो देश निर्भर रहता है, तो मेरी यह मान्यता है कि वह व्यवस्था पूर्ण विकास करने में पूर्ण न होगी।

दो-तीन कारणों से बाहर की सहायता मिला करती है। इनमें प्रमुख कारण राज-नैतिक होता है। अपनी जो विदेश नीति है उसके कारण हालांकि हमने जितनी सहायता प्राप्त की है वह राजनैतिक दबाव के अन्दर नहीं है। वह हमारा एक स्वतन्त्र लक्ष्य है। फिर भी जो विदेशी सहायता है उसका व्यय करने के लिए हमारे देश के अन्दर ऐसी स्थिति है जिसके अन्दर विदेशी प्रयोगात्मक विधि है वह अधिक खर्चीली पड़ती है।

घाटे की अर्थ व्यवस्था के फलस्वरूप भी राष्ट्र पर बड़ा असर पड़ता है। हम जब घाटे की अर्थ व्यवस्था को लेकर चलते हैं तो हमारे साधनों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में, मैं, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से श्री बी. के. मदान का कथन यहां पढ़ दूं तो असंगत नहीं होगा। उन्होंने बताया है:—

"विकास कार्य के लिए वित्त व्यवस्था करने में घाटे की अर्थ व्यवस्था का क्या क्रियात्मक तथा उचित भाग हो सकता है, यह एक अनिवार्य प्रश्न है। भिन्न भिन्न देशों की विभिन्न परिस्थितियों के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा इस प्रश्न के पृथक उत्तर दिये गये हैं। सभी परिस्थितियों के लिए कोई एक ही उत्तर सम्भव नहीं है। फिर भी भारतीय स्थिति के विभिन्न तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए, नीति निर्धारण में सहायता देने के लिये इस प्रश्न का उचित उत्तर देना आवश्यक है। मेरे अपने विचार में विकास कार्य में घाटे की अर्थ व्यवस्था का जो योग हो सकता है वह निम्न प्रकार है : घाटे की अर्थ व्यवस्था का, जिसका अर्थ संक्षेप में रिज़र्व बैंक के प्रति सरकार की ऋण ग्रस्तता ( इनडेटेडनैस ) में वृद्धि है, जो कि कर ऋणों ( टैक्सेशन लोन्स ) तथा आय की अन्य मदों से सार्वजनिक व्यय की अधिकता के रूपों में प्रकट होती है, यद्यपि इसमें कुछ मुद्रास्फीतिकारी तत्व

( डॉ० बहादुरसिंह )

सम्मिलित होते हैं, उसी सीमा तक सुरक्षित है जब तक इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति ( इनफ्लेशन ) तथा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न हो । अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थ-तन्त्र ( इकॉनोमी ) में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न कर देती है तथा हमारे साधन इसके कारण, अनुत्पादक कार्यों में प्रवृत्त होकर नियोजित विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। गतिपूर्ण तथा वास्तविक विकास के लिये सर्वोत्तम वातावरण मूल्यों की तुलनात्मक स्थिरता में निहित है। बढ़ते हुए तथा बहुत ऊंचे मूल्य साधनों के बुद्धिमत्ता-पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के बजाय उसके मार्ग में रुकावटें उपस्थित करते हैं । साधारण सी मुद्रास्फीति अवश्यम्भावी हो सकती है, किन्तु अधिक मात्रा में मुद्रास्फीति तो वित्तीय योजना का एक दम विरोधी सिद्धान्त है। यह उचित साधनों से वित्त उपलब्ध कर सकने में असफलता की सूचक है। अधिक मुद्रास्फीति से आर्थिक अस-मानताओं में वृद्धि होना निश्चित है और इस प्रकार यह समाजवादी ढांचे के समाज की मूल भावना के विपरीत है, जिसका कि एक अभिन्न तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अधिक आर्थिक समानता की स्थापना है । यह समाज के सबसे गरीब वर्ग को अत्यन्त गंभीर रूप में प्रभावित करता है । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं मुद्रास्फीति-कारी घाटे की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर रहने की अपेक्षा अधिक करारोपण, चाहे वह अनिवार्य वस्तुओं पर ही हो, के पक्ष में हूँ ।"

इस प्रकार से श्री बी. के. मदान जो कि एक अच्छे अर्थ विशेषज्ञ हैं उनका कथन है कि घाटे की अर्थ व्यवस्था अपने देश के अन्दर लागू करने से हमारे अर्थ-तन्त्र पर बुरा असर पड़ने वाला है। अपने घाटे की अर्थ व्यवस्था को दूर करने के लिए हमें चाहे अनिवार्य वस्तुओं पर करारोपण करना पड़े ।

उन योजनाओं के बारे में भी विभिन्न माननीय सदस्यों का जो मत है उस बारे में बाद में जाऊंगा । अब मैं दूसरी जो योजनाओं के बारे में जो बातें हैं कि इन पर हमें ध्यान रखना है वह बतलाऊंगा । सबसे पहले इनमें आत्म संयम की आवश्य-कता है। आत्म संयम के बारे में इतनी बातें हैं। एक तो देश के अन्दर अधिक उत्पादन की भावना होनी चाहिए । इसके लिए ज्ञान बढ़ाया जाय । खर्च कम और उत्पादन अधिक हो इस बात को लेकर चलना है। हमारे देश के राष्ट्रनायक पंडित नेहरू ने आत्म निर्भरता के बारे में जो कहा है उसके संबंध में मैं थोड़ा सा और निवेदन कर दूं। पंडित नेहरू ने कहा है :

"आयोजन का अर्थ है, यह निश्चित करना कि एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जहां पहुंच कर प्रक्रिया कम अधिक मात्रा में स्वचालित व आत्मपूरक हो जाती है, हमारे प्रारम्भिक पग क्या होने चाहिए ? यह सब करते समय हमें जन साधारण को ध्यान में रखना है। मेरा अभिप्राय यह है कि हम जो कुछ करते हैं उसके दृष्टिकोण से तथा जनता की भावनाओं के दृष्टिकोण से भी हमें उनकी सहायता करनी है । सहायता कहां ? वे कौन अनिवार्य बातें हैं जिनमें हम इन लोगों की सहायता कर सकते

( डॉ० बहादुरसिंह )

हैं ताकि उन्हें यह अनुभूति होने लगे कि उनकी स्थिति सुधर रही है तथा वे आगे बढ़ रहे हैं। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते तथा यह भी ध्यान रहे कि, हम भविष्य के लिए निर्माण करने के उद्देश्य से कठिनाइयों–आत्म संयम, आत्म त्याग, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं–के युग से गुजर रहे हैं। यह कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है कि हम एक ऐसे गरीब आदमी के पास जाकर, जिसे केवल उतने साधन उपलब्ध हैं जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए अनिवार्य हैं, उसे आत्म संयम का पाठ पढ़ायें। यह बहुत विचित्र लगता है। हमें उसे कुछ देना चाहिए। जब तक हम अन्य क्षेत्रों में उन्नति न करें उसे कुछ नहीं दे सकते। लेकिन कुछ तो देना ही है। वे कौनसी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो हमें उसे प्रदान करनी चाहिए ? यह आवश्यक है–मेरे विचार में इन वस्तुओं की गणना यथार्थ रूप में की जानी चाहिए, साधारण रूप में नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि हम ठीक ठीक बताएं कि अगले १२ महीनों में या अगले २४ महीनों में हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि तृतीय योजना के प्रारम्भ होने से काफी पहले हम यह निश्चित कर लें कि देश के लोगों की निम्नतम आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति तृतीय योजना मे किस सीमा तक होनी चाहिए। अतएव यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मेरा सुझाव यह है कि इन आवश्यक समस्याओं की आदर्शवादी व्याख्या पूर्ण करने के बाद तुरन्त ही आप क्रियात्मक समस्याओं पर आ जाय और यह निश्चित करें कि हमें निश्चित समय के अन्दर क्या करना है।"

तो इस प्रकार से हमारे देश के अन्दर हमें आत्म संयम की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी और आत्म संयम के लिए हमें थोड़े से त्याग और अनिवार्य सेवाओं की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान इसके बारे में खींचूं कि आत्म संयम के बारे में दो क्षेत्र हैं ; एक निजी क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अन्दर भी हमारे अनेक लोगों के अनेक मत हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि हमारे देश के अन्दर जो समाजवादी ढांचा है उसके बारे में भी जो उद्योगपति हैं उनको शंका है। वह उनको शंका की दृष्टि से देखते हैं। उनकी यह इच्छा है कि देश के अन्दर सरकारी क्षेत्र ५५ प्रतिशत हो और निजी क्षेत्र ४५ प्रतिशत हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो। लेकिन आज व्यवस्था संभवत: ६३ प्रतिशत और निजी क्षेत्र में ३७ प्रतिशत के करीब है। तो इस बात की जो उद्योगपतियों को शंका है उसके बारे में भी जो भी उनकी शंका है उसका निवारण करने की जरूरत है।

इसके बाद अब मैं आपका ध्यान जो योजनाओं के बारे में आवश्यकता होती है मानव पूंजी, ह्युमन केपिटल की ओर ले जाऊंगा। जनता में योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय चेतना की भी आवश्यकता पड़ती है। ह्युमन केपिटल की जरूरत के लिए हमें अपने तमाम जो साधन हैं उनका पूरा प्रयोग करना चाहिए और इसके प्रयत्न के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के नाते दोनों ही तरह के लोग चाहिए। एक तो इस प्रकार

( डॉ० बहादुरसिंह )

के लोग जो मैकेनाइज्ड हैं, खास करके हेवी इन्डस्ट्रीज़ और दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके लिये उनकी जरूरत है और दूसरे जो वैज्ञानिक लोग हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिये हमें ह्युमन केपिटल के लिये व्यवस्था करनी है।

तीसरी बात मैं जो केन्द्रीय योजना है उसके लिये अर्ज करूंगा। केन्द्र की १० हजार करोड़ की योजना है जिसके अन्तर्गत राजस्थान की योजना भी आती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के बारे में सबसे पहल है और उसमें जो कृषि के लिये व्यवस्था रखी है वह १,२०० करोड़ की है। इसमें सेवा सहकारी संस्थाएं, ग्राम सुधार आदि आइटम्स शामिल हैं। इसी प्रकार से सिंचाई की ४५० करोड़ की योजना है और पॉवर के लिये १,१५० करोड़ की योजना है। राजस्थान में भी हमने विद्युत के लिये काफी बड़ी योजना रखी है। इसी प्रकार से सेन्टर में उद्योग और खनिज के बारे में जो योजना है सबसे बड़ी योजना है जो ४ हजार करोड़ की है। इसमें हमारा लक्ष्य भी काफी बड़ा है और काफी साधन रखे गये हैं।

आगे यातायात और संचार के लिये भी १,१०० करोड़ रुपयों की योजना है जिसमें सड़क और पुल निर्माण की योजना भी शामिल है। जो सड़क की योजना है वह २० साल की योजना है और साथ में जिस प्रकार नागपुर प्लान बनाया गया है उसमें काफी सफलता मिली है।

इसके बाद समाज सेवा में १,४०० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसका अपने देश की जनता पर सीधा असर पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य, मकान निर्माण, शिक्षा, परिवार नियोजन, वैज्ञानिक तरीकों से गर्भ निरोधक व्यवस्था है। 'विविध' में ७०० करोड़ की योजना है वह भी सीधी असर रखती है।

अब मैं आपका ध्यान राजस्थान की योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान ने विद्युत में वृद्धि की है। वह काफी सहयोग पूर्ण है। इसमें आप कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं; यह सरकार के लिये चुनौती होगी। क्योंकि राजस्थान के विद्युत विभाग ने अब तक कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं की है, चाहे माननीय सदस्य कुछ भी कहें लेकिन मेरा निजी अनुभव है। मेरे यहां स्टेट के जमाने से पॉवर हाउस चलता था। उसकी कुछ स्थिति खराब हुई लेकिन उसमें राजस्थान सरकार सुधार नहीं कर सकी और दिन ब दिन उसकी स्थिति खराब होती गई। महाराजा से लेने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। जो पॉवर हाउस प्रोफिट में चलता था उसकी स्थिति किस प्रकार की है, यह देखने की बात है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है इसमें शक नहीं कि इसमें प्रगति हुई है। या तो यह महकमा मुख्य मंत्रीजी के पास है इसलिये तरक्की कर गया या विभाग के अधिकारी प्रगति करना चाहते हैं इसलिये प्रगति कर गया। इस विभाग ने तरक्की के कारण इस योजना में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

अब मैं स्वास्थ्य योजना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में स्वास्थ्य योजना में दो मेडीकल कॉलेज और

( डॉ० बहादुरसिंह )

एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की व्यवस्था की है। जहां पर दो मेडीकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की है मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की जो व्यवस्था की गई है उस पर मुझे आश्चर्य है। मैं मौजूदा दो आयुर्वेदिक कॉलेजेज़ को राजस्थान के लिये पर्याप्त नहीं मानता। शायद वे साधन संपन्न आयुर्वेदिक कॉलेजेज़ होंगी क्योंकि आज तक यहां पर शल्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से आप आयुर्वेद के नाम पर कह सकते हैं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में शल्य क्रिया को काफी बड़ा माना है। इसमें काफी अनुसंधान की आवश्यकता है। आज शस्त्र क्रिया विज्ञान भी आयुर्वेद का मुख्य अंग है लेकिन जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो वहां क्या आप आशा कर सकते हैं कि राजस्थान के विद्यार्थी दूसरे प्रान्तों में जहां सारे साधन उपलब्ध हैं उनके मुकाबले में ठहर सकते हैं ? फिर हम यह भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति स्वतंत्र होकर माइनर सर्जरी की व्यवस्था भी डिस्पेन्सरी में ही करें। यह कैसे हो सकता है ? राजस्थान के आयुर्वेदिक कॉलेज में शल्य क्रिया की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।

जहां तक एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की बात है मैं उसको न्यूनतम मानता हूं। राजस्थान के प्रत्येक डिविजन में एक कॉलेज की आवश्यकता है। इस योजना में ३ आयुर्वेदिक कॉलेज और खोलने की आवश्यकता थी, उसके बजाय एक ही रखा है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने कैन्सर हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्था की है, जहां पर ५० रोगी शय्या होंगी। इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ५० बैड्स में से १५ आयुर्वेद को देने चाहिये और ३५ मॉडर्न साइन्स के लिये रखिये क्योंकि कैन्सर में रिसर्च करना है। यहां इस प्रकार का हॉस्पिटल हो जिसमें दोनों ही पद्धतियों की व्यवस्था रखने की जरूरत पड़ेगी और दोनों पद्धतियों की व्यवस्था करने के लिये इस बात की जरूरत है कि इस पर अनुसंधान किया जावे। इस कैंसर हॉस्पिटल में ५० में से ३५ बैड्स मॉडर्न साइन्स के लिये रखे जायं और १५ बैड्स आयुर्वेदिक पद्धति के लिये रखे जायं।

अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, वैद्यों के वेतन स्तर के बारे में। इसमें विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। जहां वैद्यों के प्रोडक्शन की व्यवस्था का सवाल है आप ६८७ वैद्य बनाना चाहते हैं। यह अपर्याप्त है। इसके लिये भी आपको आगे जाकर व्यवस्था करनी होगी, जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डॉक्टरों के लिये करीब करीब ६५० डॉक्टरों की व्यवस्था है।

नर्सेज़, कम्पाउन्डर्स और उप–वैद्यों के लिये मेरा सुझाव है कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स के लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये एक ही तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिये और एक ही जगह ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां तक रोगी परिचर्यार्थ एक सी है, जहां तक दवा देने का सवाल है कंपाउन्डर्स और नर्सेज़ में फर्क

( डॉ० बहादुरसिंह )

पढ़ने वाला नहीं है। इसलिये इनके लिये समान स्तर के कोर्स की व्यवस्था करें, समान रूप से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इसके बाद, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां स्नातकोत्तर शिक्षण का प्रश्न है, यदि आपको वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति में वृद्धि करनी है तो हमें स्नातकोत्तर परीक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी चाहे मॉडर्न साइन्स में ही क्यों न हो। हमारे देश में इसका अभाव है। इसलिए हमें अपने यहां के विद्यार्थियों को विदेशों में भेजना पड़ता है। हमारे यहां जयपुर मेडीकल कॉलेज में एम० डी० और एम० एस० का कोर्स चालू किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं लेकिन उसके लिये थोड़ा फैलोशिप और दूसरा विशेष कर शिक्षण है, उसके लिये मॉडर्न साइन्स और आयुर्वेदिक दोनों में व्यवस्था करनी चाहिये।

उसी प्रकार राजस्थान के अन्दर भी जो आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित आयुर्वेदिक शिक्षा है उसके लिए भी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है....

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : Time is up, Sir.

**श्री सभापति** : He is about to finish.

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर-पश्चिम ) : He may be allowed, Sir.

**श्री सभापति** : Please finish within two minutes.

**डॉ० बहादुरसिंह** : थोड़ा रह जायेगा।

**श्री अर्जुनदास** : बाकी लिख कर भेज देना।

**डॉ० बहादुरसिंह** : थोड़ा रह जायेगा। पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

**श्री सभापति** : अच्छी बात है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के बारे में निवेदन कर रहा था! तो आयुर्वेद के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए क्यों जरूरत पड़ती है? इसके लिए माननीय सदस्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए, शिक्षण करने के लिए जब तक स्नातकोत्तर परीक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं होंगे तब तक यह शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था जब तक हमारे यहां नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि जो स्टफ निकलने-वाला है, वह अच्छा नहीं निकलेगा। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए जामनगर जैसी व्यवस्था आयुर्वेद के लिए करनी नहीं है।

एक बात, माननीय सभापतिजी, आपके द्वारा आयुर्वेद विभाग मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे मालूम हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, आयुर्वेद अनुसंधान बोर्ड बननेवाला है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद अनुसंधान बोर्ड कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति विशेष को प्लेस करना चाहते हैं, उनको भर्ती न

# Page No.112



( डॉ० बहादुरसिंह )

कर ली जाय, जैसी स्टेन्डर्ड बोर्ड ऑफ आयुर्वेद की है। इसकी जैसी व्यवस्था है उसी प्रकार हमारा जो आयुर्वेद का अनुसंधान बोर्ड बन रहा है उसमें न हो जाय।

दूसरी बात, हालांकि मुझे यह बात सदन में नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की अखिल भारतीय स्तर पर दलबन्दी है, राजस्थान का आयुर्वेद विभाग इस दलबन्दी में न चला जाय, इसके लिए सतर्कता की जरूरत पड़ेगी।

राजस्थान के बाहर के जो विद्वान् हैं, जिनको बोर्ड में लाना चाहते हैं उनको लाने के लिए विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि दिमाग किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में न चला जाय। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति :** Now we adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

[ तदुपरान्त सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर ३ मिनट पर बुधवार, दिनांक ७ सितम्बर, १९६० के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई। ]

———

# संक्षिप्त-विवरण

( मंगवार, ६ सितम्बर, १९६० )

| | स्कम्भ | | स्कम्भ |
|---|---|---|---|
| **तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** | २१७९ | के शिक्षकों का वेतन । | |
| हाई स्कूल, हायर सेकिन्डरी एवं इन्टरमीजियेट परीक्षाओं के परिणाम । | | श्री सारनेश्वरजी की जागीर ( सिरोही ) । | |
| जिला जालोर के पसायतेदार । | | मिडिल स्कूल भवन, बांसवाड़ा । | |
| बांसवाड़े के लघु उद्योग । | | यज्ञनारायण अस्पताल भवन, किशनगढ़ । | |
| तहसील भीलवाड़ा की भूमि का आवण्टन । | | जिला जोधपुर तथा नागोर में चद्दरों का कोटा । | |
| माध्यमिक शालाओं की अवकाश-तालिका । | | जसवन्त सराय, जोधपुर । | |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। | | श्री मांगीलाल 'मंगल' द्वारा राकेट छोड़ा जाना । | |
| सरोली-दूनी सड़क पर पुलों का निर्माण । | | हरिजन कुंआ, रूपनगढ़ ( अजमेर ) । | |
| उच्च माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम समिति । | | ग्राम भाप के नमक भूखण्डों का आवण्टन । | |
| धौलपुर-राजाखेड़ा सड़क । | | साहूकारी ऋण की ब्याज दर । | |
| शुभधरा तथा कुशलपुरा बस्तियां, शाहबाद ब्लॉक । | | राजकीय महा विद्यालय, सिरोही । | |
| तहसील सांगानेर (जयपुर) द्वारा दिया गया तकावी ऋण । | | लूनी नदी पर पुल निर्माण । | |
| प्राइमरी रिफ्युजीज़ स्कूल्स, जयपुर | | चुरू जिले की अध्यापिकाओं का फिक्सेशन । | |

फ्लो (Flow) एरिया की अस्थायी काश्त भूमि की दर।

सिवाना तथा पंचभद्रा ब्लॉक।

**अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६०–६१ (प्रथम खण्ड) के विवरण का उपस्थापन** २२४०

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप-मन्त्री वित्त, ने अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६०-६१ (प्रथम खण्ड) के विवरण का उपस्थापन किया।

**प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार** २२४०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किय:—

"राजस्थान राज्य की प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा से सम्बन्धित विभिन्न मदों के ज्ञापन, जिनकी प्रति दिनांक २ सितम्बर, १९६० को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर की गई बहस में निम्न-लिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)

(२) श्री जनार्दनराय नागर

(३) रावल श्री नरेन्द्रसिंह

(४) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(५) श्री लक्ष्मीचन्द

(६) डॉ० बहादुरसिंह

सदन की बैठक ५ बज कर ३ मिनट पर बुधवार, दिनांक ७ सितम्बर, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

# परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ का उत्तर देखिये )

| सन् | भूमिहीन जमींदार । | व्यापारी | । सरकारी कर्मचारी | राजनैतिक कार्यकर्त्ता | अन्य गैर काश्तकार |
|---|---|---|---|---|---|
| १९५७ | २५७५ ४ | ३४॥ ४ | . | . | १४६। |
| १९५८ | २०४९॥३ | ४६ | ६ | १८ | ३९९॥ |
| १९५९ | १२९०॥ | ५४ | . | . | १२०॥ ४ |

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३७ का उत्तर देखिये )

Copy of letter No. MDB/Genl/ (B) 14764/ Spl/ 59 dated 15-12-59 from the Addl. Director of Education, Rajasthan, Bikaner to the All Heads of Education Department.

Govt. are pleased to declare the following days to be Pubilc Holidays throghout Rajasthan State during the Calendar, 1960.

| S. N.<br>1 | Name of Holiday.<br>2 | Gregarian Calendar.<br>3 | Name of days.<br>4 | No of days.<br>5 | Remarks<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Year's Day | 1st January. | Friday. | 1 | |
| 2. | Republic Day | 26th January | Tuesday. | 1 | |
| 3. | Maha Shivratri | 25th February | Thursday | 1 | |
| 4. | Holi | 13 th March<br>14 th March | Saturday to<br>Monday. | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Nahan (Holi) | 25 th March | Friday | 1 | Announced by Collector, Kota as Local Holiday, Kota District. |
| 6. | Idul-Fitar | 26th March | Tuesday | 1 | |
| 7. | Ram Naumi | 5th April | Tuesday | 1 | |
| 8. | Mahavir Jayanti | 9th April | Saturday | 1 | |
| 9. | Pratap Jayanti | 8th May | Saturday | 1 | |
| 10. | Id-ul-Juha | 6th June | Monday | 1 | |
| 11. | Moharam | 5th July | Tuesday | 1 | |
| 12. | Raksha Bandhan | 7th August | Sunday | 1 | |
| 13. | Janmasbatmi | 14th August | Sunday | 1 | |
| 14. | Independence Day | 15th August | Monday | 1 | |
| 15. | Sthapan Navratra | 21st September | Wednesday | 1 | |

परिशिष्ट

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Desherah | 28th Sept. to 30th Sept. | Wednesday to Friday | 3 1 (1st Oct. 60 Saturday.) |
| | 1st October as local Holiday announced by Collector, Kota. | | | |
| 17. | Mahatma Gandhi's Birthday. | 2nd Oct. | Sunday | 1 |
| 18. | Dewali | 19th Oct. to 21st Oct. | Wednesday to Friday. | 3 |
| 19. | Birth Day of Guru Nanak Deo | 3rd November | Thrusday | 1 |
| 20. | Christmas, Day. | 25th December | Sunday | 1 |
| | Sectional Holidays | | | |
| I. | Guru Govind Singh's Birth Day. (for Sikhs only) | 5th Jan. | Tuesday | 1 |
| 2. | Guru Aujun Dev's Martyrdom (for Sikhs only) | 20th May. | Sunday | 1 |

परिशिष्ट

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Good Friday ( for Christians ) | 15th April. | Friday. | 1 |
| 4. | Samvatsai ( for Jain Employees ) | 27th August. | Saturday. | 1 |
| 5. | Anant Chaturdashi ( for Jains only ) | 4th Sept. | Sunday. | 1 |
| 6. | Guru Govind Singh's Birthday. ( for Sikh Emp. only ) | 24th December. | Saturday. | 1 |

Note:—All Sundays in the year are general holidays.

2. In the Kota District the day following Janmashtami will be observed as a holiday instead of Janmashtami itself.

3. The holidays on account of Id-Ul-zauha, Id-ul-fitar and Moharram will be subject to the appearance of the moon.

## शिक्षा विभाग, राजस्थान
## विभाग द्वारा स्वीकृत अवकाश

| क्र० सं० | अवकाश का नाम | तिथि व दिनांक | | दिवस | सं० |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | | ४ | ५ |
| | | रविवारों के अतिरिक्त अवकाश संस्था उपभोग करेगी। | | | |
| १. | मोहर्रम | आषाढ़ १५,१८८२ | ५ जुलाई, १९६० | मंगलवार | १ |
| २. | रक्षाबन्धन | श्रावण १६,१८८२ | ७ अगस्त, १९६० | रविवार | १ |
| ३. | जन्माष्टमी | ,, २३,१८८२ | १४ अगस्त, १९६० | रविवार | १ |
| ४. | स्वतन्त्रता दिवस | ,, २४,१८८२ | २५ अगस्त, १९६० | सोमवार | १ |
| ५. | दशहरा | आश्विन ६,१८८२ | २८ सितम्बर, १९६० | बुधवार | ३ |
| | | ,, ७,१८८२ | २९ सितम्बर, १९६० | गुरुवार | |
| | | ,, ८,१८८२ | ३० सितम्बर, १९६० | शुक्रवार | |
| ६. | महात्मा गांधी जन्म दिवस | ,, १०,१८८२ | २ अक्टूबर, १९६० | रविवार | १ |

| १ | २ | ३ | | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|
| ७. | दीपावली | आश्विन २७,१८८२<br>२८,१८८२<br>२९,१८८२ | १९ अक्टूबर,१९६०<br>२० अक्टूबर,१९६०<br>२१ अक्टूबर,१९६० | बुधवार<br>गुरुवार<br>शुक्रवार | ३ |
| ८. | गुरु नानक जन्म दिवस | कार्तिक १२,१८८२ | ३ नवम्बर,१९६० | गुरुवार | १ |
| ९. | गुरुगोविन्दसिंह | | २४ दिसम्बर,१९६० | शनिवार | १ |
| १०. | बड़ा दिन | पौष ४,१८८२ | २५ दिसम्बर,१९६० | रविवार | १ |
| ११. | मकर संक्रान्ति | | १४ जनवरी,१९६१ | शनिवार | १ |
| १२. | गणतन्त्र दिवस | | २६ जनवरी,१९६१ | गुरुवार | १ |
| १३. | बसंत पंचमी | आषाढ़ १४,१८८३ | २१ जनवरी,१९६१ | शनिवार | १ |
| १४. | महा शिवरात्रि | श्रावण १६,१८८२ | १३ फरवरी,१९६१ | सोमवार | १ |
| १५. | सूर्य ग्रहण दिवस | श्रावण २३,१८८२ | १५ फरवरी,१९६१ | बुधवार | १ |

परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|---|
| १६. | होली | फाल्गुन | ११,१८८२. २ मार्च, १९६१ | गुरुवार | ३ |
| | | ,, | १२,१८८२, ३ मार्च, १९६१ | शुक्रवार | |
| | | ,, | १३,१८८२, ४ मार्च, १९६१ | शनिवार | |
| १७. | ईदूल फितर | ,, | २८,१८८२, १९ मार्च, १९६१ | रविवार | १ |
| १८. | राम नवमी | चैत्र | १,१८८३, २५ मार्च, १९६१ | शनिवार | १ |
| १९. | महावीर जयन्ती | ,, | ६,१८८३, ३० मार्च, १९६१ | गुरुवार | १ |

# परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ का उत्तर देखिये )

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Education (B) Department

NOTIFICATION

No. F. 20 (4) Edu/B/59 Dated, the 4th September, 1959.

Government is pleased to appoint a Committee consisting of the following to review the working of the system of Higher Secondary Education in the State and to recommend measures with a view to make it possible to achieve such Improved Standards of performance as were envisaged at the time of formulation and introduction of this new pattern of Secondary Education. The Committee shall submit its report to the Government within 3months from the date of the notification:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri G. C. Chatterji, Chairman, Board of Secondary Education, Rajasthan. | Chairman |
| 2. | Shri Dr. D. S. Kothari, Professor Physics, Delhi University. | Member |
| 3. | Shri S. S. Saxena, Director of Education Rajasthan, Bikaner. | ,, |
| 4. | Shri K.L. Bordia, Director Rural Institute Vidya Bhawan, Udaipur. | ,, |
| 5. | Shri D. Vable, Principal, D. A. V. College, Ajmer. | ,, |
| 6. | Shri J. S. Mehta, Additional Director of Education, Rajasthan, Bikaner. (Incharge of Secondary Education) | Secretary |
| 7. | One Representative of the Ministry of Education. | Member |
| | Shri R. K. Kapoor, Deputy Education Advisor, Govt. of India, Ministry of Education. | ,, |

| | |
|---|---|
| 8. & 9. Two Representatives from the Delhi Administration with experience of Higher Secondary Education. | Member |
| 1. Shri N. B. Gupta, Asstt. Director of Education, Delhi Administration, Delhi. | " |
| 2. Shri S. L. Bajaj, Secretary, Board of Secondary Education, Delhi, | " |

The Committee may also co-opt two more members:—

1. Shri K. N. Bhargava, Principal, Sadul Public School, Bikaner.
2. Shri T. K. Dandia, Head master, Maharaja's M. P. H. S. School, Jaipur.

The terms of reference of the Committee shall be:—

1. To examine the causes for the low standard of attainment of Higher Secondary students and the heavy percentage of failures at the Higher Secondary Examination.

2. To examine in detail the curricular of pre-higher Secondary and Higher Secondary courses and to make specific recommendations towards its simplification, rationalisation and co-ordination, with different stages of Education vis. Primary, Middle and Higher Seccondary.

3. To make specific recommendations towards improving the standards of teaching and performance by students in the Middle and the Higher Secondary Classes.

4. To consider other relevant aspects of the problem and to make recommendations with a view to attain desired standard in the filed of Higher Secondary Education.

V. D. Sharma J. A. S.
Secy. to the Government,

———

# COPY OF THE INTERIUM RECOMMENDA TION

## Government of Rajasthan

## IMPROVEMENT & CO-ORDINATION OF STANDARD COMMITTEE

In the Questionnaire issued by the Committe in the purt dealing with Examination the following question had been asked :—

"Is examination held at the end of the Class XI after three years' on the whole course of the Higher Seconary Schcol, Strenuous and Cumbersome ?"

To this question the whole Memoranda received as well as the witnesses examined have stated that one examination at the end of Class XI is both strenuous and cumbersome. It imposes a very heavy burden on the pupil at this state of his mental development. The tendency is to slacken during the first two yesrs and then make a concentrated effort near the close of the examination to memorise answers to expected questions. This is not only unsaund from the point of view of the Education of the pupil but is also one of the main reasons why failures in the Higher Secondary Examination are so numerous.

After giving full thought to the matter the Committee unanimously recommends that the Higher Secondary Examination be staggered to be held in two parts, one at the end of the class X candidates should be examined in the following subjects :-

1. Social Studies
2. General Science
3. Craft
4. Elementary Mathematics.

Examination in Compulsory English, Compulsory Hindi and three elective subjects should be held at the end of the class XI.

In support of this recommendation, the Committee desires to point out that the original proposal of the Secondary Commission with regard to these subjects was that they should be studied for a period of two years only. If it further pointed out, this practice is being followed by the Board of Secondary Education Delhi as well as in Madhya Pradesh, West Bengal, Bihar etc.

In fact in some of the States the examination at the end of the Class X is the Home Examination. Our Committee does not recommend this but desires that the examination should be public examination conducted by the Board.

The Committee is of the opinion that the syllabus at present prescribed in Social Studies and General Science is too abstract, vague and unnecessarily heavy. The Committee recommends that early revision of the syllabus in these subjects may be undertaken so as to make it more suitable for this state of the educational process. In this connection also the Committee would like to draw the attention of the Government as well as of the Board of Secondary Education that the Secondary Commission had recommended the study of both Social Studies and General Science as a General Course and not involving any detailed technical study of the subject matter of Physics, Chemistry, Biology, History, Economics, Civics etc.

Sd/ J. S. Mehta
Secretary
2nd. May, 1960.

Sd/ G. C. Chatterji
Chairman

Copy of letter No. D. 5647/F. I (6) Edu/B/60 dated 22-5-60 from the Secretary to the Government, Education Deptt., Rajasthan, Jaipur to the Secretary, Board of Secondary Education, Rajasthan, Jaipur and endored to the Director of Primary and Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.

I am directed to state that the Government have been pleased to accept the following recommendations of the Improvement and Co-ordination of Standards Committee :—

The Higher Secondary Examination be staggered to be held in two parts, one at the end of class X and other at the end of XI. At the end of the class X candidate should be examined in the following subjects:-

1. Social Studies.
2. General Science.
3. Craft.
4. Elementary Mathematics.

Examination in Compulsory English, Compulsory Hindi and three elective subiects should be held at the end of class IX.

The syllabus at present prescribed in Social Studies and General Science is too abstract, vague and unnecessrily heavy, and as such it should be revised in these subjects so as to make it more suitable for this state of educational process.

The study of both Social Studies and General Science as a general course be made not involving any detailed technical study of the subject matter of Phyiscs, Chemistry, Biology, History, Economics, Civic etc.

You are requested to kindly to take steps to implement the above recommendations from the academic session 1960-61.

———

## परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ का उत्तर देखिये )

### समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सहायता की सूची

| क्रमांक | पद | सन् | परिवार संख्या | दर प्रति परिवार |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. | मकान सहायता | ५५-५६ | १३२ | ३५०) रु० |
| २. | मकान सहायता | ५७-५८ | ५० | ३५०) रु० |
| ३. | मकान सहायता | ५८-५९ | १३२ | ३००) रु० अतिरिक्त सहायता |
| ४. | मकान सहायता | ,, | ५० | १५०) रु० अतिरिक्त सहायता |
| ५. | जमीन सफाई हेतु | ,, | १३२ | १००) रु० |
| ६. | जमीन सफाई हेतु | ,, | ५० | १००) रु० |
| ७. | सहकारी शेयर खरीदने हेतु | ,, | ५० | ५०) रु० |
| ८. | पचायत घर हेतु | ५७-५८ | | ६,०००) रु० |
| ९. | रोड एवं पार्क बनाने हेतु | ५७-५८ | | ५,०००) रु० |
| १०. | पीने के पानी के कुओं हेतु। | ५५-५६ | | २,०००) रु० |
| ११. | पीने के पानी के कुओं हेतु। | ५७-५८ | | २,०००) रु० |

———

# परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या-३५६ का उत्तर देखिये )

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT
OFFICE MEMORANDUM

No. F.11 (13) F. 11/54 Dated, Jaipur, the 13th. May, 1954

SUBJECT :—Rajasthan Civil Services (Unified of Pay Scales Rules.)

There is no specific provision in the Rajasthan Civil Services (Unification of Pay Scales) Rules regarding the manner in which pay in the Unified Scales will be fixed in respect of persons not possessing previous pay as defined in rule 2 (g) of these rules on their permanent fixation against a post in the integrated set up. The position is that fixation of such persons has ordinarily to be at the minimum of the prescribed scale unless Government by a general or special order permits fixation at any higher stage in the new scale.

Since doubts have been expressed in this regard an amendment to be rules clarifying this position will be issued.

Government have considered the question, however, and have decided that while no protection is due in respect of pay previously drawn in temporary appointments by persons who are not pre-covenent entrants as defined in rule on their fixation against permanent posts as a result of integration some measures of relief in the form of advance increments would be reasonable in order to mitigate the hardship which would be caused to individuals concerned if they are brought down to the minimum of the new scale without any consideration of their previous pay, service etc.

It has been decided, therefore, that fixation in such cases may be :—

1. at a stage in the prescribed scale equal to the basic pay last drawn by the individual concerned in a temporary appointment excluding higher pay drawn in any temporary officiating appointment while holding temporary appointment or if there is not such stage, at the next lower stage plus personal pay equal to the difference, or

2. the minimum of the prescribed scale plus one increment for each year's complete service on basic pay equal to or higher than such minimum, whichever of (1) and (2) may be the lower.

Fixation of pay in the prescribed scale under the Rajasthan Civil Services ( Unification of Pay Scales ) Rules in the case of temporary employees absorbed in the integrated set up on a permanent basis may be regulated in accordance with this memorandum.

Approximate amendment to the Unification of Pay Scales Rules will issue in due course.

Sd/- G. S. Purohit,
Finance Secretary to the Government.

## परिशिष्ट

Copy of order No. D. 2180/F. 17 (38) Edu/I/53 dated 15.2.56 from the Education Secretary, Government of Rajasthan to the Director of Education, Rajasthan, Bikaner.

His Highness the Rajpramukh has been pleased to approve of the following principles in regard to the fixation of the displaced teachers of Refugee Schools taken over by the Education Department from the Relief & Rehabilitation Department subject to the conditions that there will be no protection of pay beyond the maximum of the Unified Pay Scales prescribed for the post:—

1. The teachers be fitted into the Rajasthan Pay Scales according to qualifications for Primary Schools teachers.
2. The appointments made after 1st July, 1952 will be on the minimum of the Rajasthan Scales.
3. Premerger employees who were appointed temporarily before merger but were not confirmed as a result of merger be confirmed in accordance with the Finance Department's Order No. F. 18 (22) F. II/53 dated 5.1.50 if they fulfill all the conditions laid down in that order.
4. Overage teachers be exempted form the age limit regulations.
5. Increments if any due to them for the period they were under R. &. R. Department be given.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION,
RAJASTHAN. BIKANER.

No. HDB/EDB/58/57/7 Dated 7-1-57

To

The Dy. Director of Education
Jaipur/Jodhpur/Udaipur.

SUBJECT :--Fixation of Refugee teachers.

For purpose of fixation of pay of Refugee teachers in the Unified Pay Scales, the following equation of the Examinations in Sind with those recognised in Rajasthan is approved.

| S. N. | Examination prevalent in Sind | Equivalent Examination in Rajasthan | Grade in unified Pay Scales of Rajasthan |
|---|---|---|---|
| 1. | Vernacular final | Untrained Middle | 35-1-40 |
| 2. | Vernacular final plus one year's training or 10 years' experience | Trained Middle with one years' training OR untrained Middle with 10 years' experience | 40-1-45-EB-2-55 |
| 3. | Vernacular final plus 2 years' training plus 7 years' experience, or vernacular final with 3 years' training. | Trained middle with two years' training | 40-1-45-EB-2-55-2-65 |

Since the Refugee Schools have been functioning only as Primary Schools the above grades have been prescribed for teachers in Primary Schools. Therefore, all the refugee teachers are to be fixed in the Unified Pay Scales mentioned above according to their qualification.

Sd/-
F. Director of Education
Rajasthan, Bikaner.

## परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिए )

| कक्षा | मार्च, ६० | जुलाई, ६० | २३ अगस्त, ६० | |
|---|---|---|---|---|
| ८ बी० ए | २५ | ३५ | २७ | |
| ८ बी० बी | २७ | ३४ | ३६ | |
| ८ बी० सी | २५ | २६ | ४० | |
| ७ बी० ए | २७ | ४३ | ४३ | |
| ७ बी० बी | ३० | ४२ | ३१ | |
| ७ बी० सी | ३२ | ४२ | ४२ | |
| ६ टी, | — | — | — | कुल १५१ |
| योग | १६६ | २२५ | २१६+१५१=७६१ कुल योग । | |

---

## परिशिष्ट ७

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६२ का उत्तर देखिये )

### जसवन्त सराय, जोधपुर के किरायेदारान की सूची

| क्रम संख्या<br>१ | मकान नम्बर<br>२ | नाम किरायेदार<br>३ | किराया की रेट<br>४ |
|---|---|---|---|
| १. | १, २, ३ | श्री जयनारायण राठी | ३३.६२ |
| २. | ४ | ,, नाथू नाई | ३.६२ |
| ३. | ५ | ,, वलभदास | ३.६२ |
| ४. | ६ | ,, ब्रधिनाराम | ४.६२ |
| ५. | ७ | ,, शंकरराव | ११.० |
| ६. | ८ | ,, भंवरसिंह | ३.६२ |
| ७. | ९ | ,, नारायण | १५.० |
| ८. | १०,११,१२ | ,, मोहनलाल | ३३.६२ |
| ९. | १३ | ,, बनोंसिंह | ३.६२ |
| १०. | १४ | ,, छगनलाल | ३.६२ |
| ११. | १५ | ,, जोगीदास | ३.६२ |
| १२. | १६ | ,, भूली जोजे प्रभु | १०.० |
| १३. | १७ | ,, खेमचन्द | ३.६२ |
| १४. | १८ | ,, बुक व चाय कम्पनी | ४.८? |
| १५. | १९ | ,, देवदत्त | ९.२५ |
| १६. | १९।१ | ,, बनोसिंह | २.३१ |
| १७. | १९।३ | ,, अब्दुल्ला | २.३१ |
| १८. | २० | ,, जेठमल बोहरा | ९.७५ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १६. | २१ | श्री भास्कर गोरे | ६.७५ |
| २०. | २२ | ,, दलीपसिंह | १०.६२ |
| २१. | २३ | ,, मित्र प्रकास | ६.८७ |
| २२. | २४ | ,, सत्यापाल | ६.० |
| २३. | २५ | ,, मामजीमल | १५.० |
| २४. | २६ | ,, किशन कल्ला | १४.३७ |
| २५. | २७ | ,, मुकट विहारी | ११.५० |
| २६. | २८-२६ | ,, प्यारे मोहन | १४.३७ |
| २७. | ३१ | ,, मनमोहननाथ कक्कड़ | १०.३१ |
| २८. | ३२ | ,, राज राणी कक्कढ़ | १०.३१ |
| २६. | ३३ | ,, बैजानाथ कक्कड | १६.६ |
| ३०. | ३४ | ,, पोकरराम | ६.० |
| ३१. | ३५ | ,, भीमसेन | ३.६२ |
| ३२. | ३६ | ,, अब्दूल सलाम | ३.६२ |
| ३३. | ३७ | ,, म्युनिशिपल ओ० | ३.६२ |
| ३४. | ३८-३६ | ,, बिशननाथ | ७.२५ |
| ३५. | ४० | ,, इनदरलाल | ३.६२ |
| ३६. | ४१ | ,, वैध प्रकाश | ३.६२ |
| ३७. | ४२ | ,, राममोहन | ३.६२ |
| ३८. | ४३ | ,, देवीलाल | ४.५१ |
| ३६. | ४४ | ,, ईश्वरचन्द गोसल | ३.६२ |
| ४०. | ४५ | ,, सीताराम | ८.० |
| ४१. | ४६ | ,, माधवप्रसाद | २.३७ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ४२. | ४७ | श्री जीवराजासिंह | ६.८७ |
| ४३. | ४८ | ,, शमसामूल हक्क | ६.८७ |
| ४४. | ४६ | ,, मदनलाल पीरायत | १०.३१ |
| ४५. | ५० | ,, बिहारीलाल | १०.३१ |
| ४६. | ५१ | ,, आसनमल वाविनी | १०.३१ |
| ४७. | ५२ | ,, जानकी बाई | १०.३१ |
| ४८. | ५३ | ,, कन्यालाल | १०.५० |
| ४६. | ५४ | ,, चौथमल | ११.५० |
| ५०. | ५५ | ,, पतीतपावन पाइन | १०.३१ |
| ५१. | ५६ | ,, लाला कपूरचन्द | १०.३१ |
| ५२. | ५७ | ,, उदियानन्द | १०.३१ |
| ५३. | ५८ | ,, नित्यानन्द | ११.५० |
| ५४. | ५६ | ,, ओमप्रकाश | ६.८७ |
| ५५. | ६० | ,, राधाकृष्ण रस्तोगी | २०.० |
| ५६. | ६१ | ,, पी. एन. विनजानी | १२.५६ |
| ५७. | ६२ | ,, शनतूराम | १२.५६ |
| ५८. | ६३ | ,, श्री नारायण विनायक | १२.५६ |
| ५६. | ६४ | ,, विनायक हरि फाटक | १०.३१ |
| ६०. | ६५ | ,, मोहनलाल | १२.५६ |
| ६१. | ६६-६७ | ,, ईश्वरचन्द गोसल | १४.३७ |
| ६२. | ६८-६६ | ,, मदनलाल कावरा | १४.३७ |
| ६३. | ७० | ,, जयकुमार | ६.०० |
| ६४. | ७१ | ,, रूपलाल | ६.०० |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६५. | ७२ | श्री भगसिंह हरीसिंह | ६.८७ |
| ६६. | ७२।१ | ,, भगसिंह हरीसिंह | ५.०० |
| ६७. | ७३ | ,, लालाहरप्रशाद | ६.८७ |
| ६८. | ७४ | ,, लाला जगन्नाथ | ६.८७ |
| ६९. | ७५ | श्री शामगिरी | ६.८७ |
| ७०. | ७६ | ,, पोकरदास | १०.०० |
| ७१. | ७७ | ,, शिवकिशन | ७.२५ |
| ७२. | ७८ | ,, माणू धोबी | ७.२५ |
| ७३. | ७९ | श्रीमती शान्तीदेवी | ७.२५ |
| ७४. | ८० | श्री भोमा नाई | १७.०० |
| ७५. | ८१ | ,, आसूलाल | ७.२५ |
| ७६. | ८२ | ,, डमराम | ७.२५ |
| ७७. | ८३ | ,, चन्दू धोबी | ७.२५ |
| ७८. | ८४ | ,, किस्तूरचन्द | ७.२५ |
| ७९. | ८५ | ,, सोहनसिंह | ७.२५ |
| ८०. | ८६ | ,, पोकरलाल | ७.२५ |
| ८१. | ८७ | ,, हेमराज | ७.५२ |
| ८२. | ८८ | ,, बाबूलाल | ७.२५ |
| ८३. | ८९ | ,, मानकचन्द | ७.२५ |
| ८४. | ९० | ,, राजूनाई | ७.२५ |
| ८५. | ९१ | ,, भोलाराम | ७.२५ |
| ८६. | ९२ | ,, वलीराम | ७.२५ |
| ८७. | ९३ | ,, दाउलाल | ७.२५ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ८८. | ९४ | श्री चुनीलाल | १२.०० |
| ८९. | ९५ | ,, अम्बालाल | १.८५ |
| ९०. | ९६ | ,, मंगाराम | १.७५ |
| ९१. | ९७ | डॉ० बख्तारमल | २८.७५ |
| ९२. | ९८ | श्री माहारतन | २५.२५ |
| ९३. | ९९ | ,, देवनारायण व्यास | १९.५० |
| ९४. | १०० | ,, रामाकृष्ण आचार्य | २५.०० |
| ९५. | १०१ | ,, घमन्डीप्रसाद | ३४.५० |
| ९६. | १०२ | ,, नारायणप्रसाद | २.८७ |
| ९७. | १०३ | श्रीमती कलावती | ३.८७ |
| ९८. | १०४ | श्री रामचर्ण | २.३७ |
| ९९. | १०५ | ,, सालीगराम | २.८७ |
| १००. | १०६ | ,, लक्ष्मीनारायण | २.८७ |
| १०१. | १०७,१०८,१०९ | ,, पन्नालाल | ८.६७ |
| १०२. | १११ | ,, द्वारादास | १९.५० |
| १०३. | ११२ | ,, पी० पी० शाहनी | २३.०० |
| १०४. | ११३ | ,, मदनलाल व्यास | १९.५० |
| १०५. | ११४ | ,, रमनलाल भड | १९.५० |
| १०६. | ११५ | ,, मिसरीलाल | १२.६२ |
| १०७. | ११६,२१ | सराय में कमरे जो रोजाना-किराये पर हैं। | |
| १०८. | १२२ | श्री लालाचर्णदास | १०.३१ |
| १०९. | १२३ | ,, अन्तराम कारखानी | १०.३१ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ११०. | १२४ | श्री नानकचन्द | १०.३१ |
| १११. | १२५ | ,, बुलाकीलाल | १५.०० |
| ११२. | १२७,१२८ | ,, गिरधारीलाल | २४.१२ |
| ११३. | १२६ | ,, गणेशीलाल | ११.५० |
| ११४. | १३० | ,, बादललाल | ३.६२ |
| ११५. | १२६ | ,, राजेश्वरकुमार | १०.३१ |
| ११६. | १३१ | ,, हरिमोहन | ४.८१ |
| ११७. | १३२ | ,, कैलाशपुरी | ८.०० |
| ११८. | १३३ | ,, रतनलाल | ३.६२ |
| ११६. | १३४ | ,, श्रीधर | ३.६२ |
| १२०. | १३५ | लोवर प्राईमारी स्कूल | ३.६२ |
| १२१. | १३६ | श्री किशोरीलाल | ३.६२ |
| १२२. | १३७ | ,, नन्दलाल | ३.६२ |
| १२३. | १३८ | ,, उमेदानन्द | ६.८७ |
| १२४. | १३६,१-२ | ,, मंगवलाल कुमट | ४.६२ |
| १२५. | १३६४-३ | ,, रमनलाल | ४.६२ |
| १२६. | १४०-१ | ,, देवनारायण | २.६२ |
| १२७. | १४०-२ | डॉ० बख्तावरमल | १.१६ |
| १२८. | १४०-३ | श्री सोहन पवार | ६.०० |
| १२६. | १४०-४ | ,, तुलछीराम | २.०० |
| १३० | १४०-५ | ,, प्रेमराज | १५.०० |
| १३१. | १४०-६ | मोटर एक्सचेंज कम्पनी | १०.०० |
| १३२. | १४०-७ | श्री सीताराम | ३०.०० |

# परिशिष्ट ८

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७० का उत्तर देखिये )

LIST OF THE PERSONS WHO WERE ALLOTTED SALT PLOTS IN BAP RIN AREA BY LOTTARY

| S. N. | Name of the allottee. | No. of the plot allotted. | Remarks. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Shri Nathumal Gordhandass | 177 | |
| 2. | ,, Amritlal Badanlal | 332 | |
| 3. | ,. Champalal Bhagwandan | 172 | |
| 4. | ,, Manmal Laxmandas | 237-282 | |
| 5. | ,, Jiwansingh Mangla Singh | 313 | |
| 6. | ,, Ramrakh Shivraj Phalodi | 297 | |
| 7. | ,, Pramraj Bastiram Gehlot | 278 | |
| 8. | ,, Natham Maderna Chandi | 176 | |
| 9. | ,, Sultansingh Hanwat Singh | 108 | |
| 10. | ,, Parna Lal Panchulal | 192 | |
| 11. | ,. Kishan s/o Punam chand | 114 | |
| 12. | ,, Chainsukh s/o Paludan | 378 | |
| 13. | ,, Bheru Lal Ramgopal Vyas | 253 | |
| 14. | •. Vasudev Pannalal | 198 | |
| 15. | ., Amritlal Manaklal | 330 | |
| 16. | ,, Kasturchand lokaram | 188 | |
| 17. | ., Gulab Chand labhchand | 174 | |
| 18. | ,, Ramlal Redhakrishan | 131 | |
| 19. | ,, Ram Lal Radhakrishana | 322 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | Shri Bhikamchand Pannalal | 142 | |
| 21. | ,, Annandraj suganmal | 274 | |
| 22. | ,, Gomesh Brijratan | •285 | |
| 23. | ,, Himatram Sura Jkaran | 295 | |
| 24. | ,, Mohanlal Bhojraj | 319 | |
| 25. | ,, Chhoturam Khara | 324-284 | |
| 26. | ,, Lalchand Bheraram | 272 | |
| 27. | ,, Ramkrishan Madan Lal | 195 | |
| 28. | ,, Mool Singh Kansingh | 337 | |
| 29. | ,, Shivratan Jiween lal | 194 | |
| 30. | ,, Anop Singh Bhaira Singh | 110 | |
| 31. | ,, Aladin Bhojoas | 265 | |
| 32. | ,, Stiaram Deepchand | 331 | |
| 33. | ,, Labhchand Surajkaran | 245 | |
| 34. | ,, Surajkaran Karnidan | 225 | |
| 35. | ,, Lalu Hiralal | 327 | |
| 36. | ,, Jankilal Parbhu Lal | 55 | |
| 37. | ,, Ashkaran Partap Singh | 329 | |
| 38. | ,, Kaluram Kundanmal | 137 | |
| 39. | ,, Abdul Rahim Chanduchand | 128-129-184 | |
| 40. | ,, Ballabhdas Rajaram | 254 | |
| 41. | ,, Praladhram Hameerram | 139 | |
| 42. | ,, Ramniranjan Shankarlal | 46 | |
| 43. | ,, Nezera s/o Ibrahimkhan | 77 | |
| 44. | ,, Hari Singh Megh Singh | 130 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 45. | Shri Bulakidas Madangopal | 238 | |
| 46. | ,, Srikrishan Tansukhadas | 268 | |
| 47. | ,, Gopal Lal Issarlal | 113 (113) | |
| 48. | ,, Indarmal Badrinarain | 328 | |
| 49. | ,, Misrilal Pannalal | 181 | |
| 50. | ,, Shivraj Ratan Singh | 189 | |
| 51. | ,, Prahladrai Dhokalram | 231 | |
| 52. | ,, Manu s/o Nena Megwar | 86 | |
| 53. | ,, Mohan Lal Tulshidas | 180 | |
| 54. | Shrimati Tulshriam Damodardas | 315 | |
| 55. | ,, Kaserdevi Tulshidas | 300 | |
| 56. | Shri Chandchand Mohamedji | 193 | |
| 57. | ,, Shivkishan Pransukh | 325 | |
| 58. | ,, Mishralal Tulshiram Soni | 118 | |
| 59. | ,, Bachraj Shivdutt | 253 | |
| 60. | ,, Shivraj Srikrishan | 229 | |
| 61. | ,, Punamdas Budharam | 90 | |
| 62. | ,, Rahimkhan Sanochhan | 83 | |
| 63. | ,, Ranulal Dhanraj | 406 | |
| 64. | ,, Gopikrishan Jagnnath | 269 | |
| 65. | ,, Pransukh Amritlal | 410 | |
| 66. | Shrimati Ramkanwar w/o Jawanmal | 48 | |
| 67. | Shri Baghduram s/o Dhokal Ram | 408 | |
| 68. | ,, Dungardas s/o Bakhoordan | 275 | |
| 69. | ,, Vasudev s/o Meghraj | 49-50-126 | |

# Page No.143



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 70. | Shri Man Mal Shivkaran | 240 | |
| 71. | ,, Shavisingh Mohan dan | 141 | |
| 72. | ,, Ushmankhan Labulchand | 250 | |
| 73. | ,, Moolchand Nathmal | 138 | |
| 74. | ,, Kedar lal Manohar lal | 277 | |
| 75. | ,, Taru khan s/o Magh Khan | 296 | |
| 76. | ,, Bhagi Rath Amba lal | 235 | |
| 77. | ,,Kheevraj s/o Hazari lal rathi | 279 | |
| 78. | ,, Akaramar Khan | 270 | |
| 79. | ,, Magh Raj Tulsi Dass | 62 | |
| 80. | ,,Ramkishan Dass Bhikam chand | 51 | |
| 81. | ,, Abdul Havid Hazi Khan | 124 | |
| 82. | ,, Shivratan Ganga Bishan | 122 | |
| 83. | ,, Shiv Pratap Dhan Raj | 281 | |
| 84. | ,, Kherop | 175 | |
| 85. | ,, Banshi Lal Chand Mal | 320 | |
| 86. | ,, Bal Kishan Chagan Lal | 82 | |
| 87. | ,, Champa lal Vishan Lal | 283 | |
| 88. | ,, Ratan Lal Ram Ratan | 405 | |
| 89. | ,, Abdul Khan Hussain Khan | 64 | |
| 90. | ,, Khata Ram Sukha Ram | 276 | |
| 91. | ,, Prem Sunder Mir Sundar | 246 | |
| 92. | ,, Ghampa lal Gordhan lal | 316 | |
| 93. | ,, Ghusilal Jai lal | 101 | |
| 94. | ,, Mandar Khan Bhairkhan | 252 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 95. | Smt. Bach Kanwar w/o Radha Kishan | 288 | |
| 96. | Shri Ganesh Ram Kishori Lal | 267 | |
| 97. | „ Amar chand Alseedan | 400 & 401 | |
| 98. | „ Gangavishan Hem Raj | 81 | |
| 99. | „ Mool Lal Megh Raj | 271 | |
| 100. | „ Hor Singh Raghunath Singh | 508-9-10 | |
| 101. | „ Jeth Ram Lal Chand | 292 | |
| 102. | „ Shiv Narain Lal Chand | 121 | |
| 103. | „ Kana Ladu | 314 | |
| 104. | „ Achla Ram Pabudan | 115 | |
| 105. | „ Ram Lal Har Dass | 310 | |
| 106. | Smt. Hari Bai w/o Shankar lal | 242 | |
| 107. | Shri Mohan lal Ram lal | 60 | |
| 108. | „ Vishan Singh Jungar Singh | 311 | |
| 109. | „ Dovi Singh Panney Singh | 171 | |
| 110. | „ Kanhiya Lal Nen Sukh | 317 | |
| 111. | „ Bhanwar Lal Sukh Ram | 273 | |
| 112. | „ Lal Chand Mool Chand | 31 | |
| 113. | „ Haringa Mool Lohtt | 47 | |
| 114. | „ Bhakata Ram Veena Ram | 226 | |
| 115. | „ Kishan Dass Shivkaran | 88 | |
| 116. | „ Kashaiya Lal Sangi Dass | 255 | |
| 117. | „ Amba Lal Roop Ram | 110 | |
| 118. | „ Abdul Rashid Karim Bux | 294 | |
| 119. | „ Ghot Mal Sangi Dass | 58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 120. | Shri Champa Lal Jeth Mal | 247 | |
| 121. | „ Jai Narain Mohan Lal | 80 | |
| 122. | „ Mukhe Ram Chaturvedi | 251 | |
| 123. | „ Pancha Ram Jaswanta | 227 | |
| 124. | „ Kishori Lal Govind Ram | 335 | |
| 125. | „ Fathu Khan Immam Khan | 234 | |
| 126. | „ Kishori Lal Raghunath Das | 57 | |
| 127. | „ Chot Mal Narain | 134 | |
| 128. | „ Dul chand Thakurdas | 235-236 | |
| 129 | „ Prahlad s/o Lumba | 29२ | |
| 130. | „ Umara Chand Gul Raj | 241 | |
| 131. | „ Ram Dan Beniaji | 230 | |
| 132. | „ Fateh Lal Newala Ram | 89 | |
| 133. | „ Gangavishan Roop Chand | 116 | |
| 134. | „ Abdul Sukhan Baradsan | 87 | |
| 135. | „ Radhakrishan Hari Ramji | 244 | |
| 136. | Smt. Lakanwar w/o Kewal Chand | 73 | |
| 137. | Shri Rajakh Hasan Khan | 336 | |
| 138. | „ Damodar Liladhar | 321 | |
| 139. | „ Hanuman Sadharam Mochi | 173 | |
| 140. | „ Onkar Dass Gopi Lal | 289 | |
| 141. | „ Prabhu Lal Asaram | 53 | |
| 142. | „ Seshmal Bhimraj | 293 | |
| 143. | „ Amirkhan Mehtukhan | 334 | |
| 144. | „ Champalal Gordhandas | 79 | |

# Page No.146



| 1 | 3 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 145. | Shri Menghraj Baktawarmal | 135 | |
| 146. | „ Jethmal Bhimraj | 266 | |
| 147. | „ Shiv Chand Haranath Purohit | 286 | |
| 148. | „ Bhorilal Manaklal | 248 | |
| 149. | „ Gangshilal Sorajkaran | 109 | |
| 150. | „ Jaikishan Bakshiram | 312 | |
| 151. | „ Bhawaribai Purshotamdas | 196 | |
| 152. | „ Narain Das Chuni Lal | 117 | |
| 153. | „ Babulal Punam Chand | 123 | |
| 154. | „ Daulal Loonkaran | 280 | |
| 155. | „ Valbhadas Jasraj | 111 | |
| 156. | „ Prem Raj Shiv Karan | 120 | |
| 157. | „ Chand Mal Nan Mal | 287 | |
| 158. | „ Manna Ram Kumbha Ram | 299 | |
| 159. | „ Babu Lal Shivnath | 112 | |
| 160. | „ Mansi Lal Damodardas | 133 | |
| 161. | „ Mehrukhan Alarakh Khan | 187 | |
| 162. | „ Jhumar Lal Jaishankar | 239 | |
| 163. | „ Mool Chand Sampat Ram | 333 | |
| 164. | „ Dalpat Singh Jaswant Singh | 178 | |
| 165. | „ Man Mal Ram Lal | 390 | |
| 166. | „ Shiv Raj Suraj Mal | 183 | |
| 167. | Smt. Jadibai w/o Shyam Sundar | 339 | |
| 168. | Shri Hari Ram Rawat Mal | 136 | |
| 169. | „ Bhim Raj Kanji | 61 | |
| 170. | „ Ramsukh Narsinghdas | 63 | |

# Page No.147



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 171. | Shri Rahimbux Hamidkhan | 326 | |
| 172. | „ Mohan Lal Murlidhar | 85 | |
| 173. | „ Hem Raj Dekan Dass | 323 | |
| 174. | „ Subhmahmad Isimal Khan | 224 | |
| 175. | „ Amrit Lal Aidan | 140 | |
| 176. | „ Sher Mahamad Kadarkhan | 52 | |
| 177. | „ Mool Singh Karan Singh | 54 | |
| 178. | „ Sultan Dhorji | 335 | |
| 179. | „ Kanee Ram Doongardas | 190 | |
| 180. | „ Kasamdeen Alikhan | 179 | |
| 181. | „ Amba Lal Moolji | 59 | |
| 182. | „ Mool Raj Sidh Raj | 44 | |
| 183. | „ Gada Modji | 185 | |
| 184. | „ Parashram Ambalala | 56 | |
| 185. | „ Kishan Rawatji | 127 | |
| 186. | „ Sukha Ram Loomba | 132 | |
| 187. | „ Paras Mal Anop Chand | 187 | |
| 188. | „ Bhanwari Lal Jasraj | 182 | |
| 189. | „ Misri Lal Himat Ram | 45 | |
| 190. | „ Kawarekhan Mehtabkhan | 240 | |
| 191. | „ Harnarain Devidas | 291 | |
| 192. | „ Kishan Lal Suce Lal | 84 | |
| 193. | „ Neejamudeen Noorkhanji | 125 | |
| 194. | „ Chain Ram Seeta Ram | 232 | |
| 195. | „ Vallabh Dass Thakurdas | 228 | |

## LIST OF PERSONS OTHER BACKWARD CLASSES TO WHOM PLOTS WERE ALLOTTED

1. Shri Kishan s/o Poonam Chand Nai.
2. Amar Chand s/o Alsi Dan Bhat.
3. Achala Ram s/o Pabu Dan Disantri ( Dakot. )
4. Abdul Salem s/o Dadruuddin Teli.
5. Bhomraj s/o Khanu Nagarchi.
6. Mool Singh s/o Karan Singh Raona Rajput.
7. Ghanda s/o Modi, Raona Rajput.
8. Pooran Dass s/o Budha Ram Sad.

## SCHEDULED CASTES

1. Hanuman s/o Ladu Ram Mochi.
2. Amoalal s/o Moolji Mochi.
3. Sayab Ram s/o Durg Chand Mochi.
4. Monia s/o Nana Meghwal.

1. 22 Plots to the Jagirdars ( one each. )
2. 53 Plots to the Co-operative Societies.
3. 2 plots to Shri Hira Lal Dhadda.
4. 8 plots to khajanchi & Co.

———

## परिशिष्ट ६

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ का उत्तर देखिये )

पंचायत समिति सिवाना में पंचपद्रा में तकावी व सबसिडी के रूप में बांटी गई धनराशि की सूची:

| क्र० सं० | खण्ड का नाम | मद | तकावी के रूप में बांटी गई धनराशि १९५७-५८ | ५८-५९ | ५९-६० | ६०-६१ | सबसिडी के रूप में बांटी गई धनराशि १९५७-५८ | ५८-५९ | ५९-६० | ६०-६१ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १. | सिवाना | साधारण | — | ६,७५०.०० | — | — | — | — | — | — |
| | ,, | अकाल | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ,, | रहट से अधिक अन्न उत्पन्न करने की तकावी | ३२,०५०.०० | ६५,४५०.०० | २२,४००.०० | ६,३५०.०० | — | — | — | — |
| | ,, | कृषि विभाग से ट्रैक्टर लोन | — | — | ८,०००.०० | — | — | — | — | — |

--परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ,, | सामुदायिक विकास फण्डस् | ८०,२५०.०० | १२,५७६०.०० | ४८,०००.०० | १६,२५०.०० | — | — | — | — |
| ,, | ग्राम्य भवन | — | — | — | १३,५००.०० | — | — | — | — |
| ,, | पशु–पालन | — | — | — | — | — | — | ३,५००.०० | १,००० |
| ,, | भेड़ पालन | — | — | — | — | — | — | २,५००.०० | ७५० |
| २. पंचपद्रा | | — | — | ३५,००० | — | — | — | — | — |
| ,, | सामुदायिक विकास | — | — | ४८,६५० | ५४,३५० | — | — | — | — |
| ,, | सिंचाई लोन | — | — | १,७५० | ८,००० | — | — | — | — |
| ,, | कृषि लोन | — | — | — | ८,२०० | — | — | — | — |

परिशिष्ट

## वसूल की गई व बकाया धनराशि की सूची

| क्र० सं | खण्ड का नाम | मद | तकावी की रकम की वसूली | बकाया तकावी की रकम |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. | सिवाना | साधारण | २४,३५१.६६ | १,२२६.०० |
| | | अकाल | ३,३७६.०० | — |
| | | रहट से अधिक अन्न उत्पन्न करने की तकावी | ८१,६७६.२६ | ३,६२७.७५ |
| | | कृषि विभाग से ट्रैक्टर लोन | १३,५४७.०० | — |
| | | सामुदायिक विकास फन्ड्स | ६६,२५०.३८, | १,४३६.०० |
| २. | पचपद्रा | — | २,२११.६६ | २,५२३.३४ |

नोटः—तकावी के रूप में जो रकम दी गई है उसकी वसूली ज्यों ज्यों वाजिब होती है किश्तों में की जाती है।
वसूल की गई रकम में पहले के ऋण की रकम भी शामिल है।

## शुद्धि-पत्र

( मंगलवार ६ सितम्बर, १९६० )

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २१८१ | २ | with experienee | With an experience. |
| २२०१ | १६–१७ | अब नहीं की गई, तक इसके | अब तक नहीं की गई, इसके |
| २२०६ | १७ | उसके ? अनुसार | उसके अनुसार |
| ,, | २३ | बॉड फीगर्स | ब्रॉड फीगर्स |
| २२०७ | ५ | I is a | It is a |
| ,, | ८ | unstared; becarrse | unstarred; because |
| २२०९ | ८ | रिफ्यूजी की | रिफ्यूजीज़ की |
| २२१२ | ५ | Diety of | Deity of |
| २२२९ | शीर्षक | १२२९ | २२२९ |
| ,, | १६ | कुलकितने | कुल कितने |
| २२३१ | १३ | loans Act | Loans Act |
| ,, | १४ | Parliamint) | Parliament |
| २२३२ | अन्तिम से ३ | जाय कानून ...जाय ? | जाय ? कानून....जाय |
| २२३४ | ८ | pillarbridge) | pillar bridge) |
| २२३५ | १७ | राजस्व मत्रा | राजस्व मंत्री |
| २२३६ | ५ | मालकाना फल | मालकाना फलों |
| २२४१ | २० | करोड़ को राजस्थान | करोड़ राजस्थान |
| २२४५ | १४ | हैल्थसेन्टर्स खोले | हैल्थ सैंटर्स १४६ खोले |
| २२५८ | अन्तिम से २ | एडीशन योजना | एडीशनल योजना |
| २२६० | ३ | लड़कियां की | लड़कियों की |
| २२६१ | १३ | इरेडिकेट किया | इरेडिकेट किया |
| २२६९ | १४ | आवश्वक होता | आवश्यक होता |
| २२७० | अन्तिम से ६ | सुलाड़ियां | सुखाड़िया |
| २२७६ | १८ | उस गांवों | उन गांवों |
| २२८१ | १० | लागता है | लगता है |
| २२८२ | अन्तिम से २ | का । मैं | का मैं |
| २२८५ | १३ | इन्डस्ट्रीड़ खोलने | इन्डस्ट्रीज़ खोलने |
| २२९४ | २७ | सब्सीडीरी कहते | सब्सीडियरी कहते |
| २२९८ | १४ | खरीदी गई | खरीदी गईं |
| ,, | अन्तिम से ३ | क्रोट किया | क्वोट किया |

# Page No.153



| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २३०१ | अन्तिम से६ | पर इकट्ठे_____ | पर इकट्ठे _ |
| २३१० | १७ | पिछले और पहली | पिछली और पहली |
| २३१५ | अन्तिम से७ | मुख्य मत्री | मुख्य मंत्री |
| २३२३ | १ | राजस्डान | राजस्थान |
| २३२५ | ४ | मुर्फे इसकी | मुझे इसकी |
| २३३६ | १८ | अयूमन रोग | अमूमन रोग |
| २३४० | अन्तिम से३ | हाउसिंग; मं | हाउसिंग, मैं |
| २३४६ | ३ | कॉलेज पर | कॉलेज हो, पर |
| ,, | ६ | शिलोग तक | शिलोंग तक |
| ,, | १० | एलयूवियल | एल्यूवियल |
| २३६१ | १६ | मिल; कारखाने | मिलें, कारखाने |
| २३७८ | १६ | बाजी दफा | बाज दफा |
| २३८० | १० | उसके बदले | उनके बदले |
| २३८२ | १३ | कदर नहीं | कद्र नहीं |
| ,, | १७ | कर देंने | कर देंगे |
| ,, | अन्तिम से५ | उसको भी | उनको भी |
| २३८६ | ६ | विशेययथा तीन | विशेषतया तीन |
| २३८७ | १५ | इस तरफ से | इस तरह से |
| २३६२ | शीर्षक | पर विचर | पर विचार |
| २३६७ | शीर्ष | डॉ० बहादुरसिह | डॉ० बहादुरसिंह |
| ,, | ८ | होंगी क्योंकि | होंगे क्योंकि |
| ,, | १६ | शस्त्र क्रिया | शल्य क्रिया |
| २३६३ | अन्तिम से२ | परिचंर्यार्थ एक | परिचंर्या का सवाल है वह एक |
| २४०१ | २ | आयुर्वेद की | आयुर्वेद में की |
| २४०३-४ | २ | मंगवार | मंगलवार |
| २४०३ | १४ | प्रारूपा | प्रारूप |
| २४०५ | अन्तिम से३ | प्रस्तुतं किया | प्रस्तुत किया |
| २४०८ | २ | ४३७ का | ३४७ क |
| ,, | आइटम ८, कॉलम ३ | 13 th March to 15th March | 13th March to 15th March |
| २४१० | आइटम१६ कॉलम ३ | 3 I (1st oct. 60 Sturday) | 3—(Istoct., 60 Saturday) |
| २४१६ | अन्तिम से३ | Civic etc | Civics etc |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २४२० | अाइटम ५ कॉलम ३ | ,, | १९५५–५६ |
| ,, | आइटम ६ कॉलम ३ | ,, | १९५७–५८ |
| २४२१ | ६ | (unified of | (Unification of |
| ,, | ९ | Scalcs of | Scales of |
| ,, | १६ | be rules | the rules |
| २४२६ | आइटम ९ व १६ कॉलम ३ | बनौसिंह | बनेसिंह |
| ,, | आइटम १४ कॉलम ३ | बुक व चाय | ब्रुक बॉड चाय |
| २४२७ | पंक्ति ४ | सत्यापाल | सत्यपाल |
| ,, | पंक्ति १० | कक्कढ़ | कक्कड़ |
| ,, | पंक्ति ११ | बैंजानाथ | बैंजनाथ |
| २४३० | पंक्ति सं० १५ कॉलम सं.३ | श्री द्वारादास | श्री द्वारकादास |
| २४३१ | कॉलम सं. ३ की पंक्तिसं.११ | लोवर प्राईमारी स्कूल | लोअर प्राइमरी स्कूल |
| ,, | कॉलमसं.३में पंक्ति सं.१५ | श्री मंगवलाल कुभट | श्री मंगललाल कुंभट |
| २४३२ | पंक्ति ४ | रूपा नाही | रूपा नाई |
| ,, | कॉलम सं.२मे पंक्ति सं.८ | ८२–८२ | ८२–८३ |
| २४३३ | २२ | Pramraj | Premraj |
| ,, | अन्तिम से २ | Ram lal Redhakrishan | Ram lal Radhakrishan |
| २४३४ | ४ | Sura Jkaran | Suraj Karan |
| २४३५ | क्रमश: १०, ११,१२व१४ | Shrimati Tulshriam | Shri Tulsiriam |
| | | ,, Kasevdevi | Shrimati kesardevi |
| | | Shri Chandchand | Shri Chandu chand |
| | | Mishra lal | Mishrilal |
| २४३६ | ९ | Akaramar khan | Akaram khan |
| ,, | १२ | Abdul Havid | Abdul Hamid |
| २४३७ | ४ | Ganga Vishan | Ganga bishan |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २४३७ | १५ | Dovi Singh | Devi singh |
| ,, | १६ | Haringa Mool Lohtt | Haringa Mool Loatt |
| २४३८ | ३ | Mukhe Ram | Mukh Ram |
| ,, | ६ | Dul chand | Duli Chand |
| ,, | ११ | Umara Chand | Umarao chand |
| ,, | १७ व १८ | Smt. Lakanwar | smt. Lalkanwar |
| | क्रमश: | Rajakh Hasan | Raja khan |
| २४३६ | ५ | Sorajkaran | Soorajkaran |
| ,, | ६व७क्रमश: | ,, Bhanwari bai | Smt. Bhawaribai |
| | | ,, Narain Das | Shri Narain Das |
| २४४० | ४ | Asimal Khan | Ismail khan |
| ,, | १४ | Imbalala | Ambalal |
| २४४१ | ६ | Dadruddin Teli | Badruddin Teli |

## अनुपूरक शुद्धि-पत्र

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| २१६४ | २२ | २४६ श्री सतीशचन्द्र | २४६. श्री सतीशचन्द्र |
| २३३३ | शीर्ष | ( श्री जनार्दनराय नामर ) | ( श्री जनार्दनराय नागर ) |
| २३६६ | शीर्ष | ( श्री पुरुषोतमलाल मर्शा ) | ( श्री पुरुषोतमलाल सर्मा |
| २४२० | शीर्षक | परिशिप्ट ४ | परिशिष्ट ४ |
| शुद्धि-पत्र | पृष्ठ २, कॉलम ४ पंक्ति ३० | ३-( 1stoct., 60 | ३-( 1st Oct., 60 |
| ,, | पृष्ठ ३, कॉलम ४ पंक्ति २० | Kesardevi | Kesardevi |